राष्ट्रीय संस्करण

# दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 25

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, सोमवार, 5 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



शेख हसीना बोलीं, इस्लाम और सेक्युलरिज्म में कोई टकराव नहीं >>11

## जागरण विशेष

### गोबर से हुआ कमाल, किसान बन रहे आत्मनिर्भर



**लोहरदगा :** रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव को देखते हुए यहां के किसान जैविक खाद की ओर मुड़ रहे हैं। गोबर और केंचुआ से तैयार जैविक खाद से फसलों का उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। (पेज-10)

# सभी भारतीयों का डीएनए एक है : भागवत

## रखी बात ▶ पूजा के तरीके से हिंदू-मुस्लिम को अलग नहीं किया जा सकता

### पंथ भले अलग, लेकिन हम सब भारतीय एक हैं

सौरभ पांडेय, गाजियाबाद

हिंदू-मुस्लिम एक हैं और इसका आधार है हमारी मातृभूमि। पूजन विधि के आधार पर हमें अलग नहीं किया जा सकता। सभी भारतीयों का डीएनए एक है। अब समय आ चुका है कि भाषा, प्रांत और अन्य विषमताओं को छोड़कर हम एक हों और भारत को विश्व गुरु बनाएं। भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी दुनिया सुरक्षित रहेगी। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित एक इंस्टीट्यूट में अपने उद्बोधन के दौरान कहीं।

**संघ जोड़ता है :** मोहन भागवत डा. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की पुस्तक 'वैचारिक समन्वय-एक पहल' का विमोचन करने आए थे। डा. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के सलाहकार थे। विमोचन कार्यक्रम में सरसंघचालक ने कहा कि लोग यह न समझें कि इस पुस्तक का विमोचन वोट बैंक पालिटिक्स के लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। राजनीति स्वयंसेवकों का काम नहीं है। संघ जोड़ने का काम करता है, जबकि राजनीति तोड़ने का हथियार बन जाती है। राजनीति की वजह से ही हिंदू-मुस्लिम एक नहीं हो सके हैं। संघ चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन जो भी करता है राष्ट्र हित में करता है।

### यह भी बोले भागवत

- एक समय संघ छोटा था तो किसी ने आवाज नहीं सुनी। आज पूरा समाज सुनता है।
- रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम की भी उपासना की और अंत मे यही कहा कि रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है।
- यहां हिंदू गुरु के मुस्लिम शिष्य हैं और मुस्लिम गुरु के हिन्दू शिष्य। हिंदू गुरु मुस्लिम शिष्य को संस्कृत में गुरु मंत्र देता है।



गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित एक इंस्टीट्यूट में डा. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की पुस्तक का विमोचन करने के बाद लोगों को संबोधित करते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत। मनोज कुमार

### हिंदू-मुस्लिम एकता शब्द ही भ्रामक

भागवत ने कहा, पुस्तक को बिना देखे ही मैंने इसके विमोचन के लिए हां कर दिया था, क्योंकि इसमें प्रमाणिकता का आह्वान किया गया है। हिंदू-मुस्लिम एकता शब्द ही भ्रामक है। हिंदू-मुस्लिम अलग हैं ही नहीं, हमेशा से एक हैं। जब लोग दोनों को अलग मानते हैं तभी संकट खड़ा होता है। हमारी श्रद्धा आकार और निराकार दोनों में समान है। हम मातृभूमि से प्रेम करते हैं क्योंकि यह यहां रहने वाले हर एक व्यक्ति को पालती आई है और पाल रही है। जनसंख्या के लिहाज से भविष्य में खतरा है, उसे ठीक करना पड़ेगा। कुछ लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, हम कहते हैं, हम सब एक हैं। हम हिंदू कहते हैं आप भारतीय कहते हो। शब्दों की लड़ाई में नहीं पड़ना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है।

### बहुसंख्यक ही उठाते हैं आवाज

संघ प्रमुख ने कहा अल्पसंख्यकों के मन में यह बिठाया गया है कि हिंदू उनको खा जाएंगे। लेकिन जब किसी अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक अत्याचार करता है तो इसके खिलाफ आवाज भी बहुसंख्यक ही उठाता है। आग लगाने वाला भाषण देने से प्रसिद्ध तो हो सकता है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा।

### यह रहे उपस्थित

डा. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने कहा कि यह कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक है। अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज आंखों से पट्टी हटाए और सबको गले लगाए। कट्टरता को छोड़कर आपसी भाईचारे की राह अपनाए। उन्होंने इस पहल के लिए कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, सह सरकार्यवाह डा. कृष्ण गोपाल, संपर्क प्रमुख रामलाल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार को धन्यवाद दिया।

### माब लिंचिंग करने वाले आततायी

मोहन भागवत ने कहा, गाय हमारे लिए पूजनीय है, इसीलिए उसे हिंदू ने मां का दर्जा दिया है, लेकिन जो माब लिंचिंग करते हैं, वे आततायी हैं। हिंदुत्व के खिलाफ हैं। उन्हें किसी भी तरीके से राष्ट्रवादी नहीं कहा जा सकता। मैं और पूरा देश उन्हें अपराधी मानता है। कानून को उनके साथ निपटना चाहिए। कानून उसकी जांच करे और दोषी को सजा दे। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। हालांकि इन मामलों में क्या सही है, क्या गलत उसका पता जांच के बाद ही चलता है।

### जनसंख्या नियंत्रण पर राजी हुए असम के मुस्लिम बुद्धिजीवी : सरमा

**गुवाहाटी :** असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने रविवार को 150 से अधिक मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। सरमा ने बाद में पत्रकारों से कहा, 'मैंने आज 150 से ज्यादा बुद्धिजीवियों, लेखकों, इतिहासकारों, प्रोफेसरों और अन्य से मुलाकात की। हमने ऐसे विभिन्न मसलों पर विचार किया जिनका असम के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सामना कर रहे हैं। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि असम के कुछ भागों में 1जनसंख्या विस्फोट राज्य के विकास के लिए खतरा है। असम को अगर देश के पांच शीर्ष राज्यों में शुमार होना है तो हमें अपने जनसंख्या विस्फोट से निपटना होगा। इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की।' (पेज-3)

डा. अहमद बोले, मोदी सबसे बेहतर निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री पेज>>3

### अफगानिस्तान में पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा भारत

**नई दिल्ली :** भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से भले ही तालिबान से किसी तरह की बातचीत से इन्कार किया हो, लेकिन इतना तय है कि वह फिर से ऐसी गलती नहीं करेगा, जिसमें संपर्कहीनता और संवादहीनता रहे। दरअसल, पिछली सदी के आखिरी दशक में तालिबान के साथ संपर्क नहीं होना भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। कंधार विमान अपहरण कांड के दौरान काबुल में भारत का पक्ष सुनने वाला कोई नहीं था। तालिबान सरकार आइएसआइ के इशारे पर काम कर रही थी और मजबूरी में भारत को अजहर मसूद समेत तीन आतंकी रिहा करने पड़े था। मसूद ने ही आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद की स्थापना की थी। (पेज-3)

### उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक

**लखनऊ :** उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को स्थिति गंभीर होने के बाद शनिवार शाम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) में भर्ती करा दिया गया। पांच विभागाध्यक्षों की निगरानी में उन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन (सीसीएम) में रखा गया है। एसजीपीजीआइ शिफ्ट कराए जाने से पहले सुबह से शाम तक लखनऊ स्थित लोहिया संस्थान जाकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका हालचाल जाना। (पेज-5)

## न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय राजधानी ▶ पृष्ठ 2

### राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने रोकी यमुना में पर्यटन की राह

**नई दिल्ली :** दिल्ली में यमुना नदी सरकारी अनदेखी और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण बेहाल है। इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। इसकी साफ-सफाई की योजनाएं बनीं, चुनावी दौर में घोषणाएं भी होती रहीं, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ नहीं हो पाया।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

### कश्मीर में नई चुनौती बन रहे हाइब्रिड आतंकवादी

**जम्मू :** कश्मीर में सुरक्षाबलों के बढ़ते दबाव से हताश दहशतगर्दों के आकाओं ने नई साजिश रची है। अब वे हमलों के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल, ये आतंकी गुमराह किए गए वे युवा होते हैं, जो न तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सूची में शामिल हैं और न ही इनकी किसी को भनक होती है।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 6

### आठ जुलाई से फिर सक्रिय होगा उत्तर भारत में मानसून

**नई दिल्ली :** आठ जुलाई से दक्षिण पश्चिम मानसून फिर सक्रिय दिखेगा। पूर्वानुमान माडल से बंगाल की खाड़ी में मौसम में ऐसे बदलाव के संकेत मिले हैं जो ज्यादा बारिश के कारक है। इसके चलते उत्तर भारत में आठ जुलाई से ज्यादा बारिश होने की संभावना है।

## भविष्य में भी सेमेस्टर और प्री-बोर्ड आधारित मूल्यांकन की तैयारी

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

- ▶ 2022 के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई के साथ मिलकर तेज की कवायद
- ▶ छात्रों को सेमेस्टर और प्री-बोर्ड परीक्षाओं को गंभीरता से लेना होगा

10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को अब सेमेस्टर और प्री-बोर्ड परीक्षाओं को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यह इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना का खतरा जिस तरह बना हुआ है, उसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि परीक्षाएं हो पाएं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के साथ मिलकर इससे जुड़े विकल्प पर काम शुरू कर दिया है। इसमें छात्रों की सेमेस्टर और प्री-बोर्ड परीक्षाएं अब बोर्ड की देखरेख में होंगी। स्कूलों को ये परीक्षाएं कराने के बाद तुरंत इसके अंकों को बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बोर्ड परीक्षाएं नहीं होने की स्थिति में इन्हीं अंकों के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

कोरोना के कारण पिछले डेढ़ वर्षों में छात्रों का बड़ा नुकसान हुआ है। बोर्ड के साथ-साथ दूसरी परीक्षाएं भी स्थगित हुईं। रिजल्ट से लेकर एडमिशन तक में काफी विलंब हुआ। केंद्र सरकार चाहती है कि अगर जरूरत हो तो भविष्य को लेकर अभी से तैयारी रहे ताकि छात्रों की पढ़ाई और करियर में अब देर न हो।

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो नए पैटर्न के संबंध में जल्द ही सभी सीबीएसई स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। वैसे भी 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की अभी कोई सेमेस्टर परीक्षा नहीं हुई है जो जुलाई अंत या फिर अगस्त में हो सकती है। यह परीक्षा आनलाइन ही हो रही है।

जेईई मेन और नीट की मुश्किलें भी होंगी आसान पेज>>3

## राहुल चाहें तो अगला चुनाव भी राफेल के मुद्दे पर लड़ लें

जेएनएन, नई दिल्ली

- फ्रांस से करार की जेपीसी जांच की मांग कर रहे कांग्रेस नेता को भाजपा ने दी चुनौती
- पूछा, गांधी परिवार को वांछित कमीशन नहीं मिला, इसलिए 10 साल के अपने शासन में कांग्रेस नहीं कर पाई सौदा



कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय। जागरण आर्काइव

### राहुल का आनलाइन सर्वे

राफेल मुद्दे को गरमाने में जुटे राहुल गांधी ने ट्विटर पर इसको लेकर आनलाइन सर्वे भी शुरू किया है। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार जेपीसी जांच क्यों नहीं करा रही है। साथ ही इसके चार विकल्प दिए हैं। इसमें अपराधबोध, मित्रों को बचाना, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए और ये सभी सही हैं, शामिल हैं।

राफेल मामले पर कांग्रेस-भाजपा के बीच सियासी तकरार तेज होती जा रही है। फ्रांस में इस सौदे में भ्रष्टाचार व पक्षपात के मामले में जांच शुरू हुई है तो कांग्रेस यहां भी जेसीपी की मांग करने लगी है और राहुल गांधी ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने पलटवार करते हुए राहुल को राफेल के मुद्दे पर ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। साथ ही सवाल किया कि कांग्रेस अपने 10 साल के शासनकाल में क्या इसलिए राफेल सौदा नहीं कर पाई क्योंकि गांधी परिवार को वांछित कमीशन नहीं मिला।

बिना किसी का नाम लिए राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया जिसमें राफेल से निकलती हवा से सफेद दाढ़ी को जोड़ा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त 'चौकीदार चोर है' जैसा नारा गढ़ने वाले राहुल गांधी ने अब 'चोर की दाढ़ी' से तंज किया है।

राहुल गांधी के इस पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, पहले हर तरह की गाली देने वाले राहुल अब निचले स्तर पर उतर आए हैं। कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव में सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सीएजी के साथ-साथ देश की जनता ने उनके झूठ को नकार दिया। मालवीय ने राहुल को चुनौती दी है कि वह चाहें तो 2024 का चुनाव भी राफेल के मुद्दे पर ही लड़ कर देख लें।

कांग्रेस के फ्रांस में जांच पर सरकार की चुप्पी के सवाल पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने 10 साल के अपने शासनकाल में जब भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता में कमी आ रही थी, तब उसने राफेल सौदा क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि गांधी परिवार को उसका वांछित कमीशन नहीं मिला?

पात्रा ने कहा, जब कांग्रेस पार्टी दूसरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाती है तो यह ठीक नहीं लगता है। कांग्रेस को पहले यह जवाब देना चाहिए कि उसके नेतृत्व वाली सरकार ने 10 साल में यह सौदा क्यों नहीं किया था।

इससे पहले, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल किया कि दो सरकारों के बीच सौदे में जब लाभार्थी सरकार ने किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं तब वह देश ऐसा आदेश क्यों नहीं दे रहा जिसके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा की बहुत बातें करते हैं, लेकिन उद्यमी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हैं।

## राजधानी में स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की मिली अनुमति

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

कोरोना के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्टेडियम और खेल परिसर (स्पोर्ट्स कांप्लेक्स ) को सोमवार से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अभी दर्शकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से रविवार को जारी आदेश जारी में कहा गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अन्य दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। फिलहाल, ये अनुमति पांच जुलाई से 12 जुलाई की सुबह पांच बजे तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसके अलावा अन्य मामलों में पिछले हफ्ते तक लागू छूट और प्रतिबंध जारी रहेंगे।

### ये गतिविधियां अभी बंद रहेंगी

- राजधानी में स्कूल, कालेज और सभी शिक्षण संस्थान अभी रहेंगे बंद
- सामाजिक, राजनीतिक, अकादमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं होगी
- सिनेमा,थिएटर,मल्टीप्लेक्स और स्वीमिंग पूल भी नहीं खुलेंगे
- मनोरंजन और वाटर पार्क बंद रहेंगे
- सभागार का भी नहीं खुलेता ताला
- बिजनेस टु बिजनेस एग्जीबिशन और स्पा बंद रहेंगे

डीडीएमए ने गत सप्ताह बैंक्वेट हाल और होटल में शादी की अनुमति के साथ ही जिम व योग संस्थान को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई थी।

## शिवसेना के साथ भाजपा की कोई शत्रुता नहीं, सिर्फ वैचारिक मतभेद : फड़नवीस

राज्य ब्यूरो, मुंबई



देवेंद्र फड़नवीस

कहा, कोई भी निर्णय हालात के मुताबिक होगा, सरकार पर लगाया विपक्ष के सवालों से भागने का आरोप

इन दिनों महाराष्ट्र की विभिन्न पार्टियों के बीच चल रही गुप्त मुलाकातों एवं आरोप-प्रत्यारोप के बीच नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने यह कहकर अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया है कि शिवसेना के साथ भाजपा की कोई शत्रुता नहीं, सिर्फ वैचारिक मतभेद है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी निर्णय परिस्थिति के अनुसार ही किया जाएगा।

महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए फड़नवीस ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत एवं भाजपा विधायक आशीष शेलार की कथित गुप्त मुलाकात पर कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। फिर भी दो पार्टियों के नेताओं के बीच कोई मुलाकात होती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। शिवसेना हमारा पुराना मित्र दल रहा है। महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना के साथ ही शिवसेना के साथ हमारे वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। किंतु उससे हमारी कोई शत्रुता नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि जिनके साथ शिवसेना के वैचारिक मतभेद थे, ऐसे दलों को साथ लेकर उसने सरकार बनाई। राजनीति में अगर-मगर के सवालों का कोई अर्थ नहीं होता। समय आने पर परिस्थिति अनुसार निर्णय किया जाता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने शिवसेना-भाजपा गठबंधन की संभावना से इन्कार नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना सहित किसी भी दल से भाजपा की कोई आधिकारिक वार्ता नहीं चल रही है। भाजपा एक सक्षम विरोधी दल के रूप में काम कर रही है।

विभिन्न दलों के नेताओं के बीच चल रहा है मुलाकातों का दौर पेज>>4

## पुष्कर धामी बने उत्तराखंड के 11वें सीएम, मंत्रिमंडल समेत ली शपथ

### ताजपोशी

- मंत्रिमंडल में सभी पुराने चेहरे, तीन राज्यमंत्रियों का कद बढ़ाया
- धन सिंह रावत, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद बने कैबिनेट मंत्री



देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी (दाएं) को रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। जागरण

युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं। उनकी समस्याओं की जानकारी है। नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उन्हें साथ लेकर चला जाएगा। सरकार के रूप में नहीं, बल्कि जनता के साझीदार के रूप में काम करूंगा। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड।

राज्य ब्यूरो, देहरादून

पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। रविवार को राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी 11 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर मंत्रिमंडल में पिछली तीरथ सरकार के सभी मंत्रियों को जगह मिली। तीन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों डा. धन सिंह रावत, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद का कद बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण करने वाले अन्य मंत्रियों में सतपाल महाराज, डा. हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडेय, गणेश जोशी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी।

भाजपा विधायक दल की शनिवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में खटीमा से दूसरी बार के विधायक धामी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर मुहर लग गई थी। युवा चेहरे को मुख्यमंत्री पद पर तरजीह देने के पार्टी के फैसले से कुछ वरिष्ठ विधायक खफा हो गए थे। उनके शपथ ग्रहण से कन्नी काटने की चर्चा रही। रविवार दिनभर शपथ ग्रहण से पहले वरिष्ठों के मान-मनुहार का सिलसिला चला। धामी ने नाराज बताए जा रहे सतपाल महाराज से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। नाराजगी दूर होने के बाद मुख्यमंत्री के साथ ही सभी वरिष्ठ विधायक राजभवन पहुंचे।

राजभवन में सवा पांच बजे शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह करीब 20 मिनट चला। संचालन मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने किया। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व तीरथ सिंह रावत, विस अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट, अजय टम्टा व नरेश बंसल, कांग्रेस विधायक राजकुमार, भाजपा के कई विधायक एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

### ये हैं अन्य कैबिनेट मंत्री

सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, डा हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडेय, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी।

पुरानी नाव में सवार होकर नए खेवनहार बने पुष्कर धामी पेज>>4

## एकजुटता का दिया संकेत

पार्टी के सभी विधायक भगवा उत्तरीय में विधानसभा में पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा- गेरुआ रंग देश और स्वामी विवेकानंद का प्रतीक

## भाजपा की अनोखी पहल से बंगाल विस में छाया भगवा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता



बंगाल विधानसभा में सफेद कुर्ता-पायजामा, गले में गेरुआ उत्तरीय (अंग वस्त्र) और माथे पर केसरिया तिलक लगाकर मीडिया से बातचीत करते नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी। साथ में भाजपा के अन्य विधायक। जागरण

बंगाल की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र भगवा रंग में रंगा नजर आया। पिछले विधानसभा चुनाव में महज तीन सीटें जीतने वाली भगवा ब्रिगेड (भाजपा) ने इस बार के चुनाव में 75 सीटों पर विजयश्री हासिल कर विस में अपनी अलग ही अंदाज में उपस्थिति दर्ज कराई। भाजपा के लगभग सभी विधायक सफेद कुर्ता-पायजामा, गले में गेरुआ रंग का उत्तरीय (अंग वस्त्र) और माथे पर केसरिया रंग का तिलक लगाकर पहुंचे। महिला विधायकों के माथे पर भी गेरुआ तिलक था। एक जैसी पोशाक के जरिये पार्टी ने एकजुटता का संदेश भी दिया।

हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए मुकुल रॉय को छोड़कर भाजपा के 74 विधायक हैं। पहले दिन इनमें से 70 विधानसभा में मौजूद रहे। मुख्य विपक्षी दल के सभी विधायकों को एक जैसे कपड़े पहने देखकर नंदीग्राम से भाजपा विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से मीडिया ने सवाल किए। जवाब में उन्होंने कहा कि गेरुआ रंग देश और स्वामी विवेकानंद का प्रतीक है। हमें इसके धारण करने पर फक्र होना चाहिए।

गौरतलब है कि 1952 से वामपंथी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जनता पार्टी और जनसंघ के नेता बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के विधायकों को इस तरह एक ही तरह के कपड़ों में नहीं देखा गया। लेकिन, इस बार राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने एक ही पोशाक में विधानसभा के सत्र में भाग लिया, जोकि अभूतपूर्व था। भाजपा के एक विधायक से इस बारे में पूछने पर कहा कि सुवेंदु दा के निर्देश पर पार्टी के सभी विधायक भगवा रंग में रंगे नजर आए। सियासी विश्लेषकों ने कहा कि विधानसभा में एक तरह के पहनावे के जरिये भाजपा अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहती है।

### छत्तीसगढ़ में फिर बजा 27 फीसद ओबीसी आरक्षण का झुनझुना

**रायपुर :** छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होते ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का सियासी झुनझुना फिर से बजने लगा है। सरकार ने जातिगत आरक्षण तय करने की कवायद शुरू की है। इसके लिए जिला और नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। (पेज-4)

### वैक्सीन की तेज होगी जांच, दो और सेंट्रल ड्रग लैब स्थापित

**नई दिल्ली :** देश में इस साल के अंत तक सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य है, इसके लिए भारी मात्रा में वैक्सीन की जरूरत है। इसे पूरा करने के लिए सरकार युद्धस्तर पर वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने में जुटी हुई है। टीके की गुणवत्ता जांच और उसे बाजार में जारी करने की मंजूरी देने के लिए दो और सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी की स्थापना की गई है। (पेज-6)

40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तथा 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सोमवार को रहने का अनुमान है। सप्ताहांत तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश की भी संभावना बनी हुई है। लिहाजा लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 5 जुलाई, 2021

# राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने रोकी यमुना में पर्यटन की राह

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

▸ डीडीए ने समय-समय पर योजनाएं भी बनाईं, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाईं

▸ वोट बैंक के चलते नहीं लग सकी बाढ़ क्षेत्र में अवैध कालोनियां बसाने पर भी रोक

दिल्ली से गुजरने वाली इकलौती नदी यमुना का पुराणों में ही नहीं, दिल्ली के इतिहास में भी खासा महत्व है। बावजूद इसके यमुना का सर्वाधिक प्रदूषित हिस्सा भी राजधानी में ही पड़ता है। यह भी सीधे तौर पर सरकारी अनदेखी या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का ही परिणाम है कि इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। इसकी साफ-सफाई को लेकर योजनाएं तो बनती रहीं, चुनावी दौर में घोषणाएं भी होती रहीं, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ नहीं हो पाया।

दरअसल, यमुना खादर में 1976 से अनधिकृत कालोनियां बसने का शुरू हुआ सिलसिला आज 100 गांव-कालोनियों तक जा पहुंचा है। इनमें रहने वालों की संख्या भी चार लाख के लगभग हो गई है। यमुना खादर का क्षेत्र करीब 9700 हेक्टेयर का है, जिसमें से 3600 पर अनधिकृत कालोनियां बस चुकी हैं। यही वोट बैंक राजनीतिक स्तर पर यमुना के पुनरुद्धार में हमेशा के लिए रुकावट बनता गया।

हालांकि यमुना की बदहाली को लेकर 1978 से लेकर 1983 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), बाढ़ एवं सिंचाई और दिल्ली जल बोर्ड की टीमों ने अनेक सर्वे किए, कई रिपोर्ट भी बनाईं। पुणे में इन रिपोर्टों के आधार पर जीर्णोद्धार की माडलिंग भी की गई। सभी रिपोर्ट केंद्र सरकार और प्रशासन के सभी स्तरों पर भेजी गईं। इनमें एक अहम सुझाव यमुना में गिरने वाले नालों पर कंक्रीट की सीमेंटेड प्लेट लगाने का था, लेकिन काम शुरू ही नहीं हो पाया। समय बीतने के साथ साथ संबंधित अधिकारी रिटायर होते गए और सरकारें भी बदलती गईं।

इसके बाद शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल में यमुना के आसपास बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने और नालों के दूषित जल को शोधित करने के लिए जगह-जगह कामन इफ्लूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) लगाने की योजना बनाई गई। 2010 में यमुना का जोनल प्लान भी बन गया। इन पर काम भी शुरू हुआ और हजारों करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार के दिल्ली की सत्ता से हटते ही यह सब भी अटक गया।

केंद्र सरकार की पहल पर पहली बार भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण ने 2019 में यमुना को इस तरह से विकसित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे पर्यटन को स्थायी रूप से बढ़ावा मिल सके। इसके तहत यमुना के करीब 16 किमी. के क्षेत्र को कवर करते हुए वाटर टैक्सी चलाने का प्लान बनाया गया। प्लान था कि यह प्रोजेक्ट यमुना किनारे स्थित पांच मुख्य जगहों को कवर करेगा। इनमें फतेहपुर जाट, ट्रानिका सिटी, जगतपुर, वजीराबाद और सोनिया विहार शामिल हैं।

प्रोजेक्ट के दो फेज में लागू होने की बात थी। पहले फेज में यह सोनिया विहार, ट्रानिका सिटी को कनेक्ट करेगा। दूसरे फेज में इन दोनों जगहों को वजीराबाद, फतेहपुर जाट और जगतपुर से कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन, यह योजना भी हवा- हवाई ही साबित हुई।

डीडीए भी यमुना के किनारों का सुंदरीकरण करने की योजना पर कई साल से काम कर रहा है। इसके तहत घाटों को पक्का करने, फूल वाले पौधे, बैठने के लिए बेंच लगाने और आगे चलकर वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करने की सोच रखी गई है। उपराज्यपाल स्वयं समय-समय पर समीक्षा बैठक लेते रहते हैं, लेकिन धरातल पर यहां भी कुछ नहीं है। इस दौरान डीडीए के दो उपाध्यक्ष भी बदल चुके हैं।



बजीराबाद में यमुना को देखकर ऐसा लगता है कि अगर इमानदार प्रयास किया जाये तो यहां पर पर्यटक स्थल बन सकता है। संजय

यमुना को पर्यटक स्थल से बनाने से पहले इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। जबकि न तो प्रशासनिक और ही राजनीतिक स्तर पर इसे लेकर गंभीरता है। कभी बहु निकाय व्यवस्था बाधक बन जाती है, कभी दिल्ली और केंद्र सरकार की आपसी खींचतान और कभी अन्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय का अभाव।
-आर जी गुप्ता, टाउन प्लानर, दिल्ली

मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट में तो रिवर (ओ) जोन को ही दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रख दिया गया है। बफर जोन होगा जहां हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जबकि इसके आगे के क्षेत्र में बसी अनधिकृत कालोनियों को कुछ शर्तों के साथ नियमित करने की योजना बनाई जा रही है। वोट बैंक की ज्यादा चिंता है।
-ए के जैन, पूर्व योजना आयुक्त, डीडीए

### दिल्ली सरकार ने यमुना के लिए बनाया नौ सूत्रीय एक्शन प्लान

यमुना को झाग और गंदे सीवर के पानी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2020 में नौ सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया। हरियाणा व उप्र तक को अपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड करने को कहा गया। इस प्लान के तहत यूपी सिंचाई विभाग को ओखला बैराज से सभी जलकुंभियां हटाने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया। लेकिन, कोरोना के कारण लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जल बोर्ड को सभी अनधिकृत कालोनियों और स्लम में 31 दिसंबर तक सीवरेज सिस्टम कनेक्ट करने को कहा गया है। कोरोनेशन पिलर और ओखला में बन रहे नए एसटीपी प्लांट को 30 जून 2021 और 31 दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा।

## छात्रों से वसूला गया परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : 12वीं व 10वीं की परीक्षा रद होने के कारण परीक्षा शुल्क वापस करने का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) व केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में कहा कि कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई द्वारा परीक्षा रद कर दी गई है, ऐसे में परीक्षा शुल्क के नाम पर छात्रों से वसूले गए रुपये वापस किए जाएं।

अधिवक्ता व याचिकाकर्ता दीपा जोसेफ समेत एक छात्र की मां अधिवक्ता राबिन राजू के माध्यम से दायर याचिका में दलील दी कि ऐसे में जब परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया गया तो फिर परीक्षा शुल्क के रूप में एकत्र किए गए पैसे को रखना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुल्क के रूप में ली गई को कापी, परीक्षक, निरीक्षक, परीक्षा केंद्र सहित अन्य पर खर्च होना था। लेकिन, परीक्षा रद होने के कारण इन मदों में कोई खर्च नहीं किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि परीक्षा शुल्क के रूप में सीबीएसई को करोड़ों रुपये प्राप्त हुए हैं।

## न्यूज गैलरी

### हाई कोर्ट में आज से बैठेंगी सभी अदालतें

नई दिल्ली : गर्मियों के अवकाश के बाद सोमवार से हाई कोर्ट की सभी अदालतें फिर शुरू होने जा रही हैं। बीते एक महीने से दिल्ली हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश था और कुछ अदालतें ही मुख्य मामलों की सुनवाई कर रही थीं। पांच जुलाई से सभी अदालतें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगी। हालांकि, फिलहाल महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई होगी। वहीं, निचली अदालतों में भी इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई होगी। इसमें पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड को लेकर ओलंपियन सुशील कुमार के मामले में रोहिणी कोर्ट में सुनवाई होगी। (जासं)

### मनमाना शुल्क लेने वाले अस्पतालों की जांच शुरू

नई दिल्ली: राजधानी में कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों से मनमाना शुल्क वसूल करने वाले अस्पतालों की जांच शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में गठित की गई समितियों के पास अब तक 76 से अधिक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। इनकी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा (दिल्ली) की महानिदेशक डा. नूतन मुंडेजा ने 15 जून को एक आदेश जारी किया था। अब तक जो 76 शिकायतें मिली हैं, उनमें सबसे ज्यादा 18 शिकायतें उत्तर-पश्चिमी जिले के अस्पतालों की हैं। इसके बाद दक्षिण-पूर्वी जिले से 11 और दक्षिण जिले से 10 शिकायतें आई हैं। 76 में से केवल आठ शिकायतों का ही अब तक निस्तारण किया जा सका है। (राब्यू)

### सक्रिय मरीजों की संख्या हुई एक हजार से कम

नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर पिछले कई दिनों से 0.15 फीसद से कम है। इससे 100 से कम नए मामले आ रहे हैं। रविवार को भी 94 नए मामले आए। वहीं 111 मरीज ठीक हुए। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या 1016 से घटकर 992 हो गई है। अस्पतालों में अब सिर्फ 586 मरीज भर्ती हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से सात मरीजों की मौत हो गई। (राब्यू)

### हवाई जहाज से आता था चोरी की गाड़ियां खरीदने

नई दिल्ली: मध्य जिला पुलिस के वाहन चोरी निरोधक दस्ते (एएटीएस) की टीम ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कश्मीर के बारामूला इलाके के दोबागाह निवासी शौकत अहमद उर्फमल्ला (25) व उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना निवासी मोहम्मद जुबैर (22) को गिरफ्तार किया है। आरोपित शौकत चोरी की गाड़ियों को खरीदने हवाई जहाज से दिल्ली आता था, जबकि जुबैर अपने अन्य साथियों को गाजियाबाद के लोनी निवासी नूर मुहम्मद उर्फ रिंकू, बागपत निवासी जुबैर व अब्बास के साथ गाड़ियों की चोरी करता था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान रिंकू फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। (जासं)

# इस वर्ष भारत रत्न का सम्मान डाक्टरों को मिले : केजरीवाल

**अपील** ▸ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बाबत प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

यदि नियम किसी समूह को भारत रत्न देने की इजाजत नहीं देता तो इसे बदला जाए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार से अपील की है कि इस साल का भारत रत्न का सम्मान डाक्टरों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इससे मेरा तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। देश के सभी डाक्टर, नर्स और पैरामेडिकल के समूह को यह सम्मान मिलना चाहिए। सीएम ने यह मांग रविवार को स्टेप वन की तरफ से आयोजित डाक्टर्स डे समारोह में भारत सरकार से की। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि देश चाहता है कि इस वर्ष भारत रत्न का सम्मान भारतीय डाक्टर को दिया जाए।

सीएम कहा कि कोरोना से लड़ते हुए अनेक डाक्टरों और नर्सों ने अपनी जान गंवाई। यदि हम उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करते हैं, तो यह उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लाखों डाक्टरों और नर्सों ने अपनी जान और परिवार की परवाह किए बिना निःस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। उन्हें सम्मानित करने का और शुक्रिया कहने का इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता है। सीएम ने पत्र में कहा है कि यदि नियम किसी समूह को भारत रत्न देने की इजाजत नहीं देता तो मेरा आपसे आग्रह है कि नियम को बदला जाए। आज सारा देश अपने डाक्टरों का आभारी है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने से हर भारतीय को खुशी होगी।



विचार : अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो

**कोरोना की आशंकित तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां जारी :** मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। दिल्ली सरकार की तरफ से उसके मद्देनजर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भगवान न करें कि तीसरी लहर आए, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में हम बातें सुन रहे हैं, उसे देखकर हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। सीएम ने कोरोना के दौरान शहीद हुए डाक्टरों व फ्रंटलाइन वर्कर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने शहीद हुए डाक्टरों या फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी। यह कोई मुआवजा नहीं है, बल्कि यह धन्यवाद बोलने का एक तरीका है कि हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। सीएम ने कहा कि पूरे मेडिकल समुदाय ने आगे बढ़कर इस कोरोना काल में देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे ऐसे डाक्टरों को जानता हूं, जो कई-कई महीनों तक अपने घर नहीं गए।

केजरीवाल ने वाट्सएप पर आए एक मैसेज का जिक्र करते हुए कहा, 'मेरे पास एक मैसेज आया था, जिसमें बहुत ही दिलचस्प लिखा था कि कोरोना के काल में मंदिर बंद हैं, क्योंकि भगवान सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में घूम रहा है।' लेकिन, इसके बावजूद ऐसे भी कई मौके आए जब कुछ लोगों ने डाक्टरों के साथ गलत व्यवहार किया। हालांकि 90-95 फीसद मामलों में डाक्टर जैसा भी हो, बर्दाश्त करते हैं। लेकिन, जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो उनको कभी-कभी विरोध भी करना पड़ता है।

## 72 संग्रह केंद्रों पर नहीं हो रहा ई-कचरा नियमों का पालन : डीपीसीसी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के निरीक्षण में राजधानी के 72 संग्रह केंद्र ई-कचरा प्रबंधन के नियमों को उल्लंघन करते पाए गए हैं। डीपीसीसी ने इन सभी संग्रह केंद्रों से जुड़े उत्पादकों को दिए गए विस्तारित निर्माता की जिम्मेदारी (ईपीआर) को रद करने व कड़ी कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को पत्र लिखा है। ईपीआर ई-कचरा प्रबंधन नियमों की मुख्य विशेषताओं में से एक है, इसके तहत बाजार में रखी गई सामग्री से निकलने वाले ई-कचरा के संग्रह और सुरक्षित निपटान की जिम्मेदारी ब्रांड मालिक की है।

दिल्ली में राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण होने के नाते डीपीसीसी पर ईपीआर के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में हाल के दिनों में डीपीसीसी ने अधिकृत संग्रह केंद्रों का निरीक्षण किया। इसमें 83 संग्रह केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 72 को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि आवासीय क्षेत्रों में संचालित 185 अवैध ई-कचरा संग्रह केंद्रों को दो वर्ष में बंद किया जा चुका है। डीपीसीसी ने यह भी कहा कि अधिकतर केंद्र ई-कचरा प्रबंधन नियमों के क्रियान्वयन में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे केंद्रों के खिलाफ अब सख्ती की जाएगी।

# दिल्ली में पंजाब का बिजली माडल लागू करे केजरीवाल सरकार : माकन

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

▸ कहा, देश में सबसे महंगी है दिल्ली में बिजली और सब्सिडी सबसे कम

▸ किसानों से वसूला जा रहा 5.02 रुपये प्रति यूनिट, 125 रुपये फिक्स चार्ज भी

पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त और 24 घंटे निर्बाध बिजली देने की घोषणा कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली कांग्रेस के निशाने पर हैं। शीला दीक्षित सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन कहते हैं कि दिल्ली में बिजली देश में सबसे महंगी और सब्सिडी सबसे कम है, जबकि इसके विपरीत पंजाब की बिजली व्यवस्था दिल्ली से कहीं बेहतर है। वह कहते हैं कि केजरीवाल पंजाब की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें पहले दिल्ली में पंजाब जैसा माडल लागू करके दिखाना चाहिए।

माकन का कहना है कि दिल्ली में औसत बिजली दर 6.85 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि पंजाब में 4.62 रुपये है। दिल्ली में किसानों को बिजली बिल पर कोई छूट नहीं है, उनसे 5.02 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल वसूला जाता है और किसानों को प्रतिमाह 125 रुपये फिक्स चार्ज भी देना पड़ता है। वहीं, पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। किसानों के यहां बिजली के मीटर तक नहीं लगे हैं और उनका बिल भी नहीं आता है।

दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों को 10.69 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलती है तो पंजाब में 6.10 रुपये, व्यावसायिक उपभोक्ताओं को दिल्ली में 12.38 रुपये प्रति यूनिट बिजली का भुगतान करना पड़ता है, जबकि पंजाब में 8.23 रुपये ही देने पड़ते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को दिल्ली में 5.11 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है, जबकि पंजाब में यह दर 4.66 रुपये प्रति यूनिट है।



अजय माकन की फाइल फोटो।

माकन के अनुसार, पंजाब में 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। यदि किसी का बिल इससे अधिक आता है तो भी 200 यूनिट मुफ्त ही रहती है, जबकि दिल्ली में 400 यूनिट से ऊपर बिल जाते ही पूरे बिल का भुगतान करना पड़ता है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा वर्ष में पंजाब सरकार की बिजली सब्सिडी बढ़कर 2.60 रुपये प्रति यूनिट हो गई है, लेकिन दिल्ली में अब भी केवल 74 पैसे है।

# छात्रों के हक की आवाज उठाई, नहीं भरूंगी जुर्माना : नेहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अंबेडकर विश्वविद्यालय के वर्चुअल दीक्षा समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करने के बाद लगाए गए जुर्माने को छात्रा नेहा ने जमा करने से इन्कार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के छात्रों के हक की आवाज उठाई थी, किसी तरह के असंसदीय और अमर्यादित शब्द नहीं कहे थे, इसलिए माफी मांगने और जुर्माना भरने का सवाल ही नहीं उठता। विश्वविद्यालय द्वारा जुर्माना लगाया जाना सच व हक की लड़ाई को दबाने का प्रयास है।

नेहा अंबेडकर विश्वविद्यालय में स्कूल आफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन में परास्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वह विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति में हुए बदलाव और एससी-एसटी वर्ग के हक पर हो रहे हमले को लेकर एक साल से आवाज उठा रही हैं। विश्वविद्यालय में पहले एससी-एसटी वर्ग की फीस माफ करने का प्रविधान था, वह खत्म कर दिया गया। अब इस वर्ग के दूसरे राज्यों के छात्रों से दिल्ली के ही जाति प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, जिससे छात्र बहुत परेशान हैं। इस संबंध में वह बीते वर्ष उपमुख्यमंत्री कार्यालय गई थीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नेहा ने बताया कि उन्होंने 23 दिसंबर 2020 को यूट्यूब पर लाइव प्रसारित हुए दीक्षा समारोह के दौरान भी इसी विषय को लेकर टिप्पणी की थी। उनका आरोप है कि उनके साथ कई अन्य छात्रों ने भी टिप्पणियां की थीं, लेकिन उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।



छात्रा का कहना, दिल्ली का प्रमाण पत्र मांगे जाने से एससी-एसटी छात्रों की हो रही है परेशानी

हाल ही में विश्वविद्यालय ने नेहा को नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार उन्हें छात्रों के लिए निर्धारित और अधिसूचित अनुशासन संहिता का उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि जुर्माना न भरने पर वह परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगी। वहीं, सहायक कुलसचिव (जनसंपर्क) का कहना है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए समय-समय पर कदम उठाते हैं।

## तिहाड़ में बंद सुशील कर रहा टेलीविजन की फरमाइश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में आरोपित ओलंपियन सुशील कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन से टेलीविजन की मांग की है। उसने जेल प्रशासन से कहा कि उसका मन जेल में नहीं लग रहा है। ऐसे में उसे टीवी की सुविधा दी जाए, जिससे कि वह कुश्ती के मैच देख सके।

पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पुलिस 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपित सुशील कुमार नौ जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। जेल सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार की अर्जी उच्चाधिकारियों तक पहुंच गई है और उन्हें ही कोई अंतिम फैसला लेना है। अगर जेल प्रशासन को लगेगा कि सुशील को टीवी की सुविधा मिलनी चाहिए तो संभव है उसे यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। इससे पहले सुशील ने एक्स्ट्रा प्रोटीन वाली डाइट की मांग की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने इन्कार कर दिया था। जेल प्रशासन का कहना है कि सुशील कुमार को अभी जो खाना दिया जा रहा है वह उसके वजन के हिसाब से पर्याप्त है। ऐसे में एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला खाना नहीं दिया जाएगा।

ज्ञात हो कि मंडोली जेल नंबर 15 से कुछ दिनों पहले ही सुशील को तिहाड़ के जेल नंबर दो में लाया गया है। उस पर जेल कर्मचारियों के साथ-साथ सुरक्षाकर्मी 24 घंटे निगरानी रखते हैं।

# फंड रोकने के बाद भी निगमों के स्कूल दे रहे हैं बेहतर नतीजे : भाजपा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ प्रदेश भाजपा और पूर्व उप महापौर ने किया सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार

▸ कम शिक्षक होने के बावजूद बच्चों को मिल रही है अच्छी शिक्षा

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा नगर निगमों पर लगाए गए आरोपों का प्रदेश भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि केंद्र की जिस रिपोर्ट का हवाला देकर सिसोदिया ने नगर निगम स्कूलों मे औसत से भी कम पीटीआर का उल्लेख किया। उसके अन्य बिंदुओं में निगमों के स्कूल दिल्ली सरकार से बेहतर पाए गए हैं। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार द्वारा फंड रोकने के बाद भी निगम के स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि निगम के स्कूलों में ज्यादातर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। फिर भी उनमें हर साल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही है। दिल्ली सरकार के 75 फीसद स्कूलों में 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान और 65 फीसद स्कूलों में कामर्स नहीं पढ़ाई जाती। निगम अपने प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं।

उन्होंने कहा कि पीटीआर की बात करें तो उसका मुख्य कारण दिल्ली सरकार है। सरकार ने निगमों के फंड रोके हुए हैं। नतीजा यह है कि नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। शिक्षक कम होने के बाद भी निगम के शिक्षक बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं।

वहीं, उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर व वरिष्ठ भाजपा नेता जय प्रकाश ने सिसोदिया को चुनौती दी कि वह दिल्ली सरकार के 10 बेहतरीन विद्यालयों को चुनकर नगर निगमों के 10 विद्यालयों से तुलना कर लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंन कहा कि नगर निगमों को 250 करोड़ रुपये का फंड शिक्षा मद में मिलना था, लेकिन वह नहीं मिला।

### 20 साल में निगमों ने किया स्कूलों का बेड़ा गर्क : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भाजपा शासित निगमों ने 20 साल में स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। निगम के स्कूलों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ये स्कूल आज देश के सबसे पिछड़े स्कूल बन चुके हैं। इससे दिल्ली की छवि खराब हो रही है। उन्होंने दावा किया कि यह बात केंद्र सरकार की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में साफ हो गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के 98 फीसद स्कूलों में आरटीई के मानकों के अनुसार पीटीआर (विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात) है, लेकिन नगर निगम के स्कूलों की बात करें तो ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 58 फीसद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 46 फीसद व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 39 फीसद स्कूलों में मानकों के मुताबिक शिक्षक नहीं हैं। ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम अपनी लापरवाही के कारण अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षक तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ये दिल्ली का नाम खराब करने का काम कर रहे हैं। वहीं, दिल्ली सरकार के स्कूलों को वर्ल्डक्लास बनाया जा रहा है।

# कोरोना से उबरे 22 फीसद मरीज छह माह तक रहे बीमार



कोरोना से अगर आप जंग जीत भी चुके हैं, तो भी सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल, एम्स के अध्ययन में यह पता चला है कि संक्रमण का शिकार होने वाले 22 फीसद मरीज तीन से छह माह तक अलग-अलग बीमारियों से जूझते रहे हैं। डाक्टर कहते हैं कि घबराएं नहीं, कोरोना से उबरने के बाद सतर्कता बरतें और किसी तरह की परेशानी होने पर डाक्टर से तत्काल संपर्क करें।

**अध्ययन का निष्कर्ष**

22 फीसद मरीजों में लांग कोविड देखा गया। इनमें से 12.1 फीसद मरीजों में तीन माह तक व 9.9 फीसद मरीजों में तीन माह के बाद भी लक्षण बरकरार थे।

| देखी गईं ये समस्याएं | |
|---|---|
| मांसपेशियों में दर्द | 10.9 फीसद |
| थकान | 5.5 फीसद |
| सांस लेने में परेशानी | 6.1 फीसद |
| सूखी खांसी | 2.1 फीसद |
| नींद न आना | 1.4 फीसद |
| मनोदशा में गड़बड़ी | 0.48 फीसद |
| चिंता | 0.6 फीसद |

**ऐसे किया गया अध्ययन**

1,234 मरीजों पर यह अध्ययन किया गया

276 मरीजों का छह माह तक, जबकि औसतन तीन माह तक सभी मरीजों फालोअप किया गया

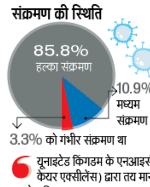
41 साल की औसत उम्र वाले मरीजों पर किया गया अध्ययन

69.4% पुरुष मरीज थे

711 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए थे, जो औसतन 11 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे।

40.11% मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने या क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के दौरान कुछ लक्षण बरकरार थे।

**अध्ययन में शामिल मरीजों में संक्रमण की स्थिति**






यूनाइटेड किंगडम के एनआइसीई (नेशनल इंस्टीट्यूट फार हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस) द्वारा तय मानक के अनुसार चार से 12 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लक्षण बरकरार रहने पर लांग कोविड सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी में ब्लड क्लाट की समस्या भी देखी जा रही है। फेफड़े में संक्रमण की वजह से लंबे समय तक सांस लेने में परेशानी हो सकती है। मध्यम व गंभीर संक्रमण के मरीजों के इलाज में कई तरह की दवाएं चलती है। सकारात्मक सोच, सांस से संबंधित योग व व्यायाम से इस पर काबू पाया जा सकता है। - डा. नीरज निश्चल, एम्स के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर व अध्ययन करने वाली टीम के सदस्य

**कोरोना से पहले बीमारी की स्थिति**

28.5% मरीजों को कम से कम एक बीमारी थी

5.8% मरीजों को थायराइड थी

8.1% मरीजों को हाइपरटेंशन थी

13.4% मधुमेह था

प्रस्तुति : रणविजय सिंह

# मेट्रो कारिडोर के निर्माण की आनलाइन होगी निगरानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने परियोजनाओं की आनलाइन निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मानीटरिंग साफ्टवेयर (आइपीएमएस) तैयार कराया है। इसके माध्यम से डीएमआरसी दिल्ली में फेज चार के मेट्रो कारिडोर के निर्माण कार्य, उससे जुड़ीं तमाम गतिविधियों व पटना मेट्रो की परियोजना की आनलाइन निगरानी कर सकेगा।

कोरोना के संक्रमण के दौर में अधिकारियों के साथ बार-बार बैठक कर निर्माण कार्य की समीक्षा और निगरानी आसान नहीं रहा। ऐसे में आनलाइन विकल्प की तलाश की गई है और अप्रैल में देश में ही यह साफ्टवेयर तैयार किया गया। फेज चार के मेट्रो कारिडोर के निर्माण कार्य का पूरा शेड्यूल तैयार कर उसे साफ्टवेयर पर अपलोड किया जा चुका है। मोबाइल, लैपटाप व कंप्यूटर के माध्यम से उच्च अधिकारी तक 24 घंटे परियोजनाओं पर नजर रख सकेंगे। अधिकारियों को निर्माण कार्यों की प्रगति का हाल लेने के लिए बार-बार निर्माणाधीन स्थल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

**9.19** फीसद पर आ गई है जून में बेरोजगारी दर। यह मई में 11.9 फीसद थी। ऐसा देश में आर्थिक गतिविधियों के गति पकड़ने से संभव हुआ।

# जनसंख्या नियंत्रण पर राजी हुए असम के मुस्लिम बुद्धिजीवी

### सीएम ने कहा, समुदाय के विकास के उपाय सुझाने को आठ उपसमूह गठित होंगे, तीन माह में देंगे रिपोर्ट

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने रविवार को 150 से अधिक स्थानीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। सीएम ने बताया, सभी ने सहमति व्यक्त की कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए खतरा है।

बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में सरमा ने बताया, 'मैंने आज (रविवार) 150 से ज्यादा बुद्धिजीवियों, लेखकों कलाकारों, इतिहासकारों, प्रोफेसरों और अन्य से मुलाकात की। हमने ऐसे विभिन्न मसलों पर विचार किया जिनका असम के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सामना कर रहे हैं। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि असम के कुछ भागों में जनसंख्या विस्फोट राज्य के विकास के लिए खतरा है। असम को अगर देश के पांच शीर्ष राज्यों में शुमार होना है तो हमें अपने जनसंख्या विस्फोट से निपटना होगा। इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की।'



असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। फाइल इंटरनेट मीडिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख शख्सियतों ने अल्पसंख्यक समुदाय में जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि सरकार आठ उपसमूहों का गठन करेगी जिनमें स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग सदस्य होंगे। ये उपसमूह अगले तीन महीनों में समुदाय के विकास को लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे। ये उपसमूह स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, सांस्कृतिक पहचान, जनसंख्या स्थिरीकरण और वित्तीय समावेश जैसे सेक्टरों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये उपसमूह अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। इन रिपोर्टों का संकलन करने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए एक रोडमैप बनाया जाएगा। उसी रोडमैप के मुताबिक सरकार अगले पांच साल तक काम करेगी। हर उपसमूह में समुदाय से एक चेयरमैन और सरकार की ओर से एक सदस्य सचिव होगा। सीएम ने बताया कि अगले दौर की बैठक मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिज्ञों और छात्र संगठनों के साथ होगी। साथ ही उन्होंने कहा, 'अगले कुछ दिनों में मैं प्रवासी मुस्लिमों या मूल रूप से पूर्वी बंगाल के मुस्लिमों के प्रतिनिधियों के साथ बैठूंगा... दोनों मुस्लिम समुदायों (स्थानीय और पूर्वी बंगाल) के बीच विशिष्ट सांस्कृतिक अंतर है और हम उसका सम्मान करते हैं।' बैठक में पद्मश्री डा. इलियास अली और अली अहमद जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के प्रख्यात लोग शामिल थे। समाचार एजेंसी 'एएनआइ' के मुताबिक, सरमा ने शनिवार को कहा था कि वह राज्य की दो बच्चों की नीति के मद्देनजर मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि दो बच्चों की नीति ही राज्य में मुस्लिम समुदाय की गरीबी और निरक्षरता खत्म करने का एकमात्र रास्ता है और इस मामले में अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से कोई विरोध नहीं है।

## मनी लांड्रिंग केस में कार्रवाई से बचने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख ने मनी लांड्रिंग केस में किसी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को इस मामले में 71 वर्षीय देशमुख को पांच जुलाई को पेश होने के लिए नया समन जारी किया था। ईडी ने अभी तक देशमुख को तीन नोटिस जारी किए हैं। एजेंसी ने उनसे दक्षिण मुंबई स्थित अपने कार्यालय में आकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा है।



अनिल देशमुख

मीडिया को जारी एक वीडियो संदेश में मुंबई के एक वकील इंदरपाल बी. सिंह ने बताया कि देशमुख ने किसी भी तरह की कार्रवाई से संरक्षण की मांग करते हुए शीर्ष अदालत की शरण ली है। कोरोना संक्रमण के खतरे का हवाला देकर देशमुख पूर्व में जारी दो समन की अनदेखी कर चुके हैं। कार्यालय आने के बजाय उन्होंने ईडी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज कराने का प्रस्ताव दिया है। ईडी ने नया समन प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज आपराधिक मामले में जारी किया है जो 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत व वसूली रैकेट से जुड़ा है।

# मोदी सबसे बेहतर निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री : डा. अहमद

धनंजय वर्मा, गाजियाबाद

- कट्टरता के कारण मुस्लिम समाज जिस रास्ते पर चल रहा वह अंधे कुएं की ओर जाता है

'वैचारिक समन्वय - एक पहल' के लेखक डा. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने अपनी पुस्तक के विमोचन के दौरान मुस्लिम समाज को बरगलाने वाले नेताओं पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुस्लिमों के कहने पर टोपी पहनी, उन्होंने ही समाज के लोगों को टोपी पहना दी। अर्थात उन्हें बेवकूफ बनाया। पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया, वह ही पूरे देश के लिए सही है। नरेंद्र मोदी देश के लिए सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं।

इफ्तिखार ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ रहते हैं। आज के बाद दोनों के बीच दोस्ती और भरोसा होगा। देवबंद और बरेली के बीच की दूरी भी कम हुई है। अब हम सबके बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। 1857 से चली आ रही एकता खिलाफत आंदोलन के बाद टूट गई। अगर यही एकता होती तो देश का विभाजन न होता। विभाजन का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि आज हमें लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम राष्ट्रभक्त हैं। आरएसएस जैसा संगठन मुस्लिम समाज के पास नहीं, जिसकी कोई विचारधारा हो। मुस्लिमों की बस एक सोच होती है कि किसी भी कीमत पर भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। अब समय है कि हमें एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान पैदा करना होगा। मुस्लिम समाज आंखों से पट्टी हटाए और सबको गले लगाए। मुस्लिम समाज जिस रास्ते पर चल रहा है वह अंधे कुएं की ओर जाता है।



डा. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद। जागरण

### मुस्लिम स्कालर बोले, अब एक होने का समय

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत ने हिंदू-मुस्लिम समाज को एक होने का सीधा संदेश दिया। कार्यक्रम में मौजूद मुस्लिम स्कालरों ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया और कहा कि अब देश के हित के लिए सभी को एक होने की जरूरत है। विमोचन कार्यक्रम में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा आदि से मुस्लिम स्कालर व कालेजों के प्रोफेसर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब खुले दिल से सोचने का वक्त है। दिल्ली से आए मोहम्मद साबरीन ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हमने बहुत कुछ खोया है। हमारी कई पीढ़ियां इसका दर्द झेल रही हैं। अब हमें उस सोच से बाहर आकर एक दूसरे को गले लगाना होगा। डा. इमरान चौधरी ने कहा कि शिक्षित व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। सभी को एक साथ लेकर चलने के बारे में सोचता है। ऐसे में अब हम सभी को इसी सोच से चलना होगा। तभी देश आगे बढ़ेगा।

# ब्रिटेन व इटली के चार दिवसीय दौरे के लिए सेना प्रमुख रवाना

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे रविवार को ब्रिटेन और इटली के चार दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। उनकी यात्रा का मकसद दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है।

सेना ने कहा कि जनरल नरवणे सैन्य सहयोग को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दोनों देशों के समकक्षों एवं वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे।



सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे। जागरण आर्काइव

नरवणे अपनी यात्रा के पहले चरण में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री, रक्षा प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ), चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। वह सेना के विभिन्न फॉर्मेशन्स का भी दौरा करेंगे जहां वह आपसी हित के मुद्दों पर वैचारिक आदान-प्रदान करेंगे। सेना ने एक बयान में कहा, 'यात्रा के दूसरे चरण में (सात व आठ जुलाई) सेना प्रमुख इटली के रक्षा प्रमुख और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ महत्वपूर्ण विचार-विमर्श करेंगे। इसके अतिरिक्त सेना प्रमुख प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सेना के स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे और रोम के सेचिंगोला में इतालवी सेना के 'काउंटर आईईडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में उन्हें विभिन्न पक्षों से अवगत कराया जाएगा।'

### रक्षा सचिव ने चीन व नेपाल सीमा क्षेत्र का लिया जायजा

जासं, पिथौरागढ़ : रक्षा सचिव डा. अजय कुमार ने चीन और नेपाल सीमा से सटे इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने सीमा पर बन रही सड़कों का भी हवाई निरीक्षण किया। गुंजी गांव पहुंच कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। रविवार को पहली बार रक्षा सचिव डा. अजय चीन और नेपाल सीमा का जायजा लेने पहुंचे। धारचूला स्थित सेना के हेलीपैड पर उतरने के बाद जिलाधिकारी आनंद स्वरूप और पुलिस अधीक्षक सुखवीर सिंह से वार्ता की। इसके बाद वह हेलीकाप्टर से गुंजी पहुंचे। वहां उन्होंने सैन्य अधिकारियों से सीमा की स्थिति की जानकारी ली और जवानों की समस्याएं सुनीं।

# देश भर में नदी जोड़ो परियोजना की बन रही डीपीआर : शेखावत

जागरण संवाददाता, महोबा

- केंद्रीय जलशक्ति मंत्री बोले- अर्जुन सहायक परियोजना पूरी, पीएम से कराएंगे लोकार्पण
- जनांदोलन बनाना होगा पानी का आंदोलन, केन-बेतवा लिंक करने का कार्य इसी वर्ष से

केंद्र सरकार नदी जोड़ो परियोजना पर कदम आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को उप्र के महोबा में कहा कि देश भर में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए नदी जोड़ो परियोजनाओं की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की जा रही है। इसी वर्ष से ही केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्य शुरू हो जाएगा। 2600 करोड़ रुपये की लागत से अर्जुन सहायक नहर परियोजना पूरी हो गई है। जल्द ही प्रधानमंत्री से इस परियोजना का लोकार्पण कराया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री दोपहर करीब सवा दो बजे हेलीकाप्टर से महोबा के लहचूना बांध परिसर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री डा. महेंद्र सिंह के साथ अर्जुन सहायक के साथ लहचूरा डैम व काशीपुरा पेयजल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। बोले, प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के लिए कई परियोजनाएं संचालित की हैं, जिनके पूर्ण हो जाने पर यहां की धरती प्यासी नहीं रहेगी। हम सभी को पानी के आंदोलन को जनांदोलन बनाना होगा। वन महोत्सव कार्यक्रम के मौके पर लहचूरा तट बंध पर दोनों मंत्रियों ने पाकड़ तथा नीम का पौधा लगाया।



दी जानकारी : गजेंद्र सिंह शेखावत फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

### जल, जंगल, जमीन व वायु में हर जीव का अधिकार

जासं, चित्रकूट : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को चित्रकूट के देवांगना हवाई पट्टी के पास रामवन में पीपल का पौधा लगाकर पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, जल, जंगल, जमीन व वायु पर मानव का एकाधिकार नहीं है, हर जीव का अधिकार है। यहां 35 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार हो रहे रामवन में रामायणकालीन 88 प्रजाति के पौधे जैसे चंदन, साल, बरगद, अनार, बहेड़ा, शीशम, चिलबिल, अमलतास, आम, महुआ, अर्जुन, बेल, पीपल, बांस, कनेर ,बड़हल, अशोक, कटहल, छितवन, आंवला, बेर और सेमल आदि लगाए गए हैं।

# 'परिसीमन का मकसद हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना'

राज्य ब्यूरो, जम्मू

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया करने का मकसद हर वर्ग और विधानसभा में हर क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है। जम्मू-कश्मीर का मामला देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की विसंगतियों को वर्षों से ठीक नहीं किया। जम्मू-कश्मीर में, सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां जो अधिकतर गैर भाजपा थीं, ने विधानसभा की सीटों को ठीक नहीं किया। जानबूझकर परिसीमन की प्रक्रिया को टाला जाता रहा।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि परिसीमन करने का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और हर क्षेत्र को विधानसभा उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव परिसीमन से पहले करवाए जाने की मांग कर रही हैं तो उन्होंने कहा कि यह तो चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कब करवाने हैं। राजनीतिक पार्टी के तौर पर भाजपा साल में 24 घंटे किसी भी स्तर पर चुनाव के लिए तैयार है संसदीय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या फिर निकायों के चुनाव।

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां अफवाह फैला रही हैं कि भाजपा परिसीमन आयोग पर प्रभाव डाल रही है कि सीटें इस तरह से बढ़ाई जाएं कि उसको फायदा मिले। यह आरोप कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों की सोच को दर्शाती है। कांग्रेस ने देश में छह दशक तक शासन किया और चुनाव आयोग, सीबीआइ समेत संवैधानिक संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करती रही। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो नियमों के तहत काम करता है। इसलिए परिसीमन आयोग पर आरोप लगाना सही नहीं होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संस्थानों के स्वतंत्र होने का सम्मान करती है। कभी भी इन संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती। परिसीमन आयोग छह जुलाई से नौ जुलाई तक जम्मू-कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर है।

## जेईई मेन और नीट की मुश्किलें भी होंगी आसान

प्रथम पृष्ठ से आगे

बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही शिक्षा मंत्रालय अब इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य (जेईई मेन) और मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के आयोजन से जुड़ी मुश्किलों को भी आसान बनाने में जुटा है। कोरोना के चलते दो साल से यह परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं।

इन परीक्षाओं को आनलाइन आयोजित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इनके आयोजन से जुड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इससे जुड़ा एक प्लेटफार्म तैयार भी कर लिया है, लेकिन अभी वह जेईई मेन और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को एक साथ कराने में सक्षम नहीं है। इस व्यवस्था को अभी फुलप्रूफ भी नहीं माना जा रहा है। वहीं, जेईई मेन और नीट देने वाले सभी छात्रों तक कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच न होना भी एक बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके शिक्षा मंत्रालय इस समस्या को सुलझाने में पूरी ताकत से जुटा है। इसमें इन परीक्षाओं को छोटे ग्रुप में और कामन सर्विस सेंटर के जरिये कराने पर भी विचार चल रहा है।

# नया समझौता : नेपाल में भी दौड़ेगी प्राइवेट कंटेनर ट्रेन

काठमांडू, आइएएनएस : आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए भारत और नेपाल ने रेलवे सर्विस एग्रीमेंट में नया बदलाव किया है। समझौते के नए मसौदे के अनुसार, दोनों देशों के प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर माल लाने-भेजने में भारतीय रेल के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नए प्रविधान से भारत सरकार के उपक्रम कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) का एकाधिकार खत्म हो जाएगा।

काठमांडू पोस्ट अखबार के अनुसार इस नए प्रविधान पर दोनों देशों में 30 जून को सहमति बनी। मूल समझौता 2004 में हुआ था लेकिन इसमें अनुभवों के आधार पर कई बार बदलाव हो चुके हैं। इससे दोनों देशों का सीमा पार माल का निर्यात-आयात बढ़ने की संभावना है। इससे निजी क्षेत्र रेलवे की बुनियादी सेवाओं के विस्तार की प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा। इससे कारोबार बढ़ेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही माल को लाने- ले जाने का खर्च कम होगा। इसका फायदा वस्तु की लागत पर पड़ेगा और अंततः उपभोक्ता को अपेक्षाकृत सस्ता सामान मिलेगा। समझौते के इस नए प्रविधान से भारतीय बंदरगाहों से नेपाल जाने वाले माल को सीमावर्ती नेपाली शहरों से आगे ले जाने का रास्ता भी तैयार होगा। दोनों देश एक-दूसरे को जोड़ने वाले कुछ और रेल नेटवर्क तैयार करने के कार्य में लगे हुए हैं। नेपाली अधिकारियों के अनुसार इस नए प्रविधान और नए रेल संपर्क से दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत और फायदेमंद बनेंगे। इसका सीधा लाभ दोनों देशों के लोगों को होगा। नेपाली अधिकारियों, विशेषज्ञों और व्यापार जगत ने इस नए प्रविधान का स्वागत किया है। इसे लंबे समय तक होने वाले फायदे का माना है। इससे दोनों देशों के कारोबारियों को तीसरे देश में कारोबार करने में भी मदद मिलेगी।

- भारत और नेपाल के बीच हुआ समझौता



कॉनकोर का एकाधिकार होगा खत्म। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

## केरल कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ सतर्कता जांच के आदेश

तिरुअनंतपुरम, आइएएनएस : केरल पुलिस के सतर्कता महानिदेशक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के. सुधाकरन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सुधाकरन पर उनके पूर्व वाहन चालक प्रशांत बाबू ने भ्रष्टाचार व गबन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।

सतर्कता महानिदेशक सुदेश कुमार ने प्रशांत बाबू की शिकायत की जांच करके सतर्कता टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। प्रशांत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाई है। सुधाकरन ने कन्नूर जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के निर्माण के लिए आवंटित राशि का भी गबन किया है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण के नाम पर गठित एक ट्रस्ट से भी गबन किया है।

राज्य के सतर्कता विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में सुधाकरन पर लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी। इस प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

# राजस्थान के राज्यपाल की किताब खरीदने का कुलपतियों पर दबाव

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की आत्मकथा पर आधारित कॉफी टेबल बुक 'कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं' की बिक्री को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। मिश्र के जन्मदिन पर राजभवन में एक जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में 27 सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए थे। आरोप है कि प्रत्येक कुलपति को किताब की 19-19 प्रतियों के साथ ही उनका बिल थमा दिया गया है। प्रत्येक कुलपति को 68,383 का बिल दिया गया। इस तरह कुल 18 लाख 54 हजार 441 के बिल दिए गए हैं। हालांकि, राजभवन सचिवालय का कहना है कि किताब और बिल कुलपतियों को देने से उनका कोई सरोकार नहीं है। राजभवन ने इस संबंध में रविवार को एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कुलपतियों को किताब और बिल देने का काम किताब के लेखक डा. डीके टकनेट ने किया है। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डा. सीपी जोशी ने किताब का विमोचन किया था।

जानकारी के अनुसार पांच कुलपतियों ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षामंत्री भंवर सिंह भाटी के समक्ष इस तरह से किताबों के बिल दिए जाने पर आपत्ति जताई है। उधर, राज्यपाल के ओएसडी गोविंदराम जायसवाल का कहना है कि किताब की प्रतियां और बिल राजभवन के किसी कर्मचारी ने कुलपतियों को नहीं दिए हैं। प्रकाशक के कर्मचारी ने अगर ऐसा किया हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जायसवाल खुद इस किताब के सह लेखक हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जसवंत गुर्जर ने इस तरह से कुलपतियों को किताब और बिल दिए जाने को गलत बताया है। एक कुलपति ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राजभवन में पहुंचते ही एक व्यक्ति ने सभी के वाहन चालक के मोबाइल और गाड़ियों के नंबर ले लिए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जैसे ही वह गाड़ी में बैठे तो उनके चालक ने उनके हाथ में एक बिल थमा दिया। उसने बताया कि एक व्यक्ति ने गाड़ी की डिक्की में किताबें रखने के साथ ही कहा था कि साहब को कह कर इस बिल का भुगतान करवा देना। एक किताब की कीमत 3,999 रुपये है। इस तरह 19 किताबों की कीमत 75,981 हुई। लेकिन बिल में 10 प्रतिशत छूट के बाद 68,383 का भुगतान करने के लिए कहा गया। बिल का भुगतान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एन्टरप्रन्योरशिप(आइआइएमई)के खाते में करने के लिए कहा गया है। इस संगठन के कर्ताधर्ता टकनेट हैं। टकनेट इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान बताते हुए कहते हैं कि यह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। वहीं, किताब की बिक्री को लेकर रविवार को राजभवन पीआर सेल की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इसमे कहा गया कि यह मुख्यरूप से प्रकाशक आइआइएम शोध संस्थान और खरीदने वालों के बीच की निजी मामला है। प्रकाशक ने पुस्तक प्रकाशित कर राजभवन में उसके लोकापर्ण की अनुमति मांगी थी, जो उन्हें दी गई। किताब के विपणन की व्यावसायिक गतिविधियों में राजभवन की कोई भूमिका नहीं है।

**बदला परिदृश्य**

# अफगानिस्तान में पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा भारत

**बदले वैश्विक परिदृश्य में तालिबान के लिए भारत को पूरी तरह नकारना होगा मुश्किल, भारत के लिए कश्मीर में अंतिम सांसें गिन रहे आतंकवाद को तालिबानी संजीवनी से बचाने की चुनौती**

नीलू रंजन, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भले ही तालिबान से किसी तरह की बातचीत से इन्कार किया हो, लेकिन इतना तय है कि भारत फिर से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, जिसमें संपर्कहीनता और संवादहीनता रहे। दरअसल, पिछली सदी के आखिरी दशक में तालिबान के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं होना भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। खासतौर पर कंधार विमान अपहरण कांड के दौरान काबुल में भारत का पक्ष सुनने वाला कोई नहीं था। तालिबान सरकार पूरी तरह आइएसआइ के इशारे पर काम कर रही थी और मजबूरी में भारत को अजहर मसूद समेत तीन आतंकियों को रिहा करना पड़ा था, जिसने भारत में सबसे अधिक घातक हमले करने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद की स्थापना की थी। कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुटों के साथ तालिबान की निकटता भारत के लिए चिंता का विषय रहा है।

अमेरिकी व नाटो सैनिकों की वापसी के साथ-साथ अफगानिस्तान में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर नजर रखने वाली सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अनुसार सितंबर 2001 में सत्ता से बेदखल होने के 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान काबुल में सत्तासीन होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पिछले दो दशक में तालिबान और भारत दोनों के लिए वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। ओसामा बिन लादेन की मौत और अलकायदा के कमजोर पड़ने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के खिलाफ जेहाद की धार कुंद हुई है। सत्ता में वापसी के बाद तालिबान का उद्देश्य सिर्फ शरीयत के अनुसार शासन करना नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में एक स्थायी सरकार देकर विकास के रास्ते की तलाश भी होगी। जाहिर है इसके लिए उसे अफगानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ किसी तरह का समझौता भी करना पड़ेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में चाहे किसी की भी सरकार हो, उसके लिए विकास में भारत के सहयोग की अनदेखी करना मुश्किल होगा। पिछले दो दशक में अफगानिस्तान में भारत की ओर से किए गए विकास के काम इसकी मिसाल हैं।



चुनौती। फाइल इंटरनेट मीडिया।

वहीं भारत के लिए जम्मू-कश्मीर में कभी चरम पर रहा आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। अनुच्छेद 370 को निरस्त कर भारत जम्मू-कश्मीर में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है और इसे वहां की राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ पाकिस्तान भी इसे स्वीकार कर रहा है। पिछले पांच महीने से सीमा पर बंद गोलाबारी इसका प्रमाण है। वहीं एफएटीएफ के शिकंजे में फंसे पाकिस्तान के लिए पहले की तरह भारत विरोधी आतंकी संगठनों की खुलेआम फंडिंग करना मुश्किल हो रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव भी बढ़ता जा रहा है। फिर भी इस चुनौती से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कश्मीर में आतंकवाद को फिर से बारूद देने की कोशिश हो सकती है।

ऐसे में भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान में खुली छूट मिलने का खतरा उठाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन भारत और तालिबान का संबंध कई परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह देखना होगा कि काबुल में मौजूदा अशरफ गनी सरकार और तालिबान का संबंध कैसा रहता है। तालिबान नजीबुल्ला की तरह अशरफ गनी सरकार को पूरी तरह उखाड़ फेंकता है या दोनों के बीच कोई तालमेल की स्थिति बनती है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में सक्रिय विभिन्न गुटों के साथ तालिबान का संबंध भी अहम साबित होगा।

**कह के रहेंगे** माधव जोशी



**82** फीसद तक आरक्षण का दायरा छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है। यह 50 फीसद आरक्षण के तय मापदंड से अधिक है। इस कारण सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 5 जुलाई, 2021

# उत्तराखंड में पुरानी नाव में सवार होकर नए खेवनहार बने धामी

**सियासी रणनीति** ▶ पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में सभी पुराने चेहरों पर जताया गया भरोसा, पिछली सरकार में रिक्त तीन सीटों पर ही शामिल किए गए नए चेहरे

## भाजपा ने युवा चेहरे पर दांव खेला, मंत्रियों से नहीं की कोई छेड़छाड़

रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून



शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एएनआइ

भाजपा ने उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी पर दांव खेला, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर सभी पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताना उचित समझा। नए मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पिछली तीरथ सरकार का भी हिस्सा रहे हैं। 2017 से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा प्रयोग किया, लेकिन मंत्रिमंडल में छेड़छाड़ नहीं की। 2017 में बनाए गए मंत्री तीसरी सरकार के गठन के वक्त भी बरकरार रखे गए हैं। गत 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाए गए तीरथ सिंह रावत की टीम में भी पुराने चेहरों को जगह मिली थी। कैबिनेट मंत्री पद छोड़कर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने मदन कौशिक की सीट समेत मंत्रिमंडल की रिक्त तीन सीट पर ही नए चेहरों को जगह दी गई थी। पुराने चेहरों को पार्टी ने बरकरार रखना मुनासिब समझा था।

**युवा कंधे पर चुनौती का पहाड़ :** युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पुरानी टीम के साथ ही नई जिम्मेदारी के मोर्चे पर आगे बढ़ना होगा। दरअसल चुनावी साल में दूसरी बार नेतृत्व परिवर्तन किया तो गया, लेकिन सत्तारूढ़ दल भाजपा और नए मुख्यमंत्री धामी के पास वक्त काफी कम बचा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आठ महीने से कम समय रह गया है। ऐसे में चुनौतियों के पहाड़ से जूझने के लिए पुरानी टीम को लेकर आगे बढ़ना पार्टी मुनासिब समझ रही है।

**विकास कार्यों की चुनौती :** केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करना है तो विकास कार्यों को गति देकर सत्ताधारी दल के विधायकों की बेचैनी से भी पार पाना है। पार्टी हाईकमान ने कम समय में बड़ी चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर डाली है। उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए कम वक्त मिला है।

**नेतृत्व को लेकर पार्टी की पहल :** पार्टी ने युवा नेतृत्व पर दांव खेलते हुए पुराने वरिष्ठ मंत्रियों का साथ बनाए रखा है। दरअसल, पिछले चार साल से ज्यादा वक्त में भाजपा सरकार ने राज्य के विकास और महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों और कार्यों के बूते ही आगामी चुनाव में पार्टी को हुंकार भरनी है। ऐसे में सभी फैसलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव को तरजीह दी गई है। प्रचंड बहुमत के सहारे भाजपा का ये प्रयोग दरअसल आगे चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखकर ही किया गया है। इसमें नए और ऊर्जावान नेतृत्व पर दांव खेलकर पार्टी ने नई पहल भी कर दी है।

**इंटरनेट मीडिया पर भी छाए धामी:** इस बीच, मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पुष्कर सिंह धामी का ग्राफ इंटरनेट मीडिया पर भी बढ़ता चला गया। बधाई संदेश व उनके संग पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं द्वारा खींची गई सैकड़ों फोटो फेसबुक व वाट्सएप पर नजर आने लगी। धामी के फेसबुक पेज पर 24 घंटे के भीतर ही 15,529 लोग जुड़ चुके थे। शनिवार शाम चार बजे उनके फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स की संख्या 356175 थी।

## 24 घंटे चला रूठों को मनाने का दौर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

**बनी बात**

- नाराज विधायकों को मनाने में पार्टी को छूटे पसीने
- अमित शाह, राजनाथ समेत अन्य नेताओं से कराई गई बात

करीब 24 घंटे तक चली मशक्कत और मान-मनुहार के बाद आखिरकार भाजपा रूठे विधायकों को मनाने में कामयाब हो गई। युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने से कुछ वरिष्ठ विधायक नाराज हो गए थे। इसे देखते हुए डैमेज कंट्रोल के लिए दून से लेकर दिल्ली तक कसरत हुई और फिर शपथ ग्रहण से करीब डेढ़ घंटे पहले पार्टी सभी को मैनेज करने में सफल हो गई। हालांकि, शपथ ग्रहण से ऐन पहले के इस पूरे घटनाक्रम ने भविष्य के लिए कई सवाल भी छोड़ दिए हैं।

शनिवार को साढ़े तीन बजे पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद ही कुछ नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी थी। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और बिशन सिंह चुफाल बैठक खत्म होते ही प्रदेश भाजपा कार्यालय से निकल गए थे। हालांकि, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरक सिंह रावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतपाल महाराज से फोन पर बातचीत की थी। भाजपा नेतृत्व तब सकते में आ गया, जब ये बात सामने आई कि नाराज चल रहे सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत व बिशन सिंह चुफाल मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। इस पर तुरंत ही पार्टी नेतृत्व डैमेज कंट्रोल के प्रयासों में जुट गया। रात में ही उनको मनाने की कोशिशें हुईं, मगर सफलता नहीं मिली।

**डैमेज कंट्रोल को बनी थी दो टीमें:** विधायकों की नाराजगी से जनता के बीच गलत संदेश न जाए, इसे देखते हुए रूठों को मनाने के लिए दो टीमें गठित की गईं। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, पूर्व मंत्री डा. धन सिंह रावत व यतीश्वरानंद को रूठों से संपर्क का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने कौशिक के आवास में बैठकर कंट्रोल रूम बनाया। इस दौरान वे भी पार्टी विधायकों से निरंतर संपर्क करते रहे।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल रहे सतपाल महाराज भी नाराज थे। विधायक दल के नेता धामी ने महाराज के डालनवाला स्थित निवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर उन्हें मनाने का प्रयास किया।

## भाजपा के धामी दांव से कांग्रेस में भी नई हलचल

राज्य ब्यूरो, देहरादून

**सियासी समीकरण**

- भाजपा की बदली परिस्थितियों के असर को तोलने में जुट गई कांग्रेस
- हफ्ते भर बाद भी नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला नहीं

कांग्रेस की सियासत में भी नई हलचल शुरू हो गई। भाजपा ने कुमाऊं से मुख्यमंत्री के रूप में युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को आगे कर दिया है। खटीमा से विधायक धामी अब कुमाऊं और तराई दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के चयन में ही असमंजस को आगे बढ़ाकर प्रदेश अध्यक्ष पर नया दांव खेलने की कांग्रेस की कवायद के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी में नए सिरे से रणनीति पर मंथन प्रारंभ हो गया है।

भाजपा के भीतर तेजी से बदले समीकरणों का असर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने सियासी नफे नुकसान के तराजू पर तोलना शुरू कर दिया। भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को जिस तरह आगे बढ़ाया है, उससे विपक्षी खेमे में खलबली है। यह बात दीगर है कि भाजपा पर मुख्यमंत्री बदलकर प्रदेश को राजनीतिक अनिश्चितता के भंवर में झोंकने का आरोप लगा रही कांग्रेस अब खुद नए सिरे से सियासी समीकरण पर विचार करने को मजबूर हो गई है। पार्टी हाईकमान के नए सिरे से मशक्कत करने की वजह से आठ दिन से दिल्ली में डेरा डाले प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को अगले एक-दो दिन और वहीं टिके रहना पड़ सकता है।

प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के चयन और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के मामले में हफ्ते से ज्यादा समय गुजरने के बावजूद कांग्रेस फैसला नहीं ले पाई है। प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता में बैठी भाजपा से मुकाबले के लिए जिन समीकरणों के आधार पर बदलाव की पैरवी की जाती रही है, अब वे गड़बड़ा चुके हैं। भाजपा एक के बाद एक युवा चेहरों को आगे बढ़ा रही है। हरिद्वार से प्रदेश अध्यक्ष बना कर भाजपा पहले ही कांग्रेस को नए सिरे से सोचने को मजबूर कर चुकी है। बदली परिस्थितियों पर पार्टी की बारीक नजर है। पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने का कदम बढ़ा सकती है।

## बिहार में अफसरशाही से नाराज मंत्री मान गए सरकार से

राज्य ब्यूरो, पटना

- निजी यात्रा पर दिल्ली से ऋषिकेष गए मदन सहनी, आज लौटेंगे पटना
- बोले- सब कुछ सामान्य और शांत, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहेंगे और उनका निर्देश मानेंगे

बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी शनिवार को निजी यात्रा पर दिल्ली से ऋषिकेष चले गए। यह उनकी निजी यात्रा है और सोमवार को वह पटना लौट आएंगे। रविवार को उन्होंने कहा कि सब कुछ सामान्य और शांत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर वे अपनी बात कहेंगे। नीतीश कुमार अभिभावक हैं और उनका हर निर्देश उन्हें स्वीकार्य है।

राज्य में तैनात 134 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्थानांतरण के मुद्दे पर विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद के रवैये से मदन सहनी नाराज थे। एक जुलाई को उनकी पीड़ा छलक आई थी। सरकार में अफसरशाही के हावी होने की शिकायत के साथ उन्होंने पद छोड़ देने की इच्छा जताई थी।

**लालू से भेंट-मुलाकात की बात निराधार :** अब मदन सहनी संभवतः मान गए हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि यह अफवाह फैला दी गई कि मैं नाराज हूं और दिल्ली जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलूंगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगर मैं मंत्री नहीं भी रहता हूं, तो भी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में कुछ बोल देने का मतलब यह नहीं होता है कि मैं अपने नेता से नाराज हूं। नेता का जो निर्देश होगा, उस पर मुझे अमल करना है। अपने इस्तीफा की बात को टालते हुए उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री से मिलना है।

**नागवार गुजरी थी जीवेश की सलाह:** मदन सहनी की यह बात बता रही कि मध्यस्थता के बाद स्थिति बिगड़ने से बच गई है। हालांकि शनिवार को भाजपा कोटे के मंत्री जीवेश मिश्रा ने उन्हें अधिकारियों से तालमेल कर चलने की सलाह दी थी, जिस पर वे हत्थे से उखड़ गए थे। उन्होंने दो टूक कहा था कि मैं नेता हूं, दलाल नहीं कि तालमेल कर चलूं। हालांकि रविवार को भाजपा कोटे के ही एक दूसरे मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सहनी के जख्मों को सहलाने का उपक्रम किया।

## पारस व चिराग के बीच शक्ति-प्रदर्शन आज

**राज्य ब्यूरो, पटना :** सोमवार का दिन लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के लिए खास है। पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पटना में जगह-जगह होर्डिंग व बैनर-पोस्टर लग चुके हैं। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान सोमवार को पहली बार पटना आएंगे। एयरपोर्ट से वह हाजीपुर के सुल्तानपुर बस्ती में आयोजित जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। वहां से वह आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। उनके स्वागत में समर्थकों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। अच्छी-खासी संख्या में होर्डिंग और तोरणद्वार बनाए गए हैं। लोजपा (पारस गुट) के अध्यक्ष एवं संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जयंती समारोह की जोरदार तैयार की गई है। राजनीतिक गलियारे में दोनों गुट के इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

लोजपा (चिराग गुट) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान व प्रवक्ता राजेश भट्ट ने रविवार को बताया कि कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत कार्यक्रम तय किया गया है।

## विभिन्न दलों के नेताओं के बीच चल रहा है मुलाकातों का दौर

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति में विभिन्न दलों के राजनेताओं की गुप्त या प्रत्यक्ष मुलाकातों का दौर चल रहा है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का राग अलाप रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से 10 मिनट अकेले मिलने का वक्त निकाल लेते हैं। पिछले वर्ष देवेंद्र फड़नवीस एवं संजय राउत के बीच हुई लंबी मुलाकात सभी को याद है। और अब भाजपा नेता आशीष शेलार से संजय राउत की कथित गुप्त मुलाकात चर्चा में है। ऐसे में देवेंद्र फड़नवीस का यह कहना कि शिवसेना के साथ भाजपा की कोई शत्रुता नहीं है, राज्य में बदलते समीकरणों की ओर इंगित कर रहा है। लेकिन मानसून सत्र की अवधि सिर्फ दो दिन रखने के निर्णय की कड़ी भर्त्सना करते हुए फड़नवीस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष के सवालों से भाग रही है। यदि हमारे सवालों के जवाब हमें सदन में नहीं मिले, तो सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए भी भाजपा तैयार है।

## कार्यकर्ताओं की मेहनत से उप्र में सरकार बनाएगी कांग्रेस : प्रियंका

जासं, मथुरा

- राष्ट्रीय महासचिव ने वर्चुअल संबोधन के जरिये कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मनोबल
- आगरा और कानपुर मंडल के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर शुरू

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधानसभा चुनाव में जीत का पूरा दारोमदार कार्यकर्ताओं के कंधे पर रख दिया। रविवार से शुरू हुए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में वर्चुअल संबोधन में कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते ही कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की निरंतरता की प्रशंसा भी की।

वृंदावन में कानपुर और आगरा मंडल के जिला, महानगर, ब्लाक व मंडल अध्यक्षों का दो दिवसीय प्रशिक्षण रविवार से शुरू हुआ। पहले दिन प्रियंका ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। आप लोग लगातार गांव-गांव जाकर बूथ कमेटी, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत कमेटियों का गठन कर रहे हैं। ये 2022 में उप्र में कांग्रेस की सरकार बनाने की शुरुआत है। भगवा संगठनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा, आरएसएस अपनी सरकार के कुशासन व भ्रष्टाचार को छिपाते हुए देश की जनता को झूठी बातों के जरिये भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों का प्रचार-प्रसार कर जनता का भ्रम दूर करना होगा।

**कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में महिला नेता का हंगामा :** कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन ही रविवार को हंगामा हो गया। एक महिला नेता ने दो पदाधिकारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। प्रशिक्षण शिविर में रविवार को कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका वर्चुअल संबोधन कर रही थीं। इसी दौरान महिला कांग्रेस की पश्चिमी उप्र अध्यक्ष प्रीति तिवारी पहुंचीं। आरोप है कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित व सचिव योगेश तालान ने उनका कंधा पकड़कर रोक दिया। प्रीति ने इस पर हंगामा कर दिया।

## लोस में पार्टी के नेता पद से अधीर को हटाने की आई खबर, कांग्रेस ने बताया बेबुनियाद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता



बंगाल में भी पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई फैसला नहीं

- जी-23 के कुछ नेताओं ने सोनिया को पत्र लिखकर संगठन में बदलाव का किया था अनुरोध

अधीर रंजन चौधरी को लेकर रविवार को खबर आई कि लोकसभा में नेता पद से कांग्रेस उन्हें हटाने वाली है। इस बीच कयास लगाए जाने लगे कि क्या लोकसभा में कांग्रेस नया नेता चुनने वाली है? क्या अधीर रंजन चौधरी का पत्ता सच में कटने वाला है? इन तमाम सवालों का पार्टी ने शाम होते-होते जवाब दे दिया। लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की खबरों को पार्टी ने समय से पहले और बेबुनियाद बताया है। पार्टी की तरफ से रविवार को कहा गया कि अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने को तैयार है।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व बदलने की खबरें समय से पहले और निराधार हैं। हालांकि, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ब्रीफिंग में पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया।

सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता के तौर पर अधीर को बदलने के संबंध में शीर्ष स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अधीर कांग्रेस की बंगाल इकाई के अध्यक्ष भी हैं। बंगाल में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। अलबत्ता, जी-23 के कुछ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बदलाव का अनुरोध जरूर किया था।

इससे पहले मीडिया में इस तरह की खबरें आई थीं कि कांग्रेस लोकसभा में पार्टी के नेता को बदलने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बारे में जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। इसके तहत अधीर रंजन चौधरी को हटाकर लोकसभा में किसी और दिग्गज नेता को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है।

## पुनर्मतगणना की मांग को लेकर अब भाजपा के आठ नेता पहुंचे हाई कोर्ट

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता :** बंगाल में पुनर्मतगणना की मांग को लेकर भाजपा के आठ नेता कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव हारे हुए इन नेताओं ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्मतगणना की मांग की है।

भाजपा नेता कल्याण चौबे ने मानिकतला विस सीट पर दोबारा गिनती की मांग की है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं, जो अपनी हारी हुई सीट पर दोबारा मतगणना की मांग कर रहे हैं। भाजपा नेता विश्वनाथ बनर्जी ने विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दोबारा गिनती की मांग की है। दूसरी ओर से जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रहे सुजीत सिन्हा भी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं।

## बंगाल में टीएमसी के दो कार्यकर्ताओं से मारपीट, फायरिंग भी की

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता :** बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो कार्यकर्ताओं से उपद्रवियों ने मारपीट की है। इसके साथ ही शहर के उत्तर में बाहरी इलाके में स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर हवा में गोली चलाई। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे 10 से 12 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर उत्तर 24 परगना के बेलघरिया में तृणमूल कांग्रेस के देशप्रियनगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। यहां रखे फर्नीचर में तोड़फोड़ की और दो कार्यकर्ताओं को मारा। उनको रिवाल्वर के हत्थे से मारने से पहले खींच कर कार्यालय से बाहर ले आए। इसके बाद उपद्रवियों ने हवा में गोली चलाई और दोनों घायलों को सड़क पर छोड़ मौके से फरार हो गए। तृणमूल कांग्रेस ने हमले के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों से इन्कार किया है।

## बंगाल में भाजपा का कड़ा संदेश- खुद को पार्टी से ऊपर नहीं समझें विधायक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कोलकाता में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष ने विधायकों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विधायक बनने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को पार्टी से ऊपर समझ लें। खुद को पार्टी से ऊपर नहीं समझें। विधायकों को लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहना होगा।

प्रदेश भाजपा की ओर से शनिवार को कोलकाता स्थित हेस्टिंग्स कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें नवनिर्वाचित विधायकों को किस तरह विधानसभा में अपनी भूमिका का पालन करना है, समेत विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भाजपा विधायकों को विधानसभा के अंदर और बाहर जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समर्थन में आवाज उठाते रहना होगा। भाजपा को पूरी ईमानदारी के साथ विरोधी दल का कर्तव्य निभाना होगा।

### अनुमति नहीं मिलने के बावजूद घेराव करेगी भाजपा

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता :** बंगाल प्रदेश भाजपा ने फर्जी टीकाकरण मामले के खिलाफ सोमवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के मुख्यालय घेराव का आह्वान किया है, जबकि कोलकाता पुलिस ने कोरोना महामारी और लाकडाउन की दुहाई देते हुए इसकी अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। हालांकि, पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भाजपा केएमसी घेराव को लेकर अडिग है।

रविवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने स्पष्ट कहा कि हर हाल में घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस अपना काम करेगी और भाजपा अपना काम। वहीं, प्रदेश भाजपा ने एक बयान जारी कर कहा है कि सोमवार दोपहर एक बजे भाजपा कार्यकर्ता सुबोध मल्लिक स्क्वायर के पास एकत्रित होंगे और वहां से कोलकाता नगर निगम मुख्यालय की ओर मार्च करेंगे।

## एनएचआरसी की समिति करेगी मालदा व मुर्शिदाबाद का दौरा

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता :** बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति छह से आठ जुलाई तक मालदा और मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेगी।

जानकारी के अनुसार समिति में शामिल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद समेत अन्य सदस्य छह व सात जुलाई को मालदा, जबकि आठ को मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान पीड़ितों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले आयोग की समिति ने 29 जून को बंगाल के विभिन्न हिंसा प्रभावित इलाकों का अपना दौरा खत्म किया था और 30 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। दो जुलाई को कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पुलिस को सभी हिंसा पीड़ितों की शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया था।

**कवायद**

कलेक्टर की अध्यक्षता में सरकार ने बनाई सर्वेक्षण समिति, पहले ही हो चुका है आयोग का गठन

## छग में फिर बजा ओबीसी आरक्षण का झुनझुना

नईदुनिया, रायपुर

### राशनकार्ड के आधार पर जुटाई जाएगी जाति की जानकारी

अधिकारियों के अनुसार जाति और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का डाटा राशनकार्ड के आधार पर एकत्र करने की कोशिश की जा रही है। राज्य में करीब 68 लाख 15 हजार से ज्यादा राशनकार्ड हैं। इसमें 32 लाख ओबीसी वर्ग के हैं। यह संख्या लगभग 47 फीसद है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होते ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का सियासी झुनझुना फिर से बजने लगा है। सरकार ने जातिगत आरक्षण तय करने की कवायद शुरू की है। इसके लिए जिला और नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे की जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सौंपी गई है। इस मामले में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र जज छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत सिंह के अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति में कुल पांच लोग रखे जाएंगे। इनमें ओबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। इन दोनों को कलेक्टर नामांकित करेंगे। ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति समिति का सदस्य सचिव होगा। दरअसल, प्रदेश में धर्म से ज्यादा जाति की सियासत हावी है। राज्य की 90 में से 10 सीट अनुसूचित जाति (एससी) और 29 सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं। बाकी 51 सीटें सामान्य के लिए हैं। इन सीटों पर ओबीसी वर्ग के वोटर प्रभावी भूमिका में हैं। इसकी वजह यह है कि राज्य की कुल आबादी में से 47 फीसद ओबीसी हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश में जातिगत आरक्षण में बदलाव की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त, 2019 को की थी। इसके तहत एसटी को मिलने वाले 32 फीसद आरक्षण को यथावत रखा गया था। एससी का आरक्षण 12 से बढ़ाकर 13 व ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसद कर दिया गया था। बाद में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था और जोड़ दी।

**कोर्ट में लंबित है मामला :** आरक्षण में किए गए बदलाव की वजह से राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़कर 82 फीसद पहुंच गया। यह 50 फीसद आरक्षण के तय मापदंड से अधिक है। इस वजह से सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में की गई वृद्धि पर रोक लगा दी। इसके बाद राज्य में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोरों की सही संख्या जानने के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है।

## सचिन पायलट के समर्थन में हुई महापंचायत

**जागरण संवाददाता, गुरुग्रामः** राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थन में गुर्जर महापंचायत नामक संगठन की ओर से रविवार को गांव रिठौज में हुई महापंचायत में हरियाणा के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान से भी गुर्जर समाज के प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में सभी ने एक सुर से कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट की वजह से ही कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया फिर आगामी 10 फरवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. राजेश पायलट की जयंती पर जयपुर में राष्ट्रीय किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उसमें देश के कोने-कोने से किसान पहुंचेंगे।

महापंचायत को संबोधित करते हुए गुर्जर महापंचायत के संयोजक, किसान नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराम खटाना ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

## पीडीपी नेताओं से सरकारी आवास खाली कराए जाने से महबूबा बेचैन

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को आरोपों से भरा पत्र लिखा
- कहा- पीडीपी नेताओं को चिह्नित कर आवास छोड़ने का दबाव डाल रहा प्रशासन

श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेताओं से सरकारी आवास खाली कराए जाने के मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती परेशान हो उठी हैं। इस बेचैनी को आरोपों में तब्दील करते हुए महबूबा ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनकी पार्टी के नेताओं और पूर्व विधायकों को चिह्नित कर उनसे श्रीनगर में सरकारी आवास खाली करने के लिए दबाव डाल रहा है।

उपराज्यपाल को लिखे पत्र में महबूबा ने आरोप लगाया है कि सिर्फ पीडीपी के नेताओं को बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिए सरकारी आवास खाली करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय जब कश्मीर में आतंकी घटनाएं फिर से बढ़ी हैं, ऐसे में पार्टी नेताओं से आवास खाली करवाना सही नहीं है। जब यह नेता ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं तो उसे भी ठुकराया जा रहा है। इसका कारण यह नेता ही जानते हैं। प्रशासन आतंकियों के होने की बात भी कहता है और सुरक्षा देने से भी इन्कार कर देता है। प्रशासन जानबूझकर उनके नेताओं की जान रिस्क पर लगा रहा है। पत्र में लिखा गया है कि यह हर कोई जानता है कि हाल ही में आतंकियों ने चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमले किए हैं। जब उनके पास सुरक्षा नहीं होगी तो उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। पीडीपी के पूर्व विधायक जहूर मीर भी आतंकियों के शिकार हुए।

**160** नक्सली मारे गए हैं पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ समेत अलग-अलग राज्यों में। इनमें अकेले दंडकारण्य क्षेत्र के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले सर्वाधिक 101 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने पर्चा जारी कर यह बात मानी है।



## न्यूज गैलरी

### स्टैच्यू आफ यूनिटी के पास झील से 194 मगरमच्छ हटाए

**अहमदाबाद :** गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू आफ यूनिटी के पास स्थित झील से निकालकर पिछले दो वर्षों में कम से कम 194 मगरमच्छों को दूसरी जगह भेजा गया है। ऐसा पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। वर्ष 2019 में गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जीएसएफडीसी) ने इस झील में नौकायान की शुरुआत की है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि केवड़िया में सरदार वल्लभ पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के पास पंचमुली झील है। पर्यटकों में वह काफी लोकप्रिय है, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। केवड़िया क्षेत्र के वन अधिकारी विक्रमसिंह गभानिया ने बताया, '2019-20 (अक्टूबर-मार्च) में 143 मगरमच्छों को दूसरी जगह पहुंचाया गया। 2020-21 में 51 और मगरमच्छों को गांधीनगर व गोधरा के बचाव केंद्रों में भेजा गया है।' (प्रेट्र)

### एनआइए ने गैंगस्टर रिंकू बीहला के घर की ली तलाशी

**बरनाला :** करीब आठ साल से कनाडा में रह रहे गैंगस्टर चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बीहला के संबंध खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से उजागर होने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम ने उसके घर में सात घंटे छानबीन की और स्वजनों से पूछताछ की। रविवार सुबह करीब सात बजे एनआइए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ गांव बीहला स्थित गैंगस्टर रिंकू बीहला के घर पहुंची। टल्लेवाल के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर कृष्ण सिंह ने बताया कि जांच टीम ने दोपहर दो बजे तक चरणजीत के भाई और मौजूदा सरपंच किरणजीत सिंह मिंटू बीहला व उसकी माता से भी पूछताछ की व समूचे घर की तलाशी ली। (जासं)

### कफील को दिल्ली ले गई एनआइए, सलीम का जेल में हो रहा इलाज

**पटना :** दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में शामली से गिरफ्तार दो आतंकियों में से कफील को रविवार की सुबह एनआइए की टीम रिमांड पर लेकर दिल्ली चली गई है। वहीं, तबीयत खराब होने से सलीम को बेउर जेल में ही रखा गया है। सलीम का यूरीन डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। उसे देर रात को बेउर जेल के अस्पताल के सेल में भर्ती कराया गया था। जेल के डाक्टरों ने इलाज कर यूरीन डिस्चार्ज करवाया। अब तबीयत में सुधार है। हालांकि, यूरीन के रास्ते ब्लड आने की शिकायत है। दवाएं चल रही हैं। जेल प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन आतंकी सलीम को लेकर एहतियात बरत रहा है। हर हाल में उसका इलाज जेल हास्पिटल में ही करवाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाई गई है। (जासं)

### गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों ने शाह से की मुलाकात

**नई दिल्ली :** कश्मीर में दो सिख लड़कियों का जबरन मतांतरण कराकर निकाह की घटना सामने आने के बाद कश्मीर की आल सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। 29 जून को सिख प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी से भी मुलाकात की थी और उन्हें कश्मीर में सिख लड़कियों के कथित जबरन मतांतरण और निकाह को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में भी मतांतरण विरोधी कानून की मांग की थी। (एएनआइ)

### उत्तर प्रदेश में एक दिन में रोपे गए 25.51 करोड़ पौधे

**लखनऊ :** उप्र के सीएम का 'एक व्यक्ति, एक पौधा' अभियान रविवार को जनांदोलन बन गया। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया की तर्ज पर शाम तक प्रदेश में कुल 25.51 करोड़ पौधे रोपे जा चुके थे। अभियान की अगुआई करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुलतानपुर में पौधे रोपे। इसी के साथ योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे रोपने का कीर्तिमान भी बनाया। (राब्यू)

# नाम बदलकर पूर्व आइएएस अधिकारी की बेटी से की शादी

**लव जिहाद** ▶ होटल संचालिका के पति की मृत्यु होने पर युवक ने 2010 में नाम बदलकर जाल में फंसाया

### असलियत सामने आने पर एक वर्ष बाद दबाव बनाकर कराया मतांतरण, गिरफ्तार

**जागरण संवाददाता, आगरा**

आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। लखनऊ के मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर रिटायर्ड आइएएस अधिकारी की विधवा बेटी से 2010 में आर्य समाज पद्धति से शादी कर ली। एक साल बाद असलियत सामने आने पर दबाव बनाकर उसका अजमेर में मतांतरण करा दिया। साथ ही शादी के ग्यारह वर्ष तक महिला का उसके पूर्व पति के होटल में रहकर शारीरिक व मानसिक शोषण करता कहा। शनिवार को मारपीट करने पर पीड़िता ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला के चाचा भी उप्र पुलिस विभाग में उच्च पद पर रहे हैं, वर्तमान में राजनीतिज्ञ हैं।

महिला की पूर्व में आगरा के एक प्रतिष्ठित परिवार में शादी हुई थी। 2005 में उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद महिला ससुर व बेटी के नाम होटल को संचालित करने लगी। महिला के पिता का भी देहांत हो चुका है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, महिला को 2010 में लखनऊ में आयोजित एक पार्टी में जाना पड़ा था। जहां उसकी मुलाकात लखनऊ के राजाजी पुरम ताल कटोरा निवासी आरिफ हाशमी से हुई थी। आरिफ ने अपना नाम आदित्य आर्य और खुद को टिंबर का बड़ा कारोबारी बताया और महिला को अपने साथ कारोबार करने का झांसा दिया। इसी बहाने वह आगरा में महिला के घर आने लगा। एक दिन किसी पार्टी में आरोपित ने महिला के टीका लगाते हुए योजनाबद्ध तरीके से फोटो खिंचा लिया, जिसमें वह मांग भरता प्रतीत हो रहा है। इस फोटो से बदनाम करने का डर दिखाकर वह समय-समय पर धन ऐंठने लगा। आरोपित ने दबाव बनाकर महिला से आर्यसमाज पद्धति से शादी कर ली। एक वर्ष बाद असली नाम आरिफ हाशमी पता चलने पर आरोपित ने महिला से भी मतांतरण करने को कहा। घर में रखा मंदिर भी फेंक दिया। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा। दबाव बनाकर अजमेर ले जाकर मतांतरण करा लिया और महिला का नाम आइशा हाशमी रख दिया। आरिफ से शादी होने के बाद भी महिला यहां पूर्व ससुराल में रहती रही। उसके साथ आरिफ भी होटल में ही रहने लगा। आरिफ ने महिला से होटल से होने वाली कमाई भी हड़प ली और महिला को यातनाएं देने लगा। महिला की लखनऊ में रहने वाली मां को जान से मारने की धमकी देता था। शनिवार को मारपीट करने पर महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी, विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्जकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर सदर अजय कौशल ने बताया कि आरोपित को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

### आरिफ का उमर गौतम से कनेक्शन तलाश रही एटीएस

रिटायर्ड आइएएस की बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाने वाला आरिफ हाशमी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। वह नाम बदलकर शादी करता था, फिर युवती का मतांतरण करा देता था। गोरखपुर और आगरा के दो मामले सामने आ चुके हैं। कई अन्य युवतियों के भी इसके जाल में फंसने की आशंका है। मतांतरण का गैंग चलाने वाले उमर गौतम से कनेक्शन की आशंका पर आरिफ से एटीएस की टीम ने भी सदर थाने में पूछताछ की। अभी उसके बारे में और छानबीन की जा रही है। मूलरूप से गोरखपुर के तिवारीपुर के रहने वाले आरिफ हाशमी ने पुलिस को बताया कि 25 वर्ष पहले उसने गोरखपुर की हिंदू युवती से राणा सिंह


लव जिहाद का आरोपित आरिफ। जागरण

बनकर दोस्ती की थी। उससे आर्य समाज पद्धति से शादी कर ली। युवती का मतांतरण करा दिया। बेटा पैदा होने पर उसका नाम अजमत हाशमी रखा। छह वर्ष बाद युवती को तलाक दे दिया, लेकिन इसके गोरखपुर स्थित घर पर ही रहता है। वहां भाई और मां के भी रहने के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। आरिफ खुद लखनऊ आकर रहने लगा। उसने पुलिस को बताया कि पहली पत्नी से तलाक होने के बाद आगरा की होटल संचालिका और रिटायर्ड आइएएस अधिकारी की बेटी को उसने लखनऊ में एक पार्टी में आदित्य आर्य बनकर जाल में फंसाया। अभी आरिफ ने केवल दो युवतियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने की बात कुबूली है। छानबीन में पुलिस को जानकारी मिली है कि अब तक वह पांच-छह युवतियों को फंसा चुका है।

### अपनी अमीरी दिखाकर लोगों को मतांतरण के लिए उकसाता था उमर गौतम

**आशुतोष गुप्ता, गाजियाबाद :** गाजियाबाद के मसूरी स्थित डासना देवी मंदिर में दो संदिग्धों विपुल विजयवर्गीय उर्फ रमजान, कासिफ व इन्हें मंदिर में भेजने वाले सलीमुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद हुए मतांतरण गिरोह के पर्दाफाश होने के बाद लगातार अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। मतांतरण गिरोह के मुख्य सूत्रधार उमर गौतम के पकड़ में आने के बाद साजिश की अब परत-दर-परत खुलने लगी हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में उजागर हुआ है कि उमर गौतम अपनी करोड़ों रुपये की संपत्ति दिखाकर लोगों को मतांतरण के लिए उकसाता था। वह लोगों से कहता था कि मेरे पास जो कुछ भी है, वह मतांतरण के बाद ही मिला है। इस तरह का लालच देकर वह लोगों को मतांतरण के लिए ब्रेनवाश करता था। मतांतरित हुए कई लोगों से पूछताछ में भी इसी तरह की बात सामने निकलकर आई हैं कि उमर ने अमीरी का ख्वाब दिखाकर ही उनका ब्रेनवाश किया था।

दरअसल, उमर गौतम ने कई दशक पहले मतांतरण कर मुस्लिम महिला से निकाह कर लिया था। इसके बाद से ही वह मतांतरण की मुहिम से जुड़ गया।

### लव जिहाद व मतांतरण के खिलाफ भरी हुंकार

**जागरण संवाददाता, पटौदी (गुरुग्राम) :** रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में लव जिहाद व मतांतरण के खिलाफ जोरदार आवाज उठी। महापंचायत में शामिल लोगों ने कहा कि लव जिहाद व मतांतरण के आरोपितों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मतांतरण से इलाके की संस्कृति बदल जाती है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने एक सुर से जनसंख्या नियंत्रण कानून एवं समान नागरिक संहिता बनाने की मांग की।

भारतीय किसान संघ के हरियाणा अध्यक्ष मास्टर ओम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद एवं करणी सेना सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही आसपास के इलाके के सैकड़ों लोग शामिल हुए। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि एक समुदाय विशेष के लोग डर, छल व लालच आदि के माध्यम से मतांतरण करवा देते हैं। इसके लिए विदेश से भी पैसा आ रहा है। सरकार ऐसे मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराए।

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि वे सभी धर्मों का आदर करते हैं, परंतु हिंदू बहन-बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

# कल्याण सिंह की हालत गंभीर, एसजीपीजीआइ में किए गए भर्ती

**जागरण संवाददाता, लखनऊ**

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को स्थिति गंभीर होने के बाद शनिवार शाम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) में भर्ती करा दिया गया है। पांच विभागाध्यक्षों की निगरानी में उन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन (सीसीएम) में रखा गया है। एसजीपीजीआइ शिफ्ट कराए जाने से पहले सुबह से शाम तक लखनऊ स्थित लोहिया संस्थान जाकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका हालचाल जाना।

एसजीपीजीआइ के निदेशक प्रो. डा. आरके धीमन ने बताया कि कल्याण सिंह की तबीयत स्थिर है। उन्हें सीसीएम में रखा गया है। उनकी सेहत की निगरानी के लिए सीसीएम के विभागाध्यक्ष प्रो. डा. बनानी प्रसाद, न्यूरोलाजी के विभागाध्यक्ष डा. सुनील प्रधान, एंडोक्राइनोलाजी के विभागाध्यक्ष डा. ईश भाटिया, नेफ्रोलाजी के विभागाध्यक्ष प्रो. डा. नारायण प्रसाद, व कार्डियोलाजी के प्रो. डा. पीके गोयल की टीम बनाई गई है।


पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एएनआइ

**सबसे पहले लोहिया संस्थान पहुंचे थे योगी :** शनिवार सुबह 10 बजे सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह का हालचाल लेने लोहिया संस्थान पहुंचे। उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। इसके बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी संस्थान पहुंचकर उनकी सेहत के बारे में डाक्टरों से जानकारी ली। सीएम योगी ने कल्याण सिंह से पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है, मगर उनकी स्मरण शक्ति काम नहीं कर रही थी। उन्होंने जब कोई रिस्पांस नहीं दिया तो सीएम ने संस्थान की निदेशक डा. सोनिया नित्यानंद व उनका इलाज कर रहे चिकित्सा अधीक्षक डा. विक्रम सिंह से उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उनके पौत्र से भी बातचीत की। कल्याण सिंह को कुछ दिनों पहले ही पैरोटिल ग्लैंड (लार ग्रंथि) में सूजन व संक्रमण के बाद यहां भर्ती कराया गया था। लोहिया संस्थान के प्रवक्ता डा. श्रीकेश सिंह ने बताया कि 21 जून को अनियंत्रित ब्लड शुगर एक्यूट बैक्टीरियलपैरोटिसिस इत्यादि की शिकायत के साथ उन्हें भर्ती कराया गया था। दवाओं से उन्हें आराम हो गया था, मगर सीटी स्कैन करने पर उनके दिमाग में खून का थक्का पाया गया। इसके बाद तीन जुलाई की रात बीपी अधिक बढ़ने से माइनर हार्ट अटैक भी पड़ गया, जिससे स्थिति गंभीर हो गई।

**शनिवार रात करीब एक बजे हुआ हृदयाघात :** लोहिया संस्थान के एमएस डा. विक्रम सिंह ने बताया कि लार ग्रंथि की समस्या तो ठीक हो गई, मगर शनिवार रात करीब एक बजे उन्हें हृदयाघात हो गया। इससे पहले अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उन्हें माइनर ब्रेन स्ट्रोक भी हो गया था, जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उनका यूरिया व क्रिटनिन भी बढ़ा हुआ है।

# हिंदू लड़की का कराया जा रहा था निकाह, पुलिस ने रुकवाया

▶ गुजरात के वड़ोदरा की रहने वाली है युवती, आरोपित हिरासत में

**जागरण संवाददाता, पीलीभीत**

गुजरात में रहने वाली हिंदू लड़की को दूसरे संप्रदाय का आरिफ अपने गांव ले गया। रविवार को वह निकाह करने जा रहा था, इतने में पुलिस पहुंच गई। देर शाम दोनों से पूछताछ की जा रही। गुजरात पुलिस से भी संपर्क कर दोनों के बारे में मालूम किया जा रहा है।

पीलीभीत (उप्र) के बीसलपुर के मुहल्ला गयासपुर निवासी आरिफ गुजरात के वड़ोदरा में काम करता था। काफी समय वह वहां रहा। 10 जून को वहां से हिंदू लड़की को अपने साथ ले आया। शनिवार तक वह उसी के घर में थी। रविवार को वह लड़की को लेकर सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव कजरी निरंजनपुर गौटिया में रिश्तेदार के घर पहुंचा। शाम को आरिफ उस लड़की से निकाह करने जा रहा था। किसी ने थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी को फोन कर दिया। वह मौके पर पहुंचे तो आरिफ दूल्हा बना तैयार था। पुलिस ने आयोजन रोका और दोनों को थाने ले आई।

> लड़की के बारे में वड़ोदरा पुलिस व उसके स्वजन से जानकारी मांगी गई है। उसके स्वजन के बयान के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी।
> -किरीट कुमार राठौर, एसपी

पुलिस का कहना है कि लड़की मर्जी से साथ आने की बात कह रही है, मगर दोनों की रजामंदी थी तो निकाह के लिए यहां क्यों आए, इसकी जांच की जा रही। वड़ोदरा पुलिस से अफसरों से संपर्क किया तो पता चला कि लड़की अपने मामा, मामी के घर रहती थी। उसके परिवार के बारे में और जानकारी मांगी गई है।

पुलिस का कहना है कि लड़की अपनी उम्र 21 साल बता रही, मगर कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए उसके स्वजन को बुलाया गया है। उनसे बातचीत के बाद जरूरत हुई तो लड़की के कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे।

# हिरासत में मौत के आरोपित पुलिसकर्मियों को जेल भेजने में 24 साल का संघर्ष

**मोहम्मद रफीक, भोपाल**

▶ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफनाक अमानवीय चेहरा आया सामने

मध्य प्रदेश पुलिस की अमानवीयता ने बनारस जिले (उत्तर प्रदेश) के एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस गलती पर पर्दा डालती रही। सिस्टम इस हद तक जटिल बना रहा कि जिन पुलिसकर्मियों पर उनकी हिरासत में एक निर्दोष व्यक्ति की मौत का आरोप था, उन्हें जेल तक पहुंचाने में 24 साल लग गए। केस अभी खत्म नहीं हुआ है, आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं। यह राहत भी पिछले माह सुप्रीम कोर्ट से मिली है। अब मध्य प्रदेश की शहडोल पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत पर आगे की सुनवाई होगी। इस मामले के आरोपित कोतवाली शहडोल के तत्कालीन थाना प्रभारी आर. राजन (अब सेवानिवृत्त डीएसपी), उपनिरीक्षक शंखधर द्विवेदी (वर्तमान में निरीक्षक जिला सिंगरौली), जगत सिंह व शेर अली अब बनारस जिला जेल में बंद हैं।

गौरतलब है कि 27 फरवरी, 1997 की शाम ग्राम कुंआर बाजार थाना फूलपुर, जिला बनारस में शहडोल के पुलिसकर्मी ट्रक मालिक ओमप्रकाश गुप्ता को तलाश करते हुए पहुंचे थे। ओमप्रकाश अगले दिन घर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें ट्रांसपोर्टर सुरेश अग्रवाल द्वारा की गई कुछ कागजात चोरी की शिकायत पर हिरासत में ले लिया और शहडोल रवाना हो गए। ओमप्रकाश के पुत्र संजय गुप्ता ने बनारस के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को उसी दिन दोपहर साढ़े 12 बजे टेलीग्राम से घटना की सूचना दी थी। परिवार को दो मार्च, 1997 को ओमप्रकाश की हार्ट अटैक से मौत का पता चला। संजय गुप्ता शहडोल पहुंचे तो उन्हें शव बनारस नहीं ले जाने दिया गया। शहडोल में ही उनका जबर्दस्ती अंतिम संस्कार करा दिया गया। संजय का आरोप है कि पिता के शरीर पर चोट के कई निशान थे। संजय के मुताबिक उनके पिता को गोरखनाथ नामक व्यक्ति होने के शक में हिरासत में लिया गया था।

संजय गुप्ता ने बताया कि पिता की मौत के मामले में उच्चस्तरीय जांच के लिए मैं कई बार शहडोल आया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बनारस में भी पुलिस के आलाधिकारियों से गुहार काम नहीं आई। इसके बाद चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) बनारस की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर आर. राजन, शंखधर द्विवेदी, दिग्विजय पांडेय, जगत सिंह, ट्रांसपोर्टर सुरेश अग्रवाल व स्वामीनाथ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने कुछ दिन में ही खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी। इसके बाद वर्ष 1998 में पुनः सीजेएम कोर्ट की शरण ली। कानूनी प्रक्रिया चलती रही और इसी बीच आरोपित पुलिसकर्मियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। आखिरकार वर्ष 2018 में संजय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 23 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टे पर रोक लगाई और इन्हें बनारस न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया।

# कश्मीर में नई चुनौती बने हाइब्रिड आतंकी

**राज्य ब्यूरो, जम्मू**

सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ पर लगभग पूर्णविराम और कश्मीर के भीतरी इलाकों में सुरक्षाबलों के दबाव के चलते घाटी में सक्रिय आतंकी जान बचाने के लिए अपने ठिकानों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सुरक्षाबलों के पास इन आतंकियों की पूरी कुंडली होती है, इसलिए जैसे ही वे अपनी मांद से बाहर आते हैं तो या तो पकड़ लिए जाते हैं या फिर ढेर कर दिए जा रहे हैं। इससे हताश आतंकियों के आकाओं ने कश्मीर में नई साजिश रची है। हमलों के लिए अब वे हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

दरअसल, ये आतंकी गुमराह किए गए युवा होते हैं, जिन्हें कोई लक्ष्य दिया जाता है। ये न तो पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की सूची में शामिल हैं और न ही इनकी किसी को भनक होती है। आतंकवादी इनका इस्तेमाल हमला करवाने के लिए करते हैं। हमले के बाद ये फिर से सामान्य जीवन की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। एक तरह से इन्हें भाड़े के शूटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गत दो माह में श्रीनगर में हुई आतंकी वारदात इसी साजिश का हिस्सा हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हाइब्रिड आतंकी बने इन युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काया जाता है। इनके हैंडलर इनका इस्तेमाल वारदातों के लिए करते हैं। जब यह कोई वारदात अंजाम देकर लौटते हैं तो फिर दूसरा काम के लिए इंतजार करने को कहा जाता है। इस दौरान वे सामान्य कामकाज करते हैं।

> श्रीनगर शहर में कुछ स्लीपर सेल और जिहाद के नाम पर गुमराह हाइब्रिड आतंकी हैं। आतंकियों के इस माड्यूल को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। कुछ स्लीपर सेल हैं जिन्हें हम हाइब्रिड आतंकी भी कहते हैं। हाइब्रिड आतंकियों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम निगरानी कर रहे हैं। इनका भी जल्दी पता लगाया जाएगा।
> -विजय कुमार, आइजीपी, कश्मीर

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकी जिसे लक्ष्य बनाते हैं, उसकी पूरी मूवमेंट को देखते हैं और कमजोर हिस्से को ढूंढ़ते हैं। ऐसा करने वाला ओवरग्राउंड वर्कर या फिर पार्ट टाइम आतंकी हो सकता है। ऐसा हाइब्रिड आतंकी जो पुलिस सूची में नहीं है, लेकिन उसके पास एक पिस्तौल है और मारने का इरादा है। एक भाड़े के शूटर की तरह एक लक्ष्य को मारने के लिए ऐसे हाइब्रिड आतंकियों को भुगतान भी किया जाता है। इसमें केवल मरने वालों की संख्या देखी जाती है और इसके अलावा कोई चीज मायने नहीं रखती है।

अधिकारियों का कहना है कि यह सब पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ की साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में साफ्ट टारगेट पर पिस्टल से हमला करने को प्राथमिकता में रखा गया है। जो निहत्थे हैं और जवाबी कार्रवाई की उनसे संभावना नहीं है।

## स्मृति शेष

**मानव को आजीवन निरोगी बनाने के लिए डा. लालजी सिंह ने रखी जीन आधारित निदान करने की परिकल्पना, 2004 में जीनोम कुंडली पर शुरू किया काम, जर्नल 'नेचर' में शोधपत्र छपने के बाद गई दुनिया की नजर**

# ...जिन्होंने आनुवंशिक रोगों के निदान की दी तकनीक

**हिमांशु अस्थाना, वाराणसी**

इंसान को जीवनकाल में छोटी-बड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ आनुवंशिक रोग कम उम्र में मौत का कारण बन जाते हैं या जीवन भर के लिए दिव्यांग बना देते हैं। बच्चे के जन्म से पहले ही उसे भविष्य में होने वाली जानलेवा व्याधियों का डाटा तैयार कर जीनोम पत्री (कुंडली) का सिद्धांत दुनिया को सबसे पहले भारत ने दिया था। इसके अगुआ थे देश में डीएनए फिंगर प्रिंट के जनक डा. लालजी सिंह।

व्यक्ति को आजीवन रोगमुक्त रखने की जीन आधारित उपचार की विधा पर प्रतिष्ठित जर्नल नेचर में डा. सिंह के पांच शोधपत्र प्रकाशित हुए थे। उन्होंने नवजात की जीवन संभाव्यता यानी अधिकतम आयु निर्धारण का तरीका बताया। हर व्यक्ति के जीनोम के आधार पर उसके लिए विशेष दवाएं बनाने का विचार दिया। 2008 में अमेरिका की हावर्ड यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने डा. सिंह से संपर्क कर जीन आधारित निदान पर नेचर में शोधपत्र प्रकाशित कराया। डा. सिंह के शिष्य व बीएचयू के जीन विज्ञानी प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि यूरोप और अमेरिका ने डा. लालजी सिंह के बाद 2005 में इस तकनीक पर काम शुरू किया। इजरायल व यूरोपीय देश एस्टोनिया तो मुफ्त में हर बच्चे की जीनोम कुंडली बनाते हैं। डा. चौबे के मुताबिक न्यूरो संबंधी समस्याओं के लक्षण व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं और इनकी पहचान मुश्किल होती है, जबकि जीन के स्तर पर आसानी से पहचान कर इलाज संभव है। इस आधार पर ही डा. सिंह ने 'पर्सनलाइज्ड मेडिसिन' टर्म का ईजाद किया। इसके बाद दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हुई। इस सिद्धांत में मां के गर्भ से जीन सैंपल की सिक्वेंसिंग कर तमाम रोगों का डाटा तैयार करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता भी मानव जीन के आधार पर तय हो रही है। जीनोम पत्री से पता चल जाएगा कि नवजात को कोविड संक्रमण का कितना खतरा है।

जीनोम फाउंडेशन, जौनपुर के प्रमुख डा. आशीष सिंह ने बताया कि जीनोम डाटा कुंडली से व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के साथ ही जीवन गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। जीनोम फाउंडेशन की स्थापना डा. सिंह ने इस मकसद से की थी कि दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बीमारियों का आनुवंशिक निदान किया जा सके। इसके लिए 2004 में हैदराबाद व जौनपुर के कलवारी गांव में केंद्र स्थापित किया।

**डा. लालजी सिंह की जयंती पर विशेष**

**जन्म :** पांच जुलाई, 1947 (जौनपुर)

**निधन :** 10 दिसंबर, 2017 (वाराणसी)

**2004** में पद्मश्री से सम्मानित

**2011-14** तक बीएचयू के कुलपति रहे


डा. लालजी सिंह के प्रतिष्ठित जर्नल नेचर में पांच शोधपत्र प्रकाशित हुए थे। फाइल/इंटरनेट मीडिया

### जम्मू फोरेंसिक विभाग में बैलेस्टिक एक्सपर्ट तक नहीं

**अवधेश चौहान, जम्मू :** जम्मू फोरेंसिक विभाग साइंटिफिक एक्सपर्ट की कमी से जूझ रहा है। आलम यह है कि जम्मू या उसके आसपास के क्षेत्र में अगर आतंकी किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो विभाग के पास न तो एक्सप्लोसिव और न ही बैलेस्टिक एक्सपर्ट है। इसके लिए दिल्ली सहित अन्य राज्यों से विशेषज्ञ आने का इंतजार करना पड़ता है। इसकी बानगी बीते रविवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए ड्रोन हमले की जांच के दौरान देखने को मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का जायजा तो लिया, लेकिन वे अपने साथ कोई भी फोरेंसिक एक्सपर्ट साथ लेकर नहीं गए। हमले के एक दिन बाद जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम एक्सप्लोसिव और बैलेस्टिक एक्सपर्ट की टीम लेकर पहुंची तो मौका-ए-वारदात से सैंपल उठाए गए।

# श्रीनगर जिले में ड्रोन के इस्तेमाल पर लगी रोक

**राज्य ब्यूरो, जम्मू**

जम्मू में एयरबेस स्टेशन पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले को देखते हुए श्रीनगर जिले में ड्रोन और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहनों के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने अपने आदेश में कहा कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई स्थान को सुरक्षित करने के लिए ड्रोन के उपयोग को बंद करना जरूरी है। आदेश में कहा गया है कि जीवन और संपत्ति के नुकसान के किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में ड्रोन का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पहले से ही ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ड्रोन की गति से लेकर विशेष पहचान नंबर, ऊंचाई तक का जिक्र है। आदेश में कहा गया है मानव रहित हवाई वाहनों को जिला श्रीनगर के भीतर आसमान में घूमना बेहद खतरनाक है।

### एलओसी पर बढ़ाई हवाई सुरक्षा

**जासं, राजौरी :** जम्मू संभाग के राजौरी व पुंछ जिलों में पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर किसी भी ड्रोन हमले की आशंका को देखते हुए भारतीय सेना ने हवाई सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ा दी है। राजौरी और पुंछ में एलओसी पर सेना सभी अग्रिम चौकियों पर मुस्तैद है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच पुनः संघर्ष विराम समझौते से 26 फरवरी के बाद से एलओसी अशांत है। बावजूद इसके सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई है।

**15** जुलाई से मुंबई में पांचवें सीरो सर्वे की शुरुआत होगी। इसमें बच्चों को छोड़कर शहर के सभी आयु के लोगों का सर्वेक्षण कर यह पता लगाया जाएगा कि कितनों में एंटीबाडी विकसित हो गई है।



# टीकाकरण ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में दी गईं करीब 64 लाख डोज

**महाभियान** ▶ देश में अब तक 35 .12 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं

### महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं


कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है। रविवार को पटना के एसकेएम हाल में वैक्सीन लेती एक महिला। एएनआइ

**नई दिल्ली, आइएएनएस :** देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। 21 जून को शुरू हुए महाभियान में पिछले कुछ दिनों से सुस्ती देखी जा रही थी और दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा 50 लाख से नीचे आ गया था, लेकिन पिछले 24 घंटे में करीब 64 लाख टीके लगाए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रविवार सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 35.12 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें पिछले एक दिन में लगाई गईं 63,87,849 डोज भी शामिल हैं। वहीं, को-विन एप के मुताबिक अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों को पहली और छह करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कुल तीन करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। महाराष्ट्र में 3.40 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 3.26 करोड़ डोज लगाई गई हैं। जबकि, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, बंगाल और मध्य प्रदेश में भी दो करोड़ से ज्यादा डोज दी गई हैं।

### यहां अफवाहों को विराम, टीकाकरण को मिला मुकाम

**ब्रजेश मिश्र/सदानंद महतो, बारुहातु (रांची) :** झारखंड की राजधानी रांची-जमशेदपुर मुख्य मार्ग से करीब चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुंडू प्रखंड की हुमटा पंचायत का गांव बारुहातु ने कोरोना महामारी के दौर में बेहद खास पहचान बनाई है। गांव में 18 वर्ष से अधिक की करीब 700 की आबादी ने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाकर मिसाल पेश कर दी है। शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन कराने वाला रांची जिले का यह पहला गांव है। नाली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस गांव के लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हैरान करने वाली है। गांव के लोगों ने पंचायत में लगे शिविर में बढ़चढ़ कर वैक्सीनेशन कराया। साथ-साथ आसपास के गांव व पंचायतों में भेजे गए टीके के बची हुई डोज को मंगाकर अपना वैक्सीनेशन कराया। गांव के लोग इस उपलब्धि का सेहरा नौवीं की परीक्षा पास दो महिला सहिया, 12वीं पास आंगनबाड़ी सेविका व ग्राम प्रधान के सिर बांधते हैं।

### जम्मू-कश्मीर में बिना टीका या निगेटिव रिपोर्ट के मॉल व रेस्तरां में जाने पर पाबंदी

**राज्य ब्यूरो, जम्मू :** जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने टीकाकरण अभियान के 100 फीसद लक्ष्य हासिल करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य में किसी भी इंडोर शापिंग कांप्लेक्स या मॉल की दुकानों, रेस्तरां, बार, इंडोर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में वह लोग ही प्रवेश कर पाएंगे, जिन्होंने कोरोनारोधी टीका लगवाया होगा या फिर जिनके पास 48 घंटे की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी।

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना की मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श किया। बैठक में उन्होंने कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के 13 जिलों में छूट देने की घोषणा की है। इसमें जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, ऊधमपुर, अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामुला, बड़गाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां जिला शामिल हैं। इन जिलों में अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा। हालांकि, रात का कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा।

# कोरोना संक्रमण से एक हफ्ते में 32 फीसद घटी मौतें


राजस्थान में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सप्ताहंत कर्फ्यू लागू है। रविवार को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जाने वाली सड़क पर पसरा सन्नाटा। एएनआइ

- उपरोक्त अवधि के दौरान संक्रमण के मामलों में भी आई 11 फीसद की कमी
- प्रति 10 लाख आबादी पर मामलों में 28 और मौतों में दो की गिरावट दर्ज की गई

**जेएनएन, नई दिल्ली :** देश में कोरोना की दूसरी लहर कुंद पड़ रही है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें संक्रमण के मामले, मौतें और प्रति 10 लाख आबादी पर मामले और मौतें कम हो रही हैं। नए मामलों की तुलना में मरीजों के ज्यादा ठीक होने से सक्रिय मामले भी घट रहे हैं।

वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले सात दिनों में कोरोना से 6,235 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे पहले के सात दिनों में यह संख्या 9,144 थी। इस तरह इसमें 32 फीसद की कमी आई। एक हफ्ते में संक्रमण के 3,12,165 मामले सामने आए, जबकि उसके पहले के सात दिनों में 3,50,968 केस मिले थे। इसमें 11 फीसद की कमी दर्ज की गई। उपरोक्त अवधि के दौरान प्रति 10 लाख आबादी पर 224 मामले मिले और चार मौतें हुईं। इससे पहले के हफ्ते की तुलना में संक्रमण के मामलों में 28 और मौतों में दो की कमी आई।

**रविवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति**

| | |
|---|---|
| नए मामले | 43,071 |
| कुल मामले | 3,05,45,433 |
| मौतें | 955 |
| कुल मौतें | 4,02,005 |
| कुल सक्रिय मामले | 4,85,005 |
| ठीक होने की दर | 97.09 फीसद |
| पाजिटिविटी दर | 2.34 फीसद |
| मृत्यु दर | 1.32 फीसद |
| जांचें (शनिवार) | 18,38,490 |
| कुल जांचें | 41,82,54,953 |

### कोविड के कारण इंटरव्यू में देरी से अभ्यर्थी ने की आत्महत्या

**पुणे, प्रेट्र :** पुणे के हदपसर इलाके में रहने वाले महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा के एक अभ्यर्थी ने कोरोना संक्रमण के कारण इंटरव्यू नहीं होने पर अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या कर ली। हदपसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक बालकृष्ण कदम ने बताया कि स्वप्निल लोनकर के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री थी। वह एमपीएससी-2019 की प्राथमिक तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था और इंटरव्यू होने का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा वह 2020 की प्राथमिक परीक्षा भी निकाल चुका था।

कदम ने बताया कि उसने 30 जून को घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वप्निल अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गया है, जिसमें उसने एमपीएससी परीक्षा को मायाजाल बताते हुए किसी से इसके चक्कर में नहीं पड़ने का अनुरोध किया है। कदम ने बताया, स्वप्निल ने सुसाइड नोट में कहा है कि इंटरव्यू नहीं होने के चलते उसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे। उसने इस उम्मीद में लोन ले लिया था कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। उसने यह भी कहा है कि वह डिप्रेशन में चला गया है और उसके परिवार को उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस बीच, स्वप्निल के पिता ने कहा, राज्य सरकार की उदासीनता उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक और मुख्य परीक्षा में चयनित होने के बाद बेटे को जल्द ही नियुक्ति मिलने की उम्मीद थी। वह कर्ज का बोझ घटाकर मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन अब तो वह खुद चला गया। सरकार की उदासीनता के कारण मैंने अपना बेटा खो दिया।

### पंजाब के मोगा में कोरोना से न कोई मौत, न ही नया मामला

**राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ :** कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच मोगा पंजाब का दूसरा ऐसा जिला बना जहां दूसरी लहर में पहली बार कोरोना का न तो कोई नया मामला सामने आया और न ही किसी की मौत हुई। शनिवार को बरनाला जिले में भी कोरोना का कोई नया मामला नहीं मिला था, लेकिन इसके अगले ही दिन रविवार को यहां तीन लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 10 जिलों में नए मामलों के संख्या पांच से कम रही। 26 जनवरी, 2021 के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब राज्य में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। रविवार को राज्य में 158 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई जबकि 358 लोगों ने कोरोना को मात दी। पांच लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 2324 रह गई है।

# वैक्सीन की तेज होगी जांच, दो और केंद्रीय ड्रग लैब की गईं स्थापित

- पुणे और हैदराबाद में स्थापित हुई प्रयोगशालाएं, अभी सिर्फ कसौली में थी लैबोरेटरी

**नई दिल्ली, एएनआइ :** देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस साल के अंत तक सभी लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है, इसके लिए भारी मात्रा में वैक्सीन की जरूरत है। इसे पूरा करने के लिए सरकार युद्धस्तर पर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में वैक्सीन की गुणवत्ता की जांच और उसे बाजार में जारी करने की मंजूरी देने के लिए दो और सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी यानी केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पुणे स्थित स्वायत्त शोध संस्थान नेशनल सेंटर फार सेल साइंस (एनसीसीएस) और हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एनिमल बायोटेक्नोलाजी (एनआइएबी) में सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी (सीडीएल) की स्थापना की गई है। यहां पर कोरोना रोधी वैक्सीन के बैच और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी।

अभी देश में सिर्फ एक कसौली में सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी है। यह एक नेशनल कंट्रोल लैबोरेटरी है, जहां मनुष्य में इस्तेमाल किए जाने वाले टीके और एंटीसेरा की जारी करने से पहले जांच की जाती है और टीकाकरण के लिए उसे प्रमाण दिया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि पीएम-केयर्स फंड द्वारा वित्तीय मदद से इन दोनों केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है। पुणे स्थित प्रयोगशाला को सीडीएल के रूप में वैक्सीन की जांच और उसके लाट को जारी करने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। हैदराबाद स्थित लैबोरेटरी के लिए भी जरूरी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इन दोनों प्रयोगशालाओं में प्रतिमाह वैक्सीन की करीब 60 बैच की जांच किए जाने की उम्मीद है। इससे टीकाकरण के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिलेंगी।

### उत्तराखंड में शापिंग मॉल खोलने की दी जा सकती है छूट

**राज्य ब्यूरो, देहरादून :** कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू को सरकार एक हफ्ते आगे बढ़ाने जा रही है। इसमें वर्तमान में लागू रियायत को बरकरार रखने के साथ ही शापिंग मॉल खोलने की छूट दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कोविड कर्फ्यू के संबंध में मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) सोमवार शाम तक जारी हो जाएगी। प्रदेश में बीती 10 मई को एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसके बाद से कर्फ्यू को एक-एक हफ्ते के लिए निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही कर्फ्यू में रियायत दी गई है। वर्तमान में सप्ताह में छह दिन बाजार सुबह आठ से शाम सात बजे तक खुल रहे हैं। आवश्यक सेवाओं के कार्यालय 100 फीसद और शेष कार्यालय 50 फीसद क्षमता के साथ खुल रहे हैं।

# कोविन वैश्विक सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित होने वाले कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा करेंगे। भारत इस सम्मेलन में अन्य देशों को उनके कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन प्लेटफार्म की पेशकश करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने ट्वीट कर कहा, 'हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचार साझा करेंगे, क्योंकि भारत कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए विश्व के सामने एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन को पेश करता है।' वर्चुअल तरीके से आयोजित इस सम्मेलन का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उद्घाटन करेंगे। एनएचए के सीईओ डा. आरएस शर्मा ने हाल ही में कहा था कि कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और उगांडा समेत करीब 50 देशों ने अपने यहां कोविड-19 टीकाकरण चलाने के लिए कोविन जैसा डिजिटल प्लेटफार्म हासिल करने में रुचि दिखाई है। भारत भारत इन देशों के साथ मुफ्त में इस प्लेटफार्म के ओपन सोर्स साफ्टवेयर साझा करने के लिए तैयार है।

## राष्ट्रीय फलक

# बेटी भागी तो प्रेमी के परिवार को गोलियों से भूना

**जागरण संवाददाता, बटाला (गुरदासपुर)**

- कांग्रेस के पंच ने युवक के दादा व पिता समेत चार की हत्या की
- जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते रहे लोग, दो की हालत गंभीर


मृतक सुखविंदर सिंह की पत्नी सतविंदर कौर विलाप करती हुईं। जागरण

बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज एक व्यक्ति ने रविवार सुबह छह बजे खेत में काम कर रहे बेटी के प्रेमी के परिवार पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद मुख्य आरोपित सुखजिंदर सिंह व उसका भाई जतिंदर सिंह फरार हैं। सुखजिंदर कांग्रेस का पंच है।

दहला देने वाली यह वारदात बटाला के बलड़वाल गांव की है। बटाला सिविल अस्पताल में भर्ती हरमनदीप सिंह ने बताया कि उसके भाई जर्मन सिंह का पंच सुखजिंदर सिंह की बेटी के साथ प्रेम संबंध था। दोनों रविवार तड़के चार बजे घर से भाग निकले, लेकिन साढ़े पांच बजे लौट आए और अपने-अपने घर को चले गए। लेकिन सुखजिंदर सिंह की नाराजगी कम नहीं हुई। वह अपने भाई जतिंदर सिंह के साथ खेतों में पहुंच गया और वहां काम कर रहे जर्मन सिंह के परिवार के सदस्यों पर लाइसेंसी रिवाल्वर से अंधाधुंध गोलियां चला दीं। जर्मन के दादा मंगल सिंह, उसके पिता सुखविंदर सिंह, चाचा जसवीर सिंह और भाई बबनदीप सिंह की मौके पर मौत हो गई। जर्मन के भाई हरमनदीप सिंह व जसप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

**जेब में भर कर लाया था गोलियां :** पुलिस के अनुसार आरोपित जेब भर के गोलियां साथ लाया था। उसकी फायरिंग से बचने के लिए परिवार के लोग इधर-उधर भागने लगे, खुला खेत होने के कारण उन्हें छिपने की जगह नहीं मिली।

**मां-बेटी से हो रही पूछताछ :** मुख्य आरोपित, उसके भाई व पत्नी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और अपराध छिपाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पंच की बेटी व उसकी मां को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। श्री हरगोबिंदपुर से कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी ने देर शाम घायलों का हाल-चाल जाना।

### पहले भी हुई थी झड़प

एसएसपी रछपाल सिंह ने बताया कि दोनों परिवारों में सबसे पहले पंचायत चुनाव के दौरान झड़प हुई थी। इसके बाद राशन डिपो लेने के लिए भी विवाद हुआ था। तब पंचायत ने राजीनामा करा दिया था। प्रेम संबंध के मामले की भी जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार के बयान लिए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार भी कांग्रेस समर्थक है।

### ऐसा लगा आतंकी हमला हो गया

घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि रविवार सुबह छह बजे उन्होंने खेतों में ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज सुनी। ऐसा लगा कि आतंकी हमला हो गया है। बाहर निकलकर देखा तो पंच खेत में काम कर रहे लोगों पर गोलियां बरसा रहा था और वे जान बचाने के लिए भाग रहे थे।

### महाराष्ट्र में भीड़ ने बिजली कंपनी के गार्ड को पीटकर मार डाला

**ठाणे, प्रेट्र:** महाराष्ट्र में बकायेदारों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान एक निजी कंपनी के गार्ड को लोगों ने पीटकर मार डाला। एक अन्य वारदात में भीड़ ने हमला कर तीन पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। निजामपुरा थाने के अधिकारियों ने बताया कि बिजली कंपनी के कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड तुकाराम पवार के साथ शनिवार को भिवंडी के कनेरी गांव में बकायेदारों से वसूली के लिए गए थे। इसी दौरान 10-15 ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। तुकाराम को गंभीर चोट आई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

उधर, महाराष्ट्र व गुजरात पुलिस भिवंडी के कसाईवाड़ा में जमील कुरैशी को पकड़ने गई थी। उस पर गुजरात के वलसाड में मुकदमा दर्ज है। इस दौरान जमील चौथी मंजिल पर स्थित फ्लैट से कूद गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जमील के स्वजन व स्थानीय लोगों ने पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगाते हुए ईंट-पत्थरों से हमला बोल दिया। इसमें दो सिपाही व एक उप निरीक्षक घायल हो गए।

# धार में बर्बरता, चचेरे भाइयों ने दो बहनों को बेरहमी से पीटा

**नईदुनिया, इंदौर**


युवतियों की पिटाई करते स्वजन। वीडियो ग्रैब

मध्य प्रदेश में धार जिले के पीपलवा गांव का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें कुछ लोग दो युवतियों को लाठी-डंडों, लात-घूंसों से बर्बरतापूर्वक पीटते नजर आ रहे हैं। वहां मौजूद लोग मूकदर्शक बने खड़े हैं। बताया जा रहा है कि मामा के लड़कों से मोबाइल पर बात करने पर दो बहनों को यह सजा उनके चचेरे भाइयों ने दी है। यह घटना 22 जून की है। 25 जून को वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो अगले दिन साधारण मारपीट के तहत मामला दर्ज किया गया और जमानती अपराध होने से उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने आरोपितों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने को कहा तब रविवार को पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

टांडा थाना प्रभारी विजय वास्कले ने बताया कि वीडियो मिलने पर वह 25 जून को पीपलवा पहुंचकर दोनों युवतियों को थाने लाए थे। उनसे पूछताछ के बाद रात करीब एक बजे एफआइआर दर्ज की गई थी। युवतियों ने बताया था कि 22 जून की सुबह करीब 11 बजे चचेरे भाइयों और ताई ने रास्ते में रोका था। उन्होंने कहा कि तुम दोनों मामा के लड़के से क्यों बात करती हो? फिर सभी मारपीट करने लगे।

# चक्रवात से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग के 50 फीसद आवेदन खारिज

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता**

- ममता सरकार ने जांच के बाद आवेदनों को पाया फर्जी

बंगाल सरकार ने चक्रवात 'यास' से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर जमा किए गए करीब 50 फीसद आवेदनों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है।

जानकारी के अनुसार बंगाल की ममता सरकार को पिछले महीने 'दुआरे त्रान' (दरवाजे पर राहत) कार्यक्रम के तहत इस बाबत 3,81,774 आवेदन मिले थे। 18 से 30 जून के बीच किए गए इन आवेदनों के सत्यापन के बाद 1,86,815 को ब्लॉक विकास अधिकारियों व शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुखों द्वारा फर्जी पाए जाने पर खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि यास ने बंगाल और पड़ोसी राज्य ओडिशा में भारी तबाही मचाई थी। विशेष रूप से तटीय इलाकों में उसके विनाश के निशान अब भी मौजूद हैं। ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मई में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यास से प्रभावित लोगों को लिखित रूप में आवेदन करने को कहा था।

उधर, वास्तविक दावेदारों को एक जुलाई से मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। यास से लगभग 2.21 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल और 71,560 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी नष्ट हो गई थी। चक्रवात से बंगाल को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिस व्यक्ति की कृषि भूमि को यास ने नुकसान पहुंचाया है, उसे 1,000 से 25,000 रुपये के बीच मुआवजा मिलेगा। पान की खेती करने वाले प्रभावित किसान और आपदा में अपने मवेशियों को खोने वाले व्यक्ति 5,000 से 30,000 रुपये के मुआवजे के हकदार होंगे।

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मिट्टी के घरों के लिए 5,000 रुपये और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

# उत्तर भारत में आठ जुलाई से सक्रिय होगा मानसून

**मिले संकेत**

- मौसम विभाग ने कहा, सात जुलाई तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं
- दक्षिण, पश्चिमी तट और मध्य पूर्व भारत में बारिश में वृद्धि का अनुमान

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** कुछ दिन की सुस्ती के बाद आठ जुलाई से उत्तर भारत के इलाकों में फिर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय नजर आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है और इन इलाकों को सात जुलाई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में इस दौरान बरसात हुई है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने रविवार को कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान को अभी दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल नहीं बन रहा है। आइएमडी ने जुलाई के लिए मौसम के पूर्वानुमान में इस महीने झमाझम बरसात की संभावना जताई थी। हालांकि, इस दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ भाग, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य और उससे कम बारिश हो सकती है। आइएमडी ने कहा कि जून के पहले ढाई हफ्तों तक दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत सक्रिय रहा था। परंतु, 19 जून के बाद मानसून धीमा पड़ गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है। वहीं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम. राजीवन के मुताबिक पूर्वानुमान माडल में आठ जुलाई के बाद बारिश में वृद्धि के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में मौसम में ऐसे बदलाव के संकेत मिले हैं जो ज्यादा बारिश के कारक हैं। इसके चलते दक्षिण, पश्चिम तट और मध्य पूर्व हिस्से में आठ जुलाई से बारिश होने की संभावना है।

बता दें कि रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में पारा 42 डिग्री सेल्यिस तक चढ़ गया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हवा में नमी 68 फीसद रही।

# भारत में प्रचंड गर्मी से 50 वर्षों में 17 हजार लोगों की मौत

- अधिकतम लोगों की मौत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में हुई

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** गर्मी की लहर के चलते भारत में पिछले 50 सालों में 17 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। देश के वरिष्ठ मौसम विज्ञानियों के ताजा शोध के अनुसार वर्ष 1971-2019 के बीच देश में लू-लपट की 706 घटनाएं हुई हैं।

भारत में प्रचंड गर्मी के मौसम में पिछले पचास सालों में अधिकतम लोगों की मौत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में हुई हैं। प्रचंड गर्मी के प्रमुख क्षेत्रों में मई के महीने में रहना मुश्किल हो जाता है। प्रचंड गर्मी के ये जोन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं।

हालांकि अभी उत्तरी गोलार्द्ध के विभिन्न हिस्सों में जानलेवा गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में कनाडा और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्मी पड़ी है। वेंकूवर में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच गया था।

इसी तरह भारत के मैदानी इलाकों में लू-लपट से मौतें हुई हैं। इस हफ्ते यहां अधिकांश जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि आमतौर पर तटीय स्टेशनों पर 40 डिग्री और अन्य मैदानी इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक तापमान देखा जाता है। इस शोध पत्र को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन, विज्ञानी कमलजीत रे, एसएस रे, आरके गिरी और एपी डिमरी ने तैयार किया है।

### महाराष्ट्र में डीआरआइ ने 300 किग्रा हेरोइन जब्त की, एक गिरफ्तार

**मुंबई, प्रेट्र :** राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) ने अफगानिस्तान से तस्करी कर लाई गई करीब 300 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पड़ोस के रायगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) पर एक व्यक्ति को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह हाल के दिनों में प्रतिबंधित पदार्थ की सबसे बड़ी जब्ती है।

डीआरआइ के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान होते हुए अफगानिस्तान से तस्करी कर लाई गई खेप को पहले जिप्सम पत्थर और टेलकम पाउडर बताया गया था। उन्होंने बताया कि आयात निर्यात कोड प्रभजोत सिंह के नाम पर था और यह खेप पंजाब भेजी जानी थी। सिंह को प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपित पिछले एक साल से जेएनपीटी के जरिये जिप्सम पत्थर और टेलकम पाउडर का आयात कर रहा था।

**खतरा बड़ा है** | ड्रोन से हमले का खतरा कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में यूरोपीय संघ के सुरक्षा आयुक्त जूलियन किंग ने चेतावनी दी थी कि यूरोपीय शहरों पर हमले के लिए आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।



पांच अगस्त, 2019 को जब से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया और यह अमन व शांति के साथ विकास की राह का अनुगामी बना, तब से पाकिस्तान और उसके पोषित आतंकी समूहों की रातों की नींद और दिन का चैन गायब है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किमी लंबी नियंत्रण रेखा है। सुरक्षा एजेंसियां इस रेखा पर घुसपैठ रोकने के लिए मुस्तैद रहती हैं। अगस्त, 2019 के बाद सुरक्षाबलों ने सीमापार से होने वाली घुसपैठ पर एक तरह से लगाम लगा दी। सुरंग के माध्यम से आतंकियों के घुसने की रणनीति सहित अन्य तरीके भी निगरानी की जद में आ गए। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम ने भी घुसपैठ रोकने में मदद की। अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते जम्मू-कश्मीर और लद्दाख इन आतंकियों को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे हैं। आतंकी विवश हैं। सीमा पर कड़ा पहरा है। भारतीय जवान मुस्तैद हैं, लिहाजा ड्रोन से आतंकी हमला करने का उन्होंने तरीका निकाला। पहली बार किसी भारतीय एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाने की आतंकियों ने हिमाकत की है। सुरक्षाबलों के मुताबिक, अगस्त, 2019 के बाद से अब तक करीब 300 ड्रोन देखे जा चुके हैं। आसमान में उड़ता यह खतरा नया तो है ही, गंभीर भी है। इसकी काट खोजने में भारतीय विज्ञानी और सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। जल्द ही हमारे पास आतंकी ड्रोन को मार गिराने या काबू करने की तकनीक होगी, जो इनके नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगी। ऐसे में पंजाब से लेकर कश्मीर तक भारतीय सीमा क्षेत्र में आने वाले इन आसमानी खतरों और इनसे निपटने की रणनीति की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।





# आतंकी ड्रोन नया खतरा



## बड़ा संकट बन रहे छोटे फ्लाइंग रोबोट

ड्रोन का जिक्र होते ही हमारे दिमाग में आमतौर पर एक छोटे से रोबोटिक विमान की छवि बनती है। कुछ फीट का विमान, जिसे रिमोट के जरिये कहीं दूर से संचालित किया जाता है। हालांकि ड्रोन यानी मानवरहित विमान (यूएवी) का परिचय सिर्फ इतना नहीं है। ड्रोन का अर्थ सिर्फ दो-तीन फीट का रिमोट से चलने वाला विमान ही नहीं होता है। हेलिकॉप्टर के आकार के बड़े युद्धक ड्रोन भी बहुतायत में हैं। दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे घातक युद्धक ड्रोन विकसित करने में सक्रियता से जुटे हैं। कई युद्धक ड्रोन 1,000 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन के हथियार लेकर उड़ने और कई-कई घंटे लगातार हवा में रहने में सक्षम हैं। हाल के दिनों में आतंकियों द्वारा इनके इस्तेमाल ने सबकी चिंता बढ़ा दी है।

### आई आफ द स्काई भी कहे जाते हैं ड्रोन

ड्रोन को आम भाषा में फ्लाइंग रोबोट कहा जा सकता है। इन्हें दूर बैठे नियंत्रित किया जा सकता है। इनके माध्यम से न केवल किसी स्थान विशेष की 24 घंटे निगरानी की जा सकती है, बल्कि ये आपको रियल टाइम पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के चलते इसे आई आफ द स्काई (आसमान की आंख) कहा जाता है।

### 1917 से जुड़ते हैं ड्रोन की कहानी के शुरुआती तार

ड्रोन के आधुनिक स्वरूप के तार 1917 से जुड़ते हैं। चार्ल्स कैटरिंग ने एक हवाई तारपीडो बनाया था, जिसे बग नाम दिया गया था। यह किसी जगह पहुंचकर वहां बम गिराने में सक्षम था। 1937 में अमेरिकी नौसेना ने रेडियो तरंगों से नियंत्रित होने वाला मानवरहित तारपीडो एन2सी-2 बनाया था। 1973 में रूस ने सैन्य निगरानी के लिए ड्रोन बनाया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान ड्रोन का पहली बार सैन्य इस्तेमाल किया था। अमेरिका का रहस्यमयी एक्स-37बी स्पेस प्लेन भी ड्रोन की ही श्रेणी में आता है। अमेरिका



की वायुसेना इसे नियंत्रित करती है। इसे अंतरिक्ष में जाकर वापस आ सकने वाले विमान के तौर पर विकसित किया गया है।

### बनते जा रहे हैं आतंकवादियों के हाथ का हथियार

द एसोसिएशन आफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी (एयूएसए) ने फरवरी, 2021 में 'द रोल आफ ड्रोन्स इन फ्यूचर टेररिस्ट अटैक्स' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें बताया गया कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने पहली बार आतंकी गतिविधियों में ड्रोन का इस्तेमाल किया था। एक गैर सरकारी संगठन मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वाशिंगटन पोस्ट के एक लेख के हवाले से कहा कि अगस्त, 2014 में आइएस ने युद्ध के मैदान की खुफिया जानकारी एकत्र करने और आत्मघाती विस्फोटों के प्रभावों का पता लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करना शुरू किया था। यह आतंकी संगठन छोटे ड्रोन पर बम बांधकर हमले की भी कई कोशिशें कर चुका है। पिछले वर्ष अक्टूबर में इराक में ऐसे एक हमले में कई कुर्द लड़ाकों की जान चली गई थी। इससे पहले



2013 में अलकायदा ने ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आतंकी हमले की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। 2016 से इराक और सीरिया में हमला करने के लिए आइएस लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस्लामिक स्टेट के अलावा फलस्तीन और लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, तालिबान के साथ पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी संगठन हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

### भारत में हथियार गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है पाक

भारत-पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा पर ड्रोन देखे जाने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कुछ ड्रोन का प्रयोग भारतीय सीमा में हथियार गिराने के लिए भी किया गया।

**2019** में सुरक्षाकर्मियों ने पाकिस्तान से 167 ड्रोन और 2020 में 77 ड्रोन देखे जाने की जानकारी दी।

**2019** सितंबर: में पंजाब पुलिस ने ड्रोन से गिराए गए हथियारों की एक खेप को जब्त कर एक आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जिन हथियारों को बरामद किया गया था, उसमें एके-47 राइफल और चीन निर्मित पिस्टल शामिल थीं।

**2020** जून: पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन से गिराए गए



हथियारों की एक और खेप जब्त की गई।

- उसी महीने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने जम्मू के हीरा नगर सेक्टर में एक ड्रोन को मार गिराया था। इसमें अमेरिका में बनी एम4 राइफल मिली थी।

**2021** जनवरी: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा, क्योंकि वे ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खेप उठा रहे थे।

### चीन कर रहा है पाकिस्तान को इस नए हथियार की आपूर्ति

पाकिस्तान के पास स्वदेशी ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां बहुत नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान को और उसके आतंकी संगठनों को चीन से ड्रोन आसानी से मिल जाते हैं। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन द्वारा गिराई गई खेप में अक्सर चीन में बने हथियार और गोला-बारूद होते हैं।



### ड्रोन हमलों को रोकने में मुश्किल क्यों आती है?

भारत द्वारा सीमाओं या नियंत्रण रेखा पर तैनात रडार सहित निगरानी तकनीक का उपयोग बड़ी वस्तुओं, हेलीकॉप्टरों, विमानों और मिसाइलों पर नजर रखने के लिए किया जाता है, लेकिन ड्रोन बहुत छोटे होते हैं। कई ड्रोन तो बमुश्किल दो फीट के होते हैं। इसीलिए ये रडार की पकड़ में नहीं आते। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए ड्रोन सिस्टम को जाम करना और उन्हें नीचे गिराना आवश्यक है। ड्रोन हमलों के खिलाफ रक्षा प्रणाली के रूप में लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू) के बारे में बात की जा रही है। भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने दो ड्रोन विरोधी सिस्टम विकसित किए हैं। ये दो किमी की दूरी पर उड़ रहे ड्रोन को निशाना बनाने के लिए 10 किलोवाट के शक्तिशाली लेजर का उपयोग करते हैं। हालांकि, इन प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होना अभी बाकी है।

### भारत की है देखो और मार गिराओ की रणनीति

सीमा सुरक्षा बल और विभिन्न पुलिस इकाइयों की सीमावर्ती यूनिट ने 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा पर ड्रोन को हवा में दिखते ही मार गिराने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए सुरक्षा प्रहरी को सतर्क रहना होता है। उसे लगातार किसी भी ड्रोन जैसी हलचल पर नजर रखना होता है और ड्रोन दिखते ही उसे इंसास राइफल जैसे हथियार से मार गिराना होता है।

### इस नए संकट से निपटने को कई प्रणालियों पर हो रहा काम

ड्रोन हमलों को रोकने के लिए स्काई फेंस, ड्रोन गन, एथैना, ड्रोन कैचर और स्काईवाल-100 जैसी विशिष्ट ड्रोन रोधी तकनीकों पर काम किया जा रहा है।



**ड्रोन गन**
यह पायलट और ड्रोन के बीच रेडियो सिग्नल को जाम करने के साथ ही ड्रोन को उतरने पर मजबूर कर देती है।



**स्काई फेंस**
इसके माध्यम से ड्रोन पर इस तरह के सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह अपना रास्ता भटक जाता है।



**एथैना**
एडवांस्ड टेस्ट हाई एनर्जी एसेट (एथैना) पर भी काम चल रहा है। यह उच्च क्षमता की लेजर बीम के जरिये ड्रोन को नष्ट करता है।



**ड्रोन कैचर**
यह तेजी से दुश्मन ड्रोन के पास पहुंचता है और हवा में ही उस पर जाल फेंककर उसे काम करने से रोक देता है।

### कुछ ध्यान रखने की बातें

- भारत में बहुत कम कंपनियां अभी ड्रोन पर रिसर्च कर रही हैं। कुछ कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर रिसर्च में सक्रिय हैं। इस दिशा में सरकार की ओर से सहयोग और निवेश बढ़ाने की जरूरत है।
- भारत में नागरिक ड्रोन को लेकर कोई डाटा मौजूद नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक, देश में चार से पांच लाख ड्रोन मौजूद हैं।
- डीजीसीए ने मार्च, 2021 में ड्रोन उड़ाने को लेकर यूएएस रूल 2021 जारी किया था। इसके तहत ड्रोन उड़ाने से पहले डीजीसीए से इजाजत लेना जरूरी है।

# अपनानी होगी इजरायल की रणनीति



ले. जनरल केजे सिंह
पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमान

**सीमा पर ड्रोन से हमले की कोशिशों के बाद इनसे निपटने की रणनीति पर चिंता बढ़ गई है। ड्रोन का यह खतरा सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। इस नए खतरे से निपटने की विशेषज्ञता को देखते हुए इजरायल की नीति पर चलने की जरूरत है। साथ ही तकनीक के स्तर पर यथासंभव विकास करना होगा।**

पाक की ओर से ड्रोन हमलों ने भारतीय सेना व सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आतंकी इन ड्रोन का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहे हैं। ड्रोन के साथ दिक्कत यह है कि इसे न तो रडार से पकड़ा जा सकता है और न ही इसे मार गिराने के बाद सेना को कुछ हासिल होता है। ऐसे में निश्चित तौर पर ड्रोन सुरक्षा के लिहाज बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहे हैं।

ड्रोन सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती हैं। अगर ड्रोन सीमावर्ती क्षेत्र की रेकी कर रहा है, तो बीएसएफ के लिए चुनौती है। हमारे समुद्री क्षेत्र में घुसा है, तो नौसेना के लिए चुनौती है। आसमान पर उड़े तो एयरफोर्स के लिए चुनौती है। इतना ही नहीं शहर के अंदर ड्रोन हमला हो तो पुलिस के लिए चुनौती है। अहम बात यह भी है कि ड्रोन बनाने में कोई बड़ा विज्ञान काम नहीं करता है। तकनीकी तौर पर मजूबत व्यक्ति 25 से 30 हजार रुपये खर्चकर छोटा ड्रोन बना सकता हैं। ऐसे में जरूरी है कि ड्रोन से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर प्रयास करें। सेना को सैनिकों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर जोर देना होगा और वायुसेना को अपने रडार अधिक सक्षम बनाने होंगे। बीएसएफ को बॉर्डर पर अपनी निगरानी तेज करनी होगी। सैनिकों के पास बेहतर हथियार और नाइट विजन इक्विपमेंट भी होने चाहिए। इस तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर सर्विलांस, इंटेलीजेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है।

हमें समझना होगा कि आतंकियों ने काफी पहले से ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इससे पहले भी कई देशों की सीमाओं पर ड्रोन से इस तरह के हमले होते रहे हैं। पंजाब की सीमा पर नशा तस्कर काफी पहले से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना ने कई बार इन हमलों को नाकाम भी किया है। बावजूद इसके अभी हमारे पास ड्रोन हमलों से निपटने के लिए सक्षम तकनीकी नहीं है। इस तरह के हमलों से निपटने में इजरायल एक्सपर्ट है। उसे उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। हमें उसी की तरह ड्रोन हमलों से निपटने के लिए काम करना होगा। इतना ही नहीं, ऐसे हमले की कोशिश करने वालों पर भी इजरायल की तर्ज पर ही कार्रवाई की जरूरत है, ताकि दोषी संगठन या व्यक्ति दोबारा ऐसी हिमाकत न कर सकें। हमें ड्रोन हमलों से बचने के लिए अपनी रेडिया फ्रिक्वेंसी मजूबत करनी होगी, ताकि जहां से ड्रोन गाइड हो रहा हो, वहीं उसे रोका जा सके। ऑडियो फ्रिक्वेंसी मॉनिटरिंग के लिए रडार सिस्टम मजबूत करना होगा। हाइटेक नाइट विजन डिवाइस भी इस दिशा में अहम हैं।

ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए बचाव की दिशा में कुछ और कदम भी जरूरी है। हमें सीमावर्ती इलाकों में रेडियो फ्रिक्वेंसी जाम करने की नीति पर सोचना होगा। इसके अलावा सीमा पर तैनात सैनिकों के पास एंटी-एयरक्राफ्ट गन होनी चाहिए। इनसे निपटने के मामले में इजरायल का स्मैश सिस्टम भी बेहद कारगर है। इसे भी अपनाए जाने की जरूरत है। डीआरडीओ भी इस दिशा में काफी पहले से काम कर रहा है। नई चुनौतियां आने के बाद उस दिशा में पहले से चल रहे काम में भी तेजी लानी होगी। रक्षा विशेषज्ञों को किफायती तकनीक पर भी जोर देना चाहिए। जो भी तकनीक विकसित की जाए, उसकी कीमत कम रखने की कोशिश हो। इससे इनके प्रसार में मदद मिलेगी।

# विदेशी तकनीक के मुकाबले कमजोर नहीं भारतीय ड्रोन



प्रो. अभिषेक
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, आइआइटी कानपुर

**ड्रोन के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम अमेरिका, इजरायल और चीन जैसे देशों की टक्कर के ड्रोन विकसित कर रहे हैं। हालांकि इनके कंपोनेंट्स के लिए विदेश पर निर्भर रहना बड़ी समस्या है। इनके लिए घरेलू स्तर पर मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत है। घरेलू स्तर पर आपूर्ति ही हमें तेजी से आगे बढ़ने और अपग्रेड होने का मौका दे सकती है।**

ड्रोन तकनीक के मामले में देश में जानकारी और सूझबूझ की कमी नहीं है। यहां अच्छे डिजाइनर और प्रोग्रामर हैं। अमेरिका, इजरायल, चीन, ऑस्ट्रेलिया की तकनीक के मुकाबले भारतीय ड्रोन कमजोर नहीं हैं। पिछले दिनों अमेरिका में हुई प्रतियोगिता में आइआइटी कानपुर के बने ड्रोन ने तीन खिताब हासिल कर इसकी मिसाल पेश की थी।

ड्रोन के क्षेत्र में चीन ने बहुत तेजी से तरक्की की है। अमेरिका, इजरायल शुरू से ही आगे रहे हैं। अब भारत में भी इस ओर से तेजी से काम शुरू हुआ है। हालांकि यहां निवेश अपेक्षाकृत बहुत कम है, जो बड़ी बाधा है। एक बड़ी समस्या तकनीक के बाजार तक आने की है। प्रोटोटाइप से उसे वास्तविक धरातल तक लाने में कई चुनौतियां हैं। तकनीक के मामले में भारतीय विज्ञानी कमजोर नहीं हैं, लेकिन उपकरणों की उपलब्धता बड़ी समस्या है। यहां ड्रोन में इस्तेमाल के लिए मोटर, कैमरे, सेंसर बनाने वाली कंपनियां सीमित हैं। इसके लिए अन्य देशों पर निर्भरता है। चीन और ताइवान से कई उपकरण खरीदे जाते हैं। हमें ड्रोन के कंपोनेंट्स की मैन्यूफैक्चरिंग पर फोकस करने की जरूरत है।

ड्रोन का इस्तेमाल धीरे-धीरे बढ़ रहा है। डीजीसीए जरूरत के मुताबिक ड्रोन के संचालन की अनुमति दे रहा है। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत ड्रोन के जरिये दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। कई अन्य तरह के ट्रायल अन्य हिस्सों में चल रहे हैं। हर जगह मॉनीटरिंग आसान नहीं है, ऐसे में सरकार को अनुमति देने में सावधानी बरतनी पड़ती है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी की है। सेना में और सर्विलांस के लिए भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। नदियों, पाइप लाइन, खेत, पुल, बिल्डिंग आदि का सर्विलांस चल रहा है। जुलूस, परेड और कार्यक्रमों की निगरानी होती है। इन सबके लिए अच्छे कैमरे की जरूरत पड़ती है। देश में ऐसे कैमरे बहुत कम बन रहे हैं। स्कूल लेवल पर भी ड्रोन तकनीक शुरू करने की जरूरत है। रोबोटिक्स के अंतर्गत ड्रोन तकनीक की जानकारी दी जा सकती है। दिल्ली के कई स्कूलों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बच्चों में छोटे स्तर से ही इसकी जानकारी देने की जरूरत है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है। ड्रोन की तकनीक में पिछले 10 साल में तेजी से बदलाव आया है।

मैं स्वयं कई ऑटो पायलट बोर्ड बदल चुका हूं। आप कुछ भी बनाएंगे, उसे अपडेट नहीं करेंगे तो दो-तीन साल में बहुत पीछे हो जाएंगे। इसकी तकनीक बहुत तेजी से बदलती है। ड्रोन पर जो भी काम कर रहे है, उन्हें नई तकनीक पर काम करने की जरूरत है। छोटे ड्रोन पर अपने यहां काम चल रहा है। ये सस्ते रहते हैं और इन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। रडार से पकड़ में भी जल्दी नहीं आते हैं। ड्रोन के विकास के साथ-साथ एंटी ड्रोन विकसित करना भी जरूरी है। इस दिशा में भी देश में काम चल रहा है और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसमें तेजी की दरकार है। सरकार की ओर से और सहयोग की जरूरत है। एंटी ड्रोन गन बन चुकी हैं। यह ड्रोन के जीपीएस और आरएफ सिग्नल को जाम करती है। इजरायल और अमेरिका ने इन पर बहुत काम किया है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, उसे देखते हुए यह जरूरी है कि इसके कंपोनेंट देश में ही तैयार हों। आयात पर निर्भर रहकर हम पिछड़ जाएंगे। बाहर से उपकरण लाकर तेजी से अपग्रेड करना संभव नहीं हो सकता है।

## जनमत

हां 94% | नहीं 06%

**क्या पाकिस्तान पोषित आतंकियों के घुसपैठ के सभी रास्ते बंद किए जाने के बाद ड्रोन हमला उनकी हताशा को दिखाता है?**

हां 96% | नहीं 04%

**क्या आतंकियों के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए हमें उसकी काट के विकास को प्राथमिकता में रखने की जरूरत है?**

## आपकी आवाज

चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से न जाए। यही हाल पाकिस्तान और उसके आतंकियों का हो गया है। घुसपैठ के सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद अब आतंकी संगठन ड्रोन का रास्ता अपना रहे हैं। हमें इसका भी मुंहतोड़ जवाब देना होगा। **गौरीशंकर अंतज**

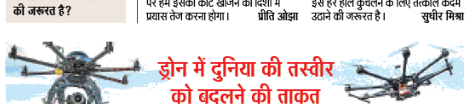
पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिये भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना हर तरह के खतरे से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान को पहले की तरह ही माकूल जवाब मिलेगा। **अनुज**

ड्रोन की तकनीक तेजी से बदल रही है। तमाम देश इस दिशा में काम कर रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है। हाल में जिस तरह से सीमा पर ड्रोन दिखे हैं, निश्चित तौर पर हमें इसकी काट खोजने की दिशा में प्रयास तेज करना होगा। **प्रीति ओझा**

आतंक को लेकर पाकिस्तान की नीति किसी से छिपी नहीं है। जम्मू-कश्मीर में वह हमेशा से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करता रहा है। ड्रोन भी उसकी ऐसी ही कोशिश है। इससे निपटने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। **कुलदीप भारद्वाज**

ड्रोन सीमा पर ही नहीं देश के भीतर भी खतरे का कारण बन सकता है। हाल के वर्षों में जिस तरह से चीन के संरक्षण में ड्रोन की उपलब्धता आसान हुई है, उसे देखते हुए इस दिशा में सरकार को नीतिगत स्तर पर सख्त होने की जरूरत है। **एसके सक्सेना**

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सीमा पर हाल के दिनों में दिखीं ड्रोन से जुड़ी गतिविधियां पाकिस्तान की हताशा ही हैं। इसे हर हाल कुचलने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। **सुधीर मिश्रा**



## ड्रोन में दुनिया की तस्वीर को बदलने की ताकत

ड्रोन की उन्नत तकनीक कई तरह से दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखती है। प्रयोग की दृष्टि यह बहुत व्यापक है। अलग-अलग क्षेत्र में इसके इस्तेमाल की संभावनाओं पर एक नजर :

**रक्षा क्षेत्र**
युद्ध के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत समय से हो रहा है। मौजूदा समय में छोटे-छोटे ड्रोन का प्रयोग सेनाएं नियमित तौर पर भी करने लगी हैं। दुनियाभर की सेनाएं इन पर निवेश बढ़ा रही हैं। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है।

**आपात स्थिति**
कैमरा टेक्नोलॉजी ने ड्रोन की ताकत को बढ़ाने में खासी मदद की है। आज कई आपातकालीन स्थितियों में ड्रोन की मदद से तेजी से राहत पहुंचाना संभव हो पाया है।

**आपदा राहत**
भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी राहत कार्यों में मददगार हो रही है। ड्रोन की मदद से आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को खोजने में मदद मिलती है।



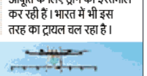
**बीमारियों के प्रसार पर नजर**
लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ने थर्मल इमेजिंग कैमरा वाले ड्रोन की मदद से ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया था, जहां मलेरिया के मामले ज्यादा थे। यह तकनीक कई बीमारियों के प्रसार को थामने में मददगार हो सकती है।

**वन्यजीव संरक्षण**
इन मानवरहित विमानों का इस्तेमाल वन्यजीव संरक्षण में भी किया जाने लगा है। इनकी मदद से संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर लगाम लगाने की क्षमता बढ़ी है।

**कंस्ट्रक्शन प्लानिंग**
ड्रोन की मदद से किसी क्षेत्र के नक्शे को ध्यान में रखते हुए वहां बेहतर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की जा सकती है। कई सौ किलो के वजन उठाने में सक्षम ड्रोन इन्फ्रा निर्माण में भी मददगार हो सकते हैं।

**स्वास्थ्य क्षेत्र**
कई कंपनियां दवाओं और अन्य जरूरी मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत में भी इस तरह का ट्रायल चल रहा है।

**कृषि क्षेत्र:** कंपनियां फूलों के परागण से लेकर कृषि क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की संभावनाओं पर काम कर रही हैं।



दैनिक जागरण
बार-बार दोहराने से कोई झूठ सच नहीं बन जाता

## फिर राफेल

राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर मुद्रा में है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसे कुछ हासिल होगा, क्योंकि एक तो यह गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है और दूसरे, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना यह निर्णय दे चुका है कि इस मामले में कहीं कोई विसंगति नहीं। यह ठीक है कि फ्रांस में इस सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक जांच शुरू हुई है, लेकिन किसी मामले की जांच शुरू होने का यह मतलब नहीं कि आरोपों की पुष्टि हो गई है। बेहतर होता कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी इस जांच के पूरा होने का इंतजार करते। जब तक फ्रांस में होने वाली जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक भारत में उस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं। यह भी ध्यान रहे कि जिस गैर सरकारी संगठन की शिकायत पर यह जांच शुरू हुई है, वह पहले भी इस तरह की कोशिश करता रहा है। तथ्य यह भी है कि यह गैर सरकारी संगठन खुद भी कई आरोपों से घिरा है। कांग्रेस को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि राफेल सौदे को तूल देकर ही उसने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था और उसे मुंह की खानी पड़ी थी। कम से कम राहुल गांधी को तो यह अच्छी तरह याद होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह देश भर में घूम-घूम कर चौकीदार चोर है का नारा प्रचारित किया था और उसके कैसे नतीजे खुद उन्हें और उनकी पार्टी को भुगतने पड़े थे? ऐसा लगता है कि कांग्रेस राफेल मामले में अपनी पुरानी भूल से कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। वह शायद यह भी समझने को तैयार नहीं कि इस मामले को बार-बार उछालने से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला।

यह समझ आता है कि कांग्रेस राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई उस सुनवाई को भूलना पसंद कर रही हो, जिसमें इन लड़ाकू विमानों की कीमत सील बंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई थी, लेकिन उसे अपने आरोपों की गंभीरता तो परखनी ही चाहिए। कांग्रेस एक ओर यह कह रही है कि राफेल विमानों को कहीं अधिक कीमत पर खरीदा गया और दूसरी ओर यह भी पूछ रही है कि आखिर 126 विमानों के बजाय केवल 36 विमान ही क्यों खरीदे गए? ऐसे सवाल पूछने के पहले कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि यदि अधिक मूल्य पर विमान खरीदने का मकसद खुद को या अन्य किसी को अनुचित लाभ पहुंचाना होता तो फिर सौदा 126 विमानों का होता। कांग्रेस यह भी याद रखे तो बेहतर कि राफेल सौदा दो सरकारों के बीच हुआ था और ऐसे सौदे में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है।

## कुपोषित बच्चे

कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाएंगी और कुपोषित बच्चों की जानकारी जुटाएंगी। माता-पिता के साथ मिल-बैठकर उन्हें बताएंगी कि किस तरह बच्चे को कुपोषण के शिकंजे से बाहर निकाला जा सकता है। 'संभव' के नाम से यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। कहना गलत नहीं होगा कि कुपोषण के शिकार बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यह स्थिति दशकों से बनी हुई है। अपेक्षित गति और स्तर पर सुधार नहीं हुआ है। कुपोषण के शिकंजे में आए बच्चों को मुख्य रूप से तीन तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। आयु के अनुरूप शरीर का विकास न होना, कृशकाय होना और रक्त अल्पता। इसके लिए सिर्फ गरीबी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहीं न कहीं, अज्ञानता और बेतहाशा बढ़ती आबादी भी जिम्मेदार है। अज्ञानता इसलिए जिम्मेदार है, क्योंकि खासकर ग्रामीण इलाकों में माता-पिता इस बात से परिचित नहीं हैं कि उन्हें बच्चों को पांच साल तक क्या खिलाना जरूरी है और क्या नहीं खिलाया जाना चाहिए। मां का दूध जीवन रक्षक का काम करता है। कुपोषण से बचाव के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित और मजबूत करता है। बच्चे को मां के दूध से वंचित करना शारीरिक विकास को रोकना है। बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जा सकता है, इसके प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिए जाने की जरूरत है। मलिन बस्तियों में शिविर लगाकर जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण कराए जाने की जरूरत है। कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर दवा के साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध करा कर कुपोषण पर नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार के साथ-साथ सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ सकती हैं। जिन बस्तियों में ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उन्हें यह संस्थाएं गोद ले सकती हैं। दवा के साथ-साथ पौष्टिक खाद्य पदार्थों का वितरण करा सकती हैं। सतत निगरानी और उपचार से कुपोषण पर नियंत्रण के लिए सरकार के प्रयासों को कुछ प्रभावी बनाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है।

> जिन बस्तियों में ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उन्हें सामाजिक एवं स्वयं सेवी संस्थाएं गोद ले सकती हैं

# अपनी जवाबदेही तय करे न्यायपालिका



हृदयनारायण दीक्षित

> कार्यपालिका और विधायिका की जवाबदेही तय है, लेकिन न्यायपालिका किसी निकाय या संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं

लोकतंत्र भारत की जीवनशैली है। संविधान की उद्देशिका में राष्ट्र राज्य की शक्ति का मूल स्रोत 'हम भारत के लोग हैं।' उद्देशिका में भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा है। भारत के लोगों ने प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का संविधान बनाया था। भारत के लोग अपनी प्रभुता का प्रयोग केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल के माध्यम से करते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसे संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि की संवैधानिकता जांचने के अधिकार भी हैं। तीनों संस्थाएं संविधान से शक्ति पाती हैं। चुनाव के माध्यम से नागरिक अपने मन की सरकार चुनते हैं। चुनाव संवैधानिक जनतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन गत सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक कार्यक्रम में कहा, 'चुनाव से सत्ता में आए लोगों को बदलने का अधिकार निरंकुश शासन से बचे रहने की गारंटी नहीं है।' उन्होंने राजनीतिक आलोचना और विपक्ष की आवाज को आदर्श लोकतंत्र प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। यहां तक सब ठीक है, लेकिन उनके वक्तव्य में न्यायपालिका के कामकाज पर कोई सारवान् चर्चा नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश ने तर्कसंगत के साथ अतर्कसंगत विचारों को भी सम्मान देने की अपील की है। इसीलिए उनका ताजा वक्तव्य विश्लेषण योग्य हो गया है। उन्होंने न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही है। साथ ही स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विधायिका या कार्यपालिका द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इससे विधि का शासन छलावा बनकर रह जाएगा। भारत में केवल आपातकाल का समय ही कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के मानमर्दन का काल है। इसके पहले और इसके बाद का काल न्यायपालिका के आदर से भरापूरा है, लेकिन मूल कठिनाई जवाबदेही की है। संविधान सभा में मसौदे पर बहस चल रही थी। सरकार के स्थायित्व और जवाबदेही की बात चली। डॉ. आंबेडकर ने कहा कि 'हमने स्टेबिलिटी (स्थायित्व) के बजाय जवाबदेही (रिस्पांसबिलिटी) को महत्व दिया है।' निर्वाचित सदस्य जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। निर्वाचित कार्यपालिका विधायी सदनों के प्रति जवाबदेह हैं, पर न्यायपालिका किसी निकाय या संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं। उसे भी अपने भीतर जवाबदेही की कोई न्यायिक संस्था का विकास क्यों नहीं करना चाहिए?

विधायन संसद और विधानमंडल का अधिकार है। किसान आंदोलन के दौरान एक नया कुतर्क सामने आया। संसद ने अपनी विधायी क्षमता से कृषि कानून बनाए। कुछ किसान संगठनों ने सरकार पर सलाह न लेने के आरोप लगाए। संविधान में विधि निर्माण के लिए आम जनता से परामर्श की कोई व्यवस्था नहीं है। आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए कोर्ट ने समिति बनाई। समिति ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। काफी समय बीत गया है। कार्रवाई नहीं हुई। न्याय में विलंब अन्याय कहा जाता है। जजों की कम संख्या सहित अन्य अज्ञात कारणवश महत्वपूर्ण मुकदमों में लंबा समय लगता है। श्रीराम जन्मभूमि मामले में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को अंतिम फैसला देने में नौ वर्ष लगे।



अवधेश राजपूत

दल-बदल भारतीय राजनीति की निंदित प्रवृत्ति है। संविधान की दसवीं अनुसूची में दलपरिवर्तन के आधार पर निरर्हता के संबंध में उपबंध है। प्रश्नगत निरर्हता की सुनवाई का कार्य संविधान ने लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा, विधान परिषद के सभापति को सौंपा है। पहले ऐसे मुकदमों की सुनवाई समयबद्ध नहीं थी। बाद में कोर्ट ने अध्यक्षों-सभापतियों के लिए तीन माह में ही सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। शरद यादव के दल-बदल मामले में राज्यसभा के सभापति ने तत्काल फैसला सुनाया, लेकिन कोर्ट में यह मामला काफी समय से लंबित है। सीएए सहित ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण मुकदमे लंबित हैं। भारत के लोग न्यायालयों के प्रति श्रद्धालु हैं। उनकी ऐसी आस्था बनाए रखने के लिए सार्थक कदम उठाए जाने की दरकार है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता उच्चतर संवैधानिक मूल्य है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए जाने के तमाम रक्षोपाय किए थे। नीति निदेशक तत्वों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना राष्ट्र राज्य के लिए आदेश है। सभी संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जरूरी है। सभी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र की सीमा है। इस सीमा के अतिक्रमण से लोकतंत्र का अंतर्संगीत कुप्रभावित होता है। प्रो. अर्नेस्ट बार्कर लोकतांत्रिक शासन के चिंतक हैं। उन्होंने सही लिखा है कि 'स्वतंत्रता के उपभोग में सामर्थ्य और सद्भावना होनी चाहिए। अपनी अस्मिता होनी चाहिए। दूसरों की अस्मिता के प्रति आदर भी होना चाहिए। यह सब संपूर्ण समाज में होना चाहिए। यह होने पर ही वास्तव में लोकतांत्रिक समाज की प्राप्ति संभव है।' कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अपने कार्यक्षेत्र में रहना चाहिए। कुछ समय पहले कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण की सुनवाई के दौरान विशेष प्रकार की गाड़ियों के प्रवेश पर लेवी लगाने के निर्देश दिए थे। कर लगाना न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है।

बंगाल चुनाव के बाद भारी हिंसा हुई। न्यायिक सुनवाई में लोगों की उम्मीदें थीं। विषय महत्वपूर्ण था, लेकिन दो न्यायमूर्तियों ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इसका औचित्य समझ में नहीं आता। मुख्य न्यायाधीश ने वास्तविक लोकतंत्र के विकास के लिए बेशक अच्छी बातें की हैं, लेकिन न्यायपालिका में जरूरी सुधार की आवश्यकता यक्ष प्रश्न है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर भी टिप्पणी की है। कहा है कि 'नए मीडिया टूल में किसी भी बात को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की क्षमता है। वे सही-गलत, अच्छे-बुरे और असली-नकली के बीच फर्क करने में असमर्थ हैं।' उन्होंने ठीक कहा है कि मीडिया ट्रायल मामलों के विचारण में मार्गदर्शक नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि 'न्यायाधीशों को कभी भी भावुक राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए।' उन्होंने कोरोना महामारी पर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 'हमें आवश्यक रूप से खुद से पूछना होगा कि हमने अपने लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून के शासन का किस हद तक इस्तेमाल किया।' ऐसा आत्मचिंतन समय की मांग भी है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

# चौतरफा गहरे संकट से घिरा नेपाल



केसी त्यागी

> नेपाली संसद में बहुमत खोने के बावजूद पीएम ओली बाज नहीं आ रहे और अटपटे फैसले करने में लगे हैं



अपने रवैये से सवालों के घेरे में नेपाली पीएम ओली। फाइल

नेपाल एक बार फिर राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक के साथ-साथ विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रहा है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कुछ हालिया फैसलों ने न केवल नेपाल को उपहास का पात्र बनाया, बल्कि नेपाली लोकतंत्र की बुनियाद भी हिला दी है। नेपाल में लोकतंत्र की पहली बयार 1951 में चली, जब 104 वर्ष की राणाशाही का अंत हुआ और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। राणा वंश से पूर्व शाहवंश का शासन था। वर्ष 1955 में महाराजा त्रिभुवन की मृत्यु के बाद महाराजा महेंद्र का राजतिलक हुआ। फिर 1959 में संविधान लागू किया गया और आम चुनाव हुए। चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन राजवंश को नई लोकतांत्रिक व्यवस्था रास नहीं आ रही थी। लिहाजा राजा महेंद्र ने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। संसद एवं संविधान भी भंग कर दिए गए और दल विहीन पंचायत प्रणाली शुरू की गई। लंबे समय तक ऐसी राजनीतिक उठापटक से जूझते हुए अप्रैल 2008 में आखिर राजशाही की आधिकारिक तौर पर समाप्ति हुई। संवैधानिक सभा के लिए चुनाव हुए। जुलाई 2008 में माओवादी नेता प्रचंड के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। नेपाली कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। एक प्रशासनिक भूल के कारण प्रचंड को तब इस्तीफा देना पड़ा, जब मई 2009 में उन्होंने सेनाध्यक्ष रूकमांगद कटवाल को पद से बर्खास्त कर दिया था।

यह भी एक तथ्य है कि नेपाली कम्युनिस्ट उस चीनी वामपंथी विचार को गलत साबित कर चुके हैं कि सत्ता का जन्म बंदूक की नोक से होता है। जब प्रचंड के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'एमाले' ने मिलकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) का गठन किया तो लगा था कि उनके नेतृत्व में स्थायी सरकार बनेगी। चुनाव नतीजों ने जनता को भी उत्साहित किया, क्योंकि पांच दशकों के बाद पहली बार किसी ऐसी सरकार का गठन हुआ, जो बिना किसी बाधा के अपना कार्यकाल पूरा करती दिख रही थी। एनसीपी ने दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। बड़ा दल होने के नाते केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी की कमान प्रचंड को सौंपी गई। हालांकि नेपाल में संवैधानिक समस्याओं, मर्यादा, आचार संहिता और मूल्यों का इतना ह्रास कभी देखने को नहीं मिला, जितना संयुक्त कम्युनिस्ट नेताओं के कार्यकाल में दिखा। ओली को पहले 'भारत समर्थक' नेता माना जाता था, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने सीमा और जल विवाद जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। उनके रवैये के कारण कई बार सीमा पर तनातनी जैसी स्थिति बनी।

मई 2020 में जब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धारचूला के बीच सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल सरकार द्वारा देश का नया नक्शा जारी कर एक अजीब संकट पैदा कर दिया गया। मार्च 1816 की सुगौली संधि का हवाला देकर ओली ने कथित तौर पर अपनी जमीन वापस मांगी। यह वह दौर था जब नेपाल के तराई इलाकों के नागरिकों को भयंकर यातना एवं अभावों से जूझना पड़ा था। मधेशियों के समर्थक दलों को ओली सरकार के विरुद्ध कई महीने संघर्ष करना पड़ा। वही ओली सरकार अब अल्पमत में आने के बाद तराई के संगठनों की मदद से ही वजूद बनाए हुए है। यह तब है जब ओली ने ही राजनीतिक अवसरवाद के चलते पहले मधेशियों की पार्टी समाजवादी जनता पक्ष में विभाजन कराया और उपप्रधानमंत्री समेत दर्जनों मंत्रियों को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद कर उन्हें असंवैधानिक करार दिया। उसका कहना था कि संसद भंग होने के बाद कैबिनेट विस्तार अवैध है। चूंकि कोई भी कार्यवाहक सरकार चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के पक्ष में बताया जा रहा है, लेकिन यह कहना कठिन है कि भविष्य का घटनाक्रम नेपाल में लोकतंत्र को मजबूती देगा।

इससे पहले एनसीपी में मतभेद और दूरी के पीछे भी ओली का अलोकतांत्रिक और मनमाना रवैया ही जिम्मेदार माना गया। उन्होंने अपने विरोधियों से निपटने और अपने हितों की पूर्ति में ही पूरी ऊर्जा लगा दी है। इसके लिए उन्होंने चीन का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं किया। फिर भी वह प्रतिनिधि सभा यानी संसद का विश्वास नहीं हासिल कर सके। परिणामस्वरूप अब अल्पमत सरकार चला रहे ओली ने नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा की है। अब देखना यही होगा कि चुनाव नतीजे क्या कहते हैं?

संसद में बहुमत खोने के बावजूद ओली अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनका आचरण प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने के साथ ही नेपाल को शर्मसार करने वाला है। वैसे तो मार्क्सवादी स्वयं को नास्तिक मानते हैं, लेकिन ओली ने न केवल भगवान राम की महत्ता को स्वीकारा, बल्कि भारत से धार्मिक प्रतिस्पर्धा में नेपाल को श्रीराम की वास्तविक जन्मभूमि होने का अटपटा दावा तक कर दिया। अपने ऊल जलूल बयानों में उन्होंने यहां तक कह दिया कि योग का उद्भव भी नेपाल में ही हुआ था।

आज नेपाल आर्थिक मोर्चे पर भी संकट से गुजर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार नेपाल में बाहर से आने वाले पैसे में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। लंबे समय से नेपाली नागरिकों का काम के सिलसिले में बाहर जाना लगभग बंद हो गया है। तकरीबन एक लाख से अधिक नेपाली नागरिक स्वदेश आ चुके हैं। ध्यान रहे कि नेपाली अर्थव्यवस्था में प्रवासी नेपालियों के अंशदान की अहम भूमिका रही है। नेपाल के मौजूदा हालात के कारण कम्युनिस्ट दलों की बहुत किरकिरी हो रही है, जिन्हें राजशाही का एक सशक्त विकल्प माना गया था। यही कारण है कि नेपाल में अब राजशाही वापस लाने के पक्ष में भी कुछ आवाजें उठनी लगी हैं।

(लेखक पूर्व सांसद हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

## परिवार का महत्व

परिवार समाज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार ही व्यक्ति के जीवन की प्रथम पाठशाला है, जहां वह पहला शब्द, ज्ञान और आचरण सीखता तथा अपने जीवन में उतारता है। परिवार का सही मार्गदर्शन ही हमें ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाता है। इसके विपरीत परिवार का उचित मार्गदर्शन न मिलने पर व्यक्ति पथभ्रष्ट भी हो जाता है। परिवार एक ऐसा वृक्ष है, जिसमें विश्वास और प्रेम एक साथ फलते-फूलते हैं। ये विश्वास और प्रेम ही हैं कि एक बालक बीमार होने पर अपने पिता की दी हुई कड़वी दवा भी आंख बंदकर पी जाता है, क्योंकि उसे उस दवा से ज्यादा भरोसा अपने पिता पर होता है।

एक बार स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज से किसी दंपती ने कहा कि 'हम लोग बहुत दुखी हैं। हमने तो अपना सारा जीवन ही अपने बच्चों के पालन-पोषण में लगा दिया। यहां तक कि अपना सारा पैसा बच्चों के लिए ही खर्च कर दिया। कभी खुद के लिए समय ही नहीं निकाला। न ही कभी देशाटन या तीर्थ के लिए सोचा, मगर आज यही बच्चे हमारा हाल तक नहीं पूछते हैं।' स्वामी जी ने उनकी बातें सुनने के बाद कहा कि 'वे आपकी आज्ञाकारी संतानें हैं। इसीलिए वे अब आपकी बातें नहीं सुनते हैं, क्योंकि आपने भी तो उन्हें यही शिक्षा दी कि अपनी संतान ही सब कुछ है। आज वे उसी पाठ को दोहरा रहे हैं।' सत्य ही है बच्चे परिवार को देखकर ही सीखते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार की प्रत्येक इकाई हर दूसरी इकाई का महत्व समझे यह संस्कार भी हमें परिवार के लोगों से ही मिलता है। परिवार का अर्थ है कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा है, जो जीवन के कठिन संघर्ष में हमारे साथ खड़ा है। इसलिए तरक्की के रास्ते पर भी परिवार के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही परिवार वास्तव में हमारी प्रगति का आधार बनता है।

अंशु प्रधान

# फर्जी विश्वविद्यालयों के भंवर में छात्र

रोहित कौशिक

> सरकारें संदिग्ध शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई करें, ताकि छात्रों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाए जा सके

पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और शिक्षा सचिवों को फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची भेजते हुए उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पूरे देश में 24 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों की डिग्री वैध नहीं है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में हजारों छात्र इनके भंवर में फंस जाते हैं। ये विश्वविद्यालय हाल में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि कई वर्षों से चल रहे हैं। सवाल यह है कि कई वर्षों से चल रहे इन फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इनके संचालकों की धरपकड़ कर इन अवैध विश्वविद्यालयों को बंद क्यों नहीं कराया जाता? जानकारी होते हुए भी ऐसे विश्वविद्यालयों को कार्य करते देना और उनके संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना तो और भी बड़ा अपराध है।

कुछ वर्ष पहले देश में शिक्षण संस्थानों को अवैध रूप से मान्यता देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में एआइसीटीई के उपनिदेशक को गिरफ्तार किया गया था। स्पष्ट है कि शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार को बढ़ाने में इस क्षेत्र से जुड़े कुछ अधिकारी और विभिन्न समितियों में स्थान प्राप्त कुछ शिक्षक भी अपनी भूमिका निभाते हैं। दरअसल कुछ निजी शिक्षण संस्थानों के मालिक प्रभावशाली लोग होते हैं इसलिए प्रशासन की ओर से इस मामले में जानबूझकर चुप्पी साध ली जाती है। ऐसे मामलों में जितने दोषी विश्वविद्यालयों के संचालक हैं उतने ही दोषी सरकार और उससे जुड़े अधिकारी भी हैं।

देखा जाए तो आज शिक्षा तंत्र में अनेक विसंगतियों ने जन्म ले लिया है। एक ओर शिक्षा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की लालसा शिक्षा को व्यापार का रूप दे रही है तो दूसरी ओर शिक्षा जगत से जुड़े माफिया ने शिक्षा को एक मजाक बनाकर रख दिया है। अंग्रेजों ने भारत में जिस शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ किया था उसके पीछे उनकी अपनी आवश्यकताएं थीं। आजादी के बाद कुछ हद तक इस शिक्षा नीति की कमजोरी को दूर करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए। एक बार फिर शिक्षा नीति में परिवर्तन की कोशिशें हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा नीति में परिवर्तन करना है या फिर इस परिवर्तन के माध्यम से शिक्षा की कमजोरियों को दूर करना है? हमारे नीति-निर्माताओं की नीतियों एवं क्रियाकलापों को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा नीति में परिवर्तन करना भर है।

अब समय आ गया है कि सरकारें निजीकरण की आड़ में पनपे संदिग्ध विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के क्रियाकलापों पर गंभीरता से ध्यान दें, ताकि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाए जा सके।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### मुख्यमंत्री बदलने की बीमारी

'उत्तराखंड में फिर बदलाव' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में यह उचित ही कहा गया है कि उत्तराखंड में एक और बार नेतृत्व परिवर्तन से यही प्रकट हुआ कि भाजपा ने करीब चार महीने पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था तो पर्याप्त सोच-विचार नहीं किया था। अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं तो भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि वह पार्टी और सरकार के समक्ष चुनौतियों को कैसे दूर कर पाते हैं। आगामी चुनाव में भाजपा की संभावनाएं बहुत हद तक इस पर भी निर्भर करेंगी। हालांकि लगता नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी की आगे की राह आसान होगी, क्योंकि उनकी ताजपोशी से प्रदेश के कई मंत्री-विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। किसी भी सरकार की सफलता का पहला सूत्र तो यही होता है कि विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में तालमेल होना चाहिए। सच तो यह है कि एक छोटे से राज्य उत्तराखंड में भाजपा कई गुटों में बंटी हुई है। यह अलग बात है कि केंद्रीय नेतृत्व की सख्ती के कारण यह सतह पर नहीं आता है, लेकिन अंदरखाने हर गुट एक-दूसरे को नीचा दिखाने का अवसर खोजता रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी बार-बार मुख्यमंत्री बदलने की नौबत नहीं आती। भले ही पार्टी यह काम आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर कर रही है, लेकिन यह भी सही है कि इसका प्रदेश की जनता में गलत संदेश जा रहा है। अगर आगामी चुनाव में भाजपा कमजोर प्रदर्शन करती है तो इसकी एक वजह नेतृत्व के स्तर पर यह अस्थिरता भी होगी। दुख की बात है कि शीर्ष स्तर पर यह अस्थिरता राज्य के विकास को भी प्रभावित कर रही है।

कमलेश सिंह, देहरादून

### शारीरिक दूरी का रखें ख्याल

कोरोना को लेकर लाकडाउन से अनलाक की शुरुआत हो चुकी है, पर इसके पहले चरण में देश के अलग-अलग शहरों से मुश्किल खड़ी कर देने वाली तस्वीरों का सामने आना खतरे से खाली नहीं है। निःसंदेह ऐसी तस्वीरें महामारी के तीसरे चरण को अपने पैर पसारने में मदद करेंगी। अनलाक का मकसद शारीरिक दूरी का पालन करते हुए लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, सरकार की ऐसी मंशा थी, पर बिना मास्क वाले सैकड़ों की तादात में देश की अलग-अलग हिस्सों से आई तस्वीरें, बिना किसी सतर्कता के बाजारों का खुलना सरकार की मंशा को धूमिल करती नजर आ रही हैं। यही लापरवाही रही तो वह दिन दूर नहीं जब महामारी के तीसरे चरण का सामना करना पड़े। ऐसे में यदि हमें महामारी से खुद को बचाते हुए पूरे समाज को बचाना है तो उचित सतर्कता के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर उचित दूरी बनानी होगी। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है।

रितिक सविता, दिल्ली

### अतिक्रमण और अवैध कब्जे

अतिक्रमण और अवैध कब्जे लगातार हो रहे हैं। इससे देश को बड़ी हानि और आम जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, घटती प्रशासनिक मशीनरी और भ्रष्टाचार से यह सब जारी है। अजीब बात तो यह है कि आज जो अतिक्रमण या अवैध कब्जा बड़ी मुश्किल से हटाया भी जाता है, अगले ही दिन धड़ल्ले से कर लिया जाता है। इसे रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सारी कवायद ही बेकार होती है। इसमें न जाने कितने धन और समय की बर्बादी ही होती है। आज फरीदाबाद और दिल्ली की सीमा से लगे पहाड़ी क्षेत्र के खोरी गांव में बने लगभग दस हजार मकानों की समस्या चर्चा में है, जो सुलझती ही नहीं दिखाई देती। असल में इसके लिए जिम्मेवार सभी अफसरों और लोगों को दंडित करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सरकार को तुरंत जनसंख्या पर लगाम लगाते हुए सभी अवैध कालोनियों पर रोक लगा कर इनके व्यापक सुधार के साथ सड़कों, गलियों और फुटपाथों की चौड़ाई आदि का पुनः सख्ती से निर्धारण करना होगा, वरना तो देश ऐसे ही बिना किसी पारदर्शी योजना के नरक बनता रहेगा।

वेद मामूरपुर, नरेला

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल

# ग्रीस के जरिये भारत का भूमध्यसागरीय राजनय



विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

**भारत और ग्रीस के मध्य संबंध आजकल सुर्खियों में है। दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और महत्वपूर्ण गठजोड़ों के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने के लिए सहमत हुए हैं। यूरोप के देशों के बीच बेहतर अवसंरचना और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को आकार देने, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने समेत किसी भी प्रभुत्ववादी मानसिकता वाले देश से क्षेत्रीय स्थिरता को बचाने के लिहाज से भारत ने ग्रीस की महत्वपूर्ण भूमिका का आकलन किया है। पिछले 18 वर्षों में यह पहला अवसर है जब ग्रीस के साथ संबंधों को नई दिशा देने के लिए भारतीय कूटनीति को गतिशील बनाया गया है**



भारत व ग्रीस के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ग्रीस के विदेश मंत्री निकोन डेंडियास के बीच पिछले सप्ताह बातचीत हुई। इंटरनेट मीडिया

पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत के राजनय को अधिक मजबूती देने और अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए पिछले 18 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री ने ग्रीस की यात्रा की है। ग्रीस के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हों, इसके लिए भारत सरकार के मन में यह चल रहा था कि ग्रीस के साथ भारत के संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया जाए और हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों देशों में यह सहमति बनी कि वर्तमान विश्व और क्षेत्रीय राजनीति की भू-राजनीतिक, भू-सामरिक और भू-आर्थिक सच्चाइयों को देखते हुए दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की जाए। हाल ही में जब भारत के विदेश मंत्री द्वारा ग्रीस से चर्चा शुरू हुई तो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकल कर आए। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह आया कि ग्रीस ने भारत के नेतृत्व वाले 'इंटरनेशनल सोलर अलायंस' में शामिल होने की घोषणा की। ग्रीस का यह निर्णय इस लिहाज से अहम है कि इससे चीन के साथ ग्रीस के एनर्जी पार्टनरशिप को सही दिशा देने का एक नैतिक दबाव भी पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन एक नियम आधारित और बेहतर सार्थक लक्ष्यों वाला संगठन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीजिंग स्थित ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ ऊर्जा साझेदारियां होती रही हैं। ऐसे में ग्रीस भारत के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा विजन में सहयोग दे सकेगा। भारत वैश्विक ऊर्जा ग्रिड की भी संकल्पना पेश कर चुका है। ग्रीस और उसके पड़ोस के राष्ट्रों में भारत की सोच को समर्थन, सम्मान मिले, इसके लिए विकसित हो रहे भारत ग्रीस संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं।

**भारत ग्रीस संबंध और चीन समीकरण :** ग्रीस यूरोप में चीन का महत्वपूर्ण आर्थिक सामरिक सहयोगी रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। यूरोप में चीन के 'बेल्ट रोड' पहल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ग्रीस है। ग्रीस ने अपने पीरियस बंदरगाह को चीन द्वारा संचालित करने की मंजूरी भी दे दी है। चीन के शिपिंग फर्म कोस्को को 2016 में इस बंदरगाह में सर्वाधिक हिस्सेदारी भी मिली थी। यह बंदरगाह एशिया और यूरोपीय महाद्वीपों के मध्य सामरिक महत्व की जगह पर अवस्थित है। भारत के विदेश मंत्री ने ग्रीस के विदेश मंत्री के साथ इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र, साइप्रस और लीबिया में घटित घटनाओं पर चर्चा की और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रयासों को खोजने पर बल दिया। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि विधि के शासन, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता के प्रति सम्मान के महत्व को राष्ट्र समझें। कट्टरता, हिंसक उग्रवाद, आतंकवाद और खासकर सीमा पार आतंकवाद के द्वारा सामने आए खतरों की गंभीरता पर दोनों देशों ने बात की और सहमत हुए कि इस संबंध में मिल-जुल कर कार्य करने की जरूरत है।

ग्रीस ने भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और साथ ही संयुक्त राष्ट्र की संरचना और कार्यों में अपेक्षित सुधारों के लिए भी अपनी मंशा जाहिर की। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को पाने के लिए प्रयास में लगा है, पर उसे चीन और उसके कॉफी क्लब समेत कई अन्य देशों के विरोध का सामना करना पड़ता है। दरअसल कॉफी क्लब के सदस्य नहीं चाहते कि जी-4 देश (भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील) सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन पाएं। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जिसे कॉफी क्लब भी कहते हैं इसमें 12 देश शामिल हैं। इसमें मुख्य हैं, पाकिस्तान, तुर्की, इटली, मेक्सिको, अर्जेंटीना, इजिप्ट, स्पेन। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार का ये देश विरोध करते हैं।

**भारत का विजन :** भारत के विदेश मंत्री ने ग्रीस के साथ भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक वास्तविकताओं पर चर्चा की। भारतीय राजनय की यही कुशलता है कि इस चर्चा के दौरान भारत ने ग्रीस को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और विजन के महत्व को इस प्रकार समझाया कि ग्रीस ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक विजन पर हस्ताक्षर कर दिया। भारत ने ग्रीस को जिस रूप में मुक्त, खुले, समावेशी और सहयोगी इंडो पैसिफिक रणनीति के बारे में अपनी राय व्यक्त की, उसका असर ग्रीस पर पड़ा। अभी कुछ समय पूर्व ही ग्रीस और उसके पड़ोसी तुर्की के बीच सागरीय क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर विवाद हो गया था। तुर्की ने ग्रीस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर अपना दावा कर दिया था और ग्रीस ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सागरीय नियमों व कानूनों के तहत उस पर ग्रीस का ही अधिकार है। निश्चित रूप से भारत जिस प्रकार सभी देशों की सागरीय संप्रभुता और स्वायत्तता का समर्थन करता रहा है, ग्रीस भारत की उस उच्च कोटि की प्रतिबद्धता से परिचित रहा है। भारत ने अपने मजबूत सामरिक साझेदार ब्रिटेन की नाराजगी को न देखते हुए कुछ समय पहले चागोस द्वीप पर मॉरीशस के जायज हक का समर्थन किया था। ग्रीस के भी जायज सागरीय हक में भारत अपनी आवाज उठा सकता है, ऐसा ग्रीस को लगता है। नाटो सदस्य ग्रीस और तुर्की के बीच ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे को लेकर पिछले कुछ समय से युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे हालात तब भी पैदा हुए थे जब पिछले साल ग्रीस ने एक छोटे मगर रणनीतिक रूप से बेहद अहम द्वीप कास्टेलोरिजो में अतिरिक्त सैन्य बल भेज दिया था।

वर्ष 1982 के 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' के हिसाब से ग्रीस को दोनों देशों के बीच के और विवादित द्वीप साइप्रस के आसपास भूमध्यसागर में ज्यादा हिस्सा मिलता है। तुर्की इस बात को भी नहीं मानता। पूर्वी भूमध्यसागर में तुर्की का एक अहम रुख पूर्वी भूमध्यसागरीय गैस फोरम (ईएमजीएफ) से इसे बाहर रखे जाने को लेकर है। इस फोरम का गठन जनवरी 2019 में कायरो में हुआ था और इसे 'भूमध्यसागरीय गैस के ओपेक' की संज्ञा दी गई थी। इस फोरम में ईजिप्ट, ग्रीस, साइप्रस, इजरायल, इटली, जॉर्डन और फिलिस्तीन शामिल हैं।

ग्रीस के पड़ोस में स्थित साइप्रस में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया था, जब तुर्की ने 1974 में अपनी सेनाओं द्वारा साइप्रस पर किए गए हमले की वर्षगांठ मनाने की योजना बनाई। साइप्रस और यूरोपीय संघ ने तुर्की से आग्रह किया था कि वह इस क्षेत्र में ऐसा करके तनाव न पैदा करे। यहां तनाव इसलिए भी बढ़ता दिख रहा था, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने उत्तरी साइप्रस जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के रूप में भी जानते हैं, उसकी यात्रा करने और नॉर्दर्न टर्किश साइप्रस इकाई के अस्तित्व में आने की वर्षगांठ मनाने का निर्णय किया।

भारत ने जिस तरह से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साइप्रस और लीबिया का उल्लेख करते हुए ग्रीस से चर्चा की और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों की शुचिता बनाए रखने की बात की, उससे साफ है कि तुर्की को भी भारत एक संदेश देना चाहता था। तुर्की की सरकार को डर है कि पूर्वी भूमध्यसागर का इस्तेमाल तुर्की को अलग-थलग करने की कोशिशों में किया जा रहा है। ग्रीस और साइप्रस ने यूरोपीय संघ से तुर्की की कार्रवाई के खिलाफ समर्थन की मांग की है और इनके साथ ही तुर्की के क्षेत्रीय विरोधी भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं।

इस बीच भारत में अनुच्छेद 370 और कश्मीर मुद्दे पर तुर्की का हठधर्मी रवैया भारत के खिलाफ और पाकिस्तान चीन जैसे देशों के पक्ष में रहा है, इसलिए भारत ने भी तुर्की को परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन उस पर दबाव बनाने की कोशिश की है। तुर्की जिस तरह से अफगानिस्तान में भी रुचि ले रहा है और जिस तरह अब वहां के 100 से अधिक जिलों को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है, उस दृष्टि से तुर्की और भारत के संबंध और भी संवेदनशील हो जाते हैं।

## दोनों देशों के बीच संबंधों की पृष्ठभूमि

भारत की आजादी के बाद वर्ष 1950 में दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, वर्ष 1968 में भारत ने एथेंस में अपना दूतावास खोला। वर्ष 2020 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए, वहीं इसी वर्ष ग्रीस की आजादी के 200 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने ग्रीस को बधाई दी। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार करीब 60 करोड़ डॉलर का है। भारत की कई कंपनियां ग्रीस में मौजूद हैं। इनमें आइटी और निर्माण जैसे क्षेत्रों की 10 कंपनियां शामिल हैं। दोनों देशों के बीच वर्ष 2017 में पहली सीधी उड़ान शुरू करने को लेकर एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। उड़ान संबंधी करार से भारतीय विमानन कंपनियों को एथेंस, थेस्सलोनिकी और हेराक्लियन की सेवा शुरू करने की अनुमति मिलेगी।

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, ग्रीस में 11,333 प्रवासी भारतीय रहते हैं। वर्ष 2010 के बाद ग्रीस के आर्थिक रूप से लगातार कमजोर होने के बाद कई भारतीय समुदाय के लोग अन्य ईयू देशों की तरफ भी रुख करते पाए गए थे। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने ग्रीस के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने की कोशिश की है। कोलकाता और वाराणसी में दो ग्रीक सेंटर भी हैं और एथेंस में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई केंद्रों का भी निर्माण किया गया है। ग्रीक नृत्य और संगीत को बढ़ावा देने की कोशिश जहां एक तरफ की गई है वहीं योग, कत्थक और कथकली को भी बढ़ावा देने के प्रयास ग्रीस में किए गए हैं। भारत और ग्रीस के संबंधों का महत्व इस लिहाज से भी है कि भारत को ग्रीस सहित सभी यूरोपियन यूनियन सदस्यों का सहयोग चाहिए, ताकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लंबित मुक्त व्यापार समझौते को मूर्तमान बनाना आसान हो सके। ग्रीस यूरोपीय संघ में एक अहम भूमिका रखता है और भारत के हितों पर प्रभावशाली राय पेश करता है। ग्रीस ने एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया समूह और वासनेर व्यवस्था जैसे निकायों में भारत की सदस्यता का समर्थन किया था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के आग्रह के बाद यूरोपीय संघ के जिन आठ देशों और स्विट्जरलैंड ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है, उसमें ग्रीस भी शामिल है। ग्रीस के अलावा यूरोपीय संघ के देशों ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और एस्टोनिया व गैर ईयू सदस्य देश स्विट्जरलैंड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल किया है।

खरी-खरी

## व्यस्त लोगों की दुनिया

भूपेंद्र भारतीय

व्यस्त लोगों की दुनिया भी विचित्र घटनाओं से भरी चलती है। आप वर्तमान समय में व्यस्त भले न हो, पर लोगों की नजर में दिखना जरूर चाहिए। आपका कोई मित्र मिलने आए और आप उसको फोकटिया टाईप टीवी देखते मिल जाओ, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा।

मेरे एक मित्र ने 'व्यस्त' दिखने के लिए अपने घर की छत पर एक छोटी-सी वाटिका तैयार कर ली। एक दिन उसी मित्र से मिलने गया। भले ने मिलने के लिए एक घंटा प्रतीक्षा करवाई। और ऊपर से कहता है क्षमा करना यार, आजकल व्यस्तता बढ़ गई है। इतने सारे काम हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल जाता है। ऊपर से इन पौधों का भी ध्यान मुझे ही रखना पड़ता हैं।

कुछ लोग स्वयं को हमेशा ही व्यस्त दर्शाने के उपक्रम में लगे रहते हैं। हालांकि वे कुछ सार्थक नहीं करते, फिर भी समाज में इनकी बड़ी इज्जत होती है। इन्हें फोन करो तो फटाक से कहते हैं, अभी बिजी हूं? थोड़ी देर में लगाता हूं आपको फोन। लेकिन वह थोड़ी देर फिर आता नहीं है।

किसी भी कार्यक्रम में देर से पहुंचना इनकी 'व्यस्तता' का पैमाना है। इन्हें लगता है कि देर से पहुंचने पर लोग इज्जत करते हैं। जैसे नेताओं के देर से आने की आदत के कारण उनका मान-सम्मान होता है और उन्हें बड़ा आदमी माना जाता है।

व्यस्त रहो और मस्त रहो, नारे का असली आनंद यही व्यस्त रहने वाले महामानव ले रहे हैं। ऐसे ही व्यस्त लोगों से हमारे देश के सरकारी भवन भरे पड़े हैं। शिक्षा संस्थानों के आसपास घास काटते ऐसे व्यस्त नौजवान आसानी से देखें जा सकते है। इनकी व्यस्त दिनचर्या में सरकारी फाइलों को तकिया बनाकर व्यस्तता को जीवंत रखा जाता है।

आजकल व्यस्तता का पावर-पैक हर किसी ने अपने मोबाइल में डलवा लिया है, ऐसा लगता है जैसे दसों दिशाओं में कुकुरमुत्तों की तरह व्यस्त लोगों का खेला हो रहा है। इनकी व्यस्तता जंगल के उस सरपंच (बंदर) की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदा-फांदी करता रहता है, पर उसकी नीयत सभी जानते हैं।

खैर, आजकल की इस 'व्यस्त' दिनचर्या में मानव आखिर कितना व्यस्त रहे और कितना दिखे, यह शोध का विषय है।

ट्वीट-ट्वीट

अरे भई असदुद्दीन ओवैसी साहब आप कितनों को हटाएंगे? बिहार में नीतीश कुमार को हटा रहे थे। देश में नरेंद्र मोदी को हटा रहे थे और अब यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कर रहे हो। बेहतर है कि खुद ही हट जाओ तो इज्जत बच जाएगी। डॉ. अजय आलोक@alok_ajay

जब हम शादी करते हैं तो भी खुशी जताते हैं। जब साथ में रहते हैं तो भी खुद को खुश ही बताते हैं। फिर जब तलाक लेते हैं तो भी कहते हैं कि हम खुश हैं। ऐसा कहने वाले लोग सरासर झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि कोई भी हर हालात में खुश नहीं रह सकता।
तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

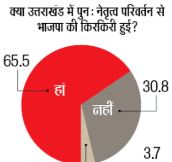


मिताली राज ने दिखा दिया कि युवा प्रतिभाओं को लेकर उत्साह दिखाने की राह में हमें अपने अनुभवी सितारों को लेकर धैर्य नहीं खोना चाहिए। युवाओं को प्रोत्साहित करिए, लेकिन वरिष्ठ खिलाड़ियों की भी अनदेखी न हो। यह क्रिकेट की सबसे पुरानी सीख में से एक है।
मोहम्मद कैफ@MohammadKaif

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पूर्वोत्तर के पहले ऐसा नेता हैं, जिनकी चर्चा हिंदी बेल्ट में भी हो रही है। चर्चा केवल उनके कामकाज की ही नहीं, बल्कि उन्हें हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है। आश्चर्य तब हुआ जब मेरे गांव में कुछ लोगों ने उनके बारे में ऐसी चर्चा की, जैसे वे उन्हें वर्षों से जानते हों।
नीरज पांडेय@NirajPandeyLive

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या उत्तराखंड में पुन: नेतृत्व परिवर्तन से भाजपा की किरकिरी हुई?




सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**
क्या केंद्रीय स्तर पर दो बच्चों की नीति अनिवार्य की जानी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

परदे पर कुछ और है जीवन में कुछ और,
शादी और तलाक तो जैसे मुंह का कौर।
जैसे मुंह का कौर लोग बनते उपदेशक,
खुद अपना परिवार न संभले उनसे बेशक!
सात जनम का साथ प्रभू झोली में भर दे,
फिर तो सब उकताय मरेंगे नकली परदे!!
– ओमप्रकाश तिवारी

# यूपी में तैयार हुआ तीसरी लहर का चक्रव्यूह



राजू मिश्र
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर पर नियंत्रण के आंकड़े अब उत्साहजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। दावा किया गया है कि प्रदेश को झकझोरने वाली दूसरी लहर पर लगभग काबू पा लिया गया है। साथ ही संभावित तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार कर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, कि संक्रमण को इसे भेदने का मौका ही न मिले। यह एक खुला तथ्य है कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रति बेपरवाही का हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। हजारों जानें गईं, लोगों की माली हालत खस्ता हुई और आंशिक कर्फ्यू ने समग्र अर्थव्यवस्था पर अधिक असर नहीं डाला लेकिन इसके दुष्परिणाम खुदरा कारोबारियों को उठाने पड़े हैं। हालांकि, अब यह बीते दिनों की बात है। इसलिए अब बीती बातों से सबक लेकर आगे की सुधि लेने का समय है।

शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े आए हैं, वह यह बताने के लिए काफी हैं कि दूसरी लहर अब दम तोड़ रही है। शनिवार को प्रदेश के 75 में से 36 जिले ऐसे रहे जहां कोरोना का एक भी संक्रमित रोगी नहीं मिला। 37 ऐसे जिले रहे जहां 10 से भी कम मरीज मिले। अब सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रयागराज ही ऐसे जिले हैं जहां 10 या उससे अधिक मरीज मिले। लखनऊ में नए मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 17 और प्रयागराज में यह आंकड़ा 10 पर रहा। औसत रूप से देखें तो प्रदेश में 75 जिलों के मुकाबले 112 संक्रमित मिले। इसी तरह की जानकारी मृत्यु दर की है। शनिवार को सिर्फ सीतापुर और चंदौली में ही एक-एक मरीज की मौत हुई। एक्टिव केस, पाजिटिविटी रेट और रिकवरी रेट भी उत्साहजनक है। यही वजह है कि सोमवार से प्रदेश सामान्य कामकाज की ओर पूरी गति से लौटने लगेगा। राजस्व न्यायालयों की गतिविधियां भी शुरू की जा रही हैं और लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए थाना व तहसील दिवस जैसे प्रशासनिक आयोजन शुरू करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इस हिदायत के साथ कि कोरोना से बचाव के उपायों का सख्ती से पालन करते हुए ही इसे फिर से शुरू किया जाए।



अस्पतालों में तैयारियों का जायजा ले रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फाइल

रोजमर्रा की जीवनचर्या की इस शुरुआत का आशय यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम एक बार फिर निश्चिंत हो जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना बिल्कुल उचित है कि हम कोरोना पर नियंत्रण के नजदीक हैं, लेकिन सावधानी बरतने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की बात कही जा रही है। इस खतरे से निपटने के लिए प्रदेशभर में अब तक 6324 पीडियाट्रिक आइसीयू (पीकू) के बेड तैयार किए जा चुके हैं। जल्दी ही प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदेश के देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मीरजापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में नए तैयार मेडिकल कालेजों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी तैयार है। संभवतः यह इसी माह शुरू हो जाएंगे। इनके लिए 70 फीसद फैकल्टी का चयन हो चुका है। 450 से अधिक संकाय सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी 13 नए मेडिकल कालेजों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है।

कोई संदेह नहीं कि दूसरी विनाशकारी लहर के बाद प्रदेश सरकार ने जिस तेजी से तीसरी लहर को नियंत्रित करने की तैयारी की है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन इन तैयारियों का अपेक्षित परिणाम तभी निकल सकता है जब आम नागरिक और ग्रामीण अपनी भूमिका को पिछले अनुभवों के आधार पर आचरण में उतारें। पहली लहर के बाद जिस तरह लोग लापरवाह हुए थे, उसकी अपेक्षा इस बार लोग भी जागरूकता दिखा रहे हैं। बाजारों में शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा। अब भी काफी संख्या में लोग मास्क को सही तरह से लगाने के प्रति सचेत नहीं दिख रहे। मास्क या तो ठोढ़ी या गर्दन पर अटका रहता है। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने में भी व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। आटो-टेम्पो और कम दूरी की बसों में शारीरिक दूरी का पालन तो कतई नहीं हो पा रहा। कुछ हद तक यह संसाधनों के अभाव की विवशता भी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मास्क के सही उपयोग, खुद के सैनिटाइजेशन के साथ घर में दाखिल होने से पहले खुद को पहले पूरी तरह विसंक्रमित करने की प्रक्रिया में ढिलाई नहीं आनी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तैयारियों और हिदायतों के साथ यदि हम तीसरी लहर से मुकाबले के लिए मुस्तैद होंगे तो संभव है कि आशंकाओं पर विजय पायी जा सके। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना और बच्चों के लिए टीके का सफल होना आवश्यक है।

अपनी बात

# सौंदर्यशास्त्र के इन पुजारियों से बच कर रहिए

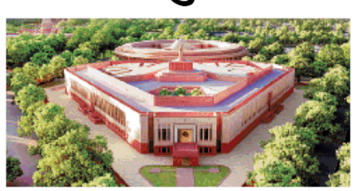


ब्रजबिहारी
brij.choube@nda.jagran.com

उम्मीद की जानी चाहिए कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब इसके निर्माण कार्य को रोकने के लिए कानूनी दांवपेच का सहारा ले रहे लोगों को सद्बुद्धि आ जाएगी और वे राष्ट्रीय महत्व की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विरोध करना छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज करते हुए याची पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बावजूद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परियोजना के विरोधी किस हद तक जा सकते हैं। इस परियोजना में कानूनी अड़ंगे लगाने वालों की दलील थी कि इसके निर्माण कार्य जारी रहने से कोविड दिशानिर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। अच्छा हुआ कि अदालतों ने इस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया। इस परियोजना की राह में रोड़े अटकाने वाले विरोधी कोविड महामारी के दौरान इस पर हो रहे खर्च और उसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार महामारी से प्रभावित लोगों की मदद करने के बजाय फिजूलखर्ची पर उतारू है।

कहना न होगा कि विरोध की इन दलीलों में कोई दम नहीं है। देश को एक नए संसद भवन और मंत्रियों एवं प्रशासनिक अमले को काम करने और रहने के लिए नई इमारतों की जरूरत है। लगभग एक सदी पहले सेंट्रल विस्टा की ये इमारतें उस दौर में बनी थीं जब एयर कंडीशनर और टेलीफोन को भी लक्जरी समझा जाता था। डिजिटल दुनिया के बारे में तो तब किसी ने सुना भी नहीं था। जाहिर है, आधुनिक सुविधाओं और टेक्नोलाजी के लिहाज से ये इमारतें अनुपयोगी साबित हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल विस्टा में जगह नहीं होने के कारण कई मंत्रालय दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से काम कर रहे हैं और सालाना लगभग एक हजार करोड़ रुपये का किराया चुका रहे हैं।



नई दिल्ली में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा का मॉडल। इंटरनेट मीडिया

सेंट्रल विस्टा परियोजना की उपयोगिता पर तो कोई सवाल ही नहीं है। भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर देश को नया संसद भवन चाहिए। वर्तमान में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य हैं, लेकिन 2021 की जनगणना के बाद इनकी संख्या बढ़ेगी। वर्ष 2026 में परिसीमन के बाद बढ़े हुए सांसदों के बोझ को उठाने में वर्तमान संसद भवन सक्षम नहीं है। मौजूदा संसद भवन को बने 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब नई लोकसभा में 888 सीटें, जबकि राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। विजिटर गैलरी में 336 लोग बैठ पाएंगे। इस परियोजना पर होने वाले खर्च पर भी त्योरियां चढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसकी भी कोई बुनियाद नहीं है। नए संसद भवन एवं सेंट्रल विस्टा की अन्य नई इमारतों के निर्माण पर वर्ष 2026 तक कुल 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होने हैं। विरोधियों का कहना है कि इस राशि को कोविड प्रभावितों की मदद पर खर्च करना चाहिए था। अगर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे तर्कों से प्रभावित हो गए होते तो देश में परमाणु बिजली परियोजनाएं और विशाल बांध नहीं बन पाते और हम आज चांद पर मानव भेजने की तैयारी नहीं कर रहे होते। यह सही है कि सरकार का ध्यान गरीबी दूर करने पर होना चाहिए, लेकिन भविष्य के लिए निवेश करना भी उसकी ही जिम्मेदारी है।

प्रासंगिकता और लागत के अलावा सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध इस आधार पर भी किया जा रहा है कि इससे लुटियन दिल्ली की सुंदरता पर दाग लग जाएगा। कई ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त कर दी जाएंगी। इन विरोधियों में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो लुटियन दिल्ली में पले-बढ़े और सक्रिय रहे। उन्हें अपना बचपन और जवानी याद आ रही है। वे याद दिला रहे हैं कि इंडिया गेट के लॉन में उनकी सुबहें और शामें कैसी हुआ करती थीं। ये लोग केंद्र सरकार और उसके नेतृत्व के सौंदर्यशास्त्र पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये भूल रह हैं कि अब नया सौंदर्यशास्त्र गढ़ने का समय चल रहा है। इसे वे लोग गढ़ रहे हैं जो हर पश्चिमी चीज पर लट्टू नहीं रहते हैं और अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए, अंग्रेजीदां लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं।

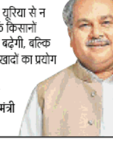
हास्यास्पद होने की सीमा तक अतार्किक और अव्यावहारिक विरोधियों के रहते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी को इस तरह की लड़ाइयों से नहीं हराया जा सकता है। वे एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो खुद पर गर्व करता है। उसे मालूम है कि देसी टीका विकसित करने का क्या अर्थ होता है। वह यह भी जानता है कि अमेरिका में कोरोना का टीका लगवाने के लिए दो-दो हफ्तों तक भटकना पड़ रहा है, जबकि अपने देश में इसकी पूरी व्यवस्था अभूतपूर्व तेजी और सटीकता के साथ चल रही है और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। यही नहीं, यहां टीका लगवाते ही तुरंत उसका प्रमाणपत्र मोबाइल पर आ जाता है और अमेरिका में कागज के कार्ड पर नर्स के हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय संस्करण
सोमवार 5 जुलाई, 2021
दैनिक जागरण
# बिजनेस
www.jagran.com

### विलय-अधिग्रहण सौदों में तेज उछाल

**नई दिल्ली:** कोरोना संकट के बीच भी इस वर्ष पहली छमाही (जनवरी-जून, 2021) के दौरान विलय-अधिग्रहण सौदों की रकम 44 फीसद बढ़कर बढ़कर 49.34 अरब डॉलर पर पहुंच गई। पिछले वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 34.3 अरब डॉलर रहा था। एलएसई ग्रुप की इकाई रिफिनिटिव के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में विलय एवं अधिग्रहण सौदों की संख्या पांच फीसद बढ़कर 730 पर पहुंच गई। (प्रेट्र)

नैनो यूरिया से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि रासायनिक खादों का प्रयोग भी घटेगा।
- नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री



## एफपीआइ ने जून में किया 13,269 करोड़ रुपये निवेश

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** लगातार दो महीनों तक बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने जून के दौरान भारतीय बाजार में 13,269 करोड़ रुपये का निवेश किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार पहली से 30 जून के दौरान एफपीआइ ने इक्विटी में 17,215 करोड़ का निवेश किया। वहीं, उन्होंने डेट सेग्मेंट से 3,946 करोड़ रुपये निकाल लिए। इस तरह जून में उनका शुद्ध निवेश 13,269 करोड़ रहा।

एफपीआइ ने इससे पहले मई में शुद्ध रूप से 2,666 करोड़ रुपये और अप्रैल में 9,435 करोड़ रुपये निकाल लिए थे। उल्लेखनीय है कि इन दो महीनों के दौरान कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकांश राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति थी। मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर (मैनेजर रिसर्च) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि संक्रमण के लगातार गिरते मामलों से विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार के प्रति भरोसा बढ़ता दिख रहा है।

# क्रूड सस्ता हो या महंगा, कंपनियां बढ़ाती रहीं दाम

## 2004-05 के बाद पिछले वर्ष सबसे सस्ता क्रूड खरीदा, मगर बीते एक वर्ष में 60% तक महंगा हो चुका है कच्चा तेल

जयप्रकाश रंजन • नई दिल्ली

रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की खुदरा कीमत में 35 पैसे और डीजल में 16 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर स्पष्ट कर दिया है कि इन उत्पादों के दाम में वृद्धि का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा।

सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर इस वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतों को वजह बताया है। लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े ही इस बात की गवाही हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों का घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से कोई लेनादेना नहीं है। अगर ऐसा होता तो वर्ष 2020-21 में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 17 वर्षों के निचले स्तर पर होतीं।

पिछले वर्ष औसतन 44.82 डॉलर प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदा गया था, जो वर्ष 2004-05 के औसत खरीद मूल्य (39.21 डॉलर प्रति बैरल) के बाद सबसे सस्ती दर है।

**पिछले 16 वर्षों के दौरान भारत ने ऐसे खरीदा कच्चा तेल**

| वर्ष | क्रूड का औसत दाम (डॉलर प्रति बैरल) | वर्ष | क्रूड का औसत दाम (डॉलर प्रति बैरल) |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | 55.72 | 2013-14 | 105.52 |
| 2006-07 | 62.46 | 2014-15 | 84.16 |
| 2007-08 | 79.25 | 2015-16 | 46.17 |
| 2008-09 | 83.57 | 2016-17 | 47.56 |
| 2009-10 | 69.76 | 2017-18 | 56.43 |
| 2010-11 | 85.09 | 2018-19 | 69.88 |
| 2011-12 | 111.89 | 2019-20 | 60.47 |
| 2012-13 | 107.97 | 2020-21 | 44.82 |

पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन तेल कंपनियों ने वर्ष 2019-20 के 60.47 डॉलर प्रति बैरल के मुकाबले 15.55 डॉलर कम दाम पर क्रूड खरीदा। इसके बावजूद पिछले एक वर्ष के दौरान पेट्रोल करीब 21 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में लगभग 29 रुपये प्रति लीटर महंगा किया। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में पहली अप्रैल से 30 जून तक अगर तेल कंपनियों ने पेट्रोल को 8.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल क 8.49 रुपये प्रति लीटर महंगा किया है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इन तीन महीनों में क्रूड लगातार महंगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि क्रूड की कीमत इस पूरे वर्ष 80 डॉलर से 100 डॉलर के बीच रह सकती है।

बहरहाल, रविवार को पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों को बढ़ाए जाने के बाद देश के कुछ और राज्यों में इसकी कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार चली गई है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है जबकि सिक्किम एक और राज्य बन गया है जहां पेट्रोल का दाम तीन अंकों के ऊपर गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में पेट्रोल पहले से ही 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा का हो चुका है।

**केंद्र व राज्यों के टैक्स की मार**

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) के डाटा के मुताबिक पहली जुलाई को दिल्ली स्थित उसके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की खुदरा कीमत 98.84 रुपये थी जिसमें 32.90 रुपया केंद्रीय टैक्स, 22.82 रुपये राज्य का टैक्स और 3.82 रुपये डीलर का कमीशन था। फिर, केंद्र के खाते में जितना भी टैक्स आता है उसका 45 फीसद भी राज्यों को जाता है। पेट्रोल-डीजल पर टैक्स की कमाई कई राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा है। इसलिए भी अधिकतर राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना ही नहीं चाहती हैं।

रही बात राज्यों में अलग अलग कीमत की तो वह पूरी तरह राज्यों की ओर से वसूले जाने वाले वैट टैक्स पर निर्भर करता है। डीजल की 89.23 रुपये की खुदरा कीमत में 31.80 रुपये केंद्र का, 13.05 रुपये राज्य का और 2.60 रुपये डीलर कमीशन था। दिल्ली में पेट्रोल पर वैट की दर 30 फीसद, डीजल पर 16.75 फीसद है। जबकि केंद्र सरकार पेट्रोल पर चार तरह से केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूलती है, 1.40 रुपये प्रति लीटर की बेसिक उत्पाद शुल्क, 11 रुपये का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, 2.50 रुपये कृषि विकास फंड के तौर पर और 18 रुपये रोड व इंफ्रास्ट्रक्चर अधिभार के तौर पर। डीजल पर केंद्र सरकार की तरफ से आयद यह दर क्रमशः 1.80 रुपये, 8 रुपये, 4 रुपये और 18 रुपये प्रति लीटर की है। 27 राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल पर 25 फीसद से लेकर 36.50 के बीच टैक्स वसूला जा रहा है। डीजल पर 20 राज्य 20-28 फीसद टैक्स लगा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो दिन पहले ही कहा था कि पेट्रो उत्पादों पर टैक्स की दर घटाने को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।

## एक्सचेंज से शेयर खरीद पर नहीं कटेगा टीडीएस

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार या जिंस बाजार से शेयरों या जिंस की खरीद करने वाली कंपनियों को अपने लेनदेन के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं करनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि भले ही यह खरीद 50 लाख रुपये से अधिक हो, लेकिन उन पर टीडीएस का प्रविधान लागू नहीं होगा। पहली जुलाई से स्रोत पर कर कटौती का प्रविधान लागू किया है। यह 10 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा।

ऐसी कंपनियों से अगर कोई भारतीय निवासी किसी एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी करता है तो उसे खरीद की रकम का 0.1 फीसद हिस्सा टीडीएस के रूप में काटना होता है। यह प्रविधान स्टॉक एक्सचेंजों के जरिये शेयरों या जिंसों के लेनदेन पर लागू नहीं होगा। आयकर विभाग ने कहा कि कई पक्षों ने एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिये लेनदेन में व्यावहारिक दिक्कतों की बात कही है।

## शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 65,167 करोड़ रुपये गिरा

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** बीएसई-सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 65,176.78 करोड़ रुपये गिर गया। इनमें सबसे अधिक नुकसान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और एचडीएफसी बैंक को हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड (एचयूएल) के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई।

बीते सप्ताह टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 20,400.27 करोड़ घटकर 12,30,138.03 करोड़ रह गया। एचडीएफसी बैंक के बाजार मूल्यांकन में 18,113.03 करोड़ की गिरावट आई और यह 8,18,313.66 करोड़ रुपये पर आ गया।

एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 5,837.3 करोड़ रुपये घटकर 4,46,941.10 करोड़ रुपये और आइसीआइसीआइ बैंक का 5,762.02 करोड़ रुपये गिरकर 4,43,404.75 करोड़ रुपये रह गया। बजाज फाइनेंस का पूंजीकरण 4,614.48 करोड़ रुपये गिरकर 3,62,047.96 करोड़ रुपये, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) का 3,748.34 करोड़ रुपये घटकर 3,78,894.38 करोड़ रुपये, कोटक महिंद्रा बैंक का 3,697.15 करोड़ रुपये फिसलकर 3,40,237.26 करोड़ रुपये और इन्फोसिस का 3,004.19 करोड़ रुपये टूटकर 6,67,911.74 करोड़ रुपये रह गया।



सबसे अधिक नुकसान टीसीएस और एचडीएफसी बैंक को हुआ • फाइल फोटो

इन कंपनियों के विपरीत आरआइएल का बाजार मूल्यांकन 15,785.21 करोड़ रुपये बढ़कर 13,49,794.23 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एचयूएल ने पूंजीकरण में 9,245.63 करोड़ रुपये जोड़े। इसके साथ सोमवार को 5,84,695.18 करोड़ रुपये पूंजीकरण के साथ बीएसई में कारोबार शुरू करेगी। पिछले सप्ताह के आखिर में पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 10 कंपनियों में आरआइएल, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचयूएल, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ बैंक, एसबीआइ, बजाज फाइनेंस तथा कोटक महिंद्रा बैंक रहीं।

बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 440.37 अंक या 0.83 प्रतिशत के नुकसान में रहा।

## वित्तीय नतीजों समेत प्रमुख आंकड़ों से शेयर बाजारों को मिलेगी राह

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों का दारोमदार बहुत कुछ बड़े आर्थिक आंकड़ों और देश की सबसे बड़ी आइटी कंपनी टीसीएस के तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगा। जानकारों का मानना है कि विदेशी शेयर बाजारों का रुख और प्रमुख घटनाओं का असर पहले की तरह शेयर बाजारों की दैनिक चाल पर थोड़ा-बहुत दिख सकता है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के घटते मामलों और टीकाकरण की बढ़ती गति से निवेशकों को बड़ा बल मिलेगा। डॉलर के मुकाबले रुपये का उतार-चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतें तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश रुख भी प्रमुख सूचकांकों को प्रभावित करेगा।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि मोटे तौर पर घरेलू बाजार को विदेशी संकेतों से ही दिशा मिलती दिख रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी और टीकाकरण की रफ्तार पर काफी-कुछ निर्भर करेगा। इस सप्ताह सेवा क्षेत्र के पीएमआइ आंकड़े आने हैं, जिनसे कारोबारी धारणा प्रभावित होगी। सैमको सिक्युरिटीज की इक्विटी रिसर्च प्रमुख निराली शाह का मानना है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए नतीजों के दौर की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस सप्ताह सभी की निगाह बड़ी और मझोली आइटी कंपनियों पर रहेगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिटेल रिसर्च प्रमुख सिद्धार्थ खेमका का कहना था कि तिमाही नतीजों के मोर्चे पर किसी तरह की निराशा से कुल धारणा प्रभावित हो सकती है।



टीकाकरण की बढ़ती गति से निवेशकों को बड़ा बल मिलेगा • फाइल फोटो

## सीड रिप्लेसमेंट ही देश में तिलहन रकबा और उत्पादन बढ़ाने का उपाय

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** तिलहनी फसलों की खेती को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ने लगा है। खाद्य तेलों की ज्यादातर जरूरतें आयात से पूरी हो रही हैं, जो खजाने पर बोझ बनने लगा है। इस गंभीर चुनौती से निपटने के अब तक के सारे तरीके विफल रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि तिलहन का ना रकबा बढ़ रहा है और न ही उत्पादकता। इसके मुकाबले प्रति व्यक्ति घरेलू खपत में लगातार इजाफा हो रहा है। कृषि विज्ञानियों की मानें तो तिलहनी फसलों की खेती में सबसे बड़ी मुश्किल सीड रिप्लेसमेंट (कमजोर बीजों को छोड़ उन्नत किस्म के बीज अपनाने) के प्रति उदासीन रहने की है। दुनियाभर के मुकाबले भारत में तिलहनी फसलों उत्पादकता निचले स्तर पर है।

**तिलहन खेती की चुनौती**

- रिप्लेसमेंट रेट बढ़ाने पर देना होगा जोर
- खपत का 65 फीसद से ज्यादा खाद्य तेल हो रहा आयात

पिछले दो दशकों के दौरान खाद्य तेलों के आयात में कई गुना की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत घरेलू तिलहनी फसलों की खेती नजरअंदाज होती चली गई। बढ़ते आयात के चलते भी किसानों का मोह तिलहनी फसलों से भंग होता गया। इस दौरान लगभग सभी तिलहनी फसलों की खेती में रकबा घटा और उत्पादकता में कमी दर्ज की गई। हालांकि सोयाबीन का रकबा बढ़ा, लेकिन उसमें कम तेल की वजह से बहुत लाभ नहीं हुआ। नौ तिलहनी फसलों का रकबा सिमट गया है। पिछले 40 वर्षों में सरसों के रकबा में 20 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कम उत्पादकता की वजह से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया।

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) के डायरेक्टर जनरल डॉ. त्रिलोचन महापात्र का कहना है कि घरेलू तिलहनी फसलों उत्पादकता बहुत नीचे हैं। देश में मूंगफली की प्रति हेक्टेयर पैदावार 1,642 किलो है, जबकि यह अमेरिका में 4,496 किलो है। सरसों की पैदावार प्रति हेक्टेयर 1,245 किलो होती है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 1994 किलो और जर्मनी में 3,947 किलो है। सोयाबीन प्रति हेक्टेयर 1,034 किलो उत्पादकता वैश्विक 2,484 किलो और ब्राजील की सर्वाधिक 2,932 किलो से कहीं नीचे है।

इसकी बड़ी वजह गिनाते हुए महापात्र कहते हैं कि हमारे यहां सीड रिप्लेसमेंट रेट बहुत खराब है। किसान पुराने बीजों को ही बार-बार बोते हैं, जिसे हर वर्ष अच्छे बीजों से बदलने की जरूरत है।

# राष्ट्रीय फलक

## हरियाणा के आइपीएस अधिकारी से की ठगी, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर

- आइपीएस हिमांशु गर्ग के बैंक खाते से निकाल लिए थे 99 हजार रुपये
- राजस्थान की पुलिस ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर की कार्रवाई

साइबर ठगों ने भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के एक अधिकारी से 99 हजार रुपये की ठगी की है। आइपीएस अधिकारी के पिता की शिकायत के बाद राजस्थान पुलिस ने इस मामले में झारखंड के जामताड़ा से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपित अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। झारखंड पुलिस का इसमें सहयोग लिया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार जयपुर मूल के हरियाणा कैडर के आइपीएस अधिकारी हिमांशु गर्ग ने पिछले माह मुक्तानंद नगर में रह रहे अपने पिता को एक पार्सल कुरियर किया था। पार्सल नहीं मिला तो हिमांशु के भाई निमेश गर्ग ने गूगल पर कुरियर कंपनी के बारे में सर्च किया। इस दौरान पता चला कि साइबर ठगों ने इंटरनेट पर कुरियर कंपनी से मिलती-जुलती एक नकली वेबसाइट बना रखी थी। उन्होंने निमेश से 10 रुपये आनलाइन मांगे। आइपीएस अधिकारी हिमांशु गर्ग के खाते से आनलाइन यह पैसे मिल गए तो उन्होंने साइबर ठगी करते हुए लिंक भेजकर खाते से 99 हजार रुपये निकाल लिए। इसकी रिपोर्ट उनके पिता ने ईमेल के माध्यम से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल में दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। एक से एक लिंक मिलाते हुए पुलिस झारखंड के जामताड़ा पहुंच गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने कलीम अंसारी के घर दबिश दी, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया। अंसारी इस वारदात का मुख्य आरोपित है। छानबीन के बाद उसके साथी विकास मंडल व समीर पुलिस पकड़ में आए। पुलिस जब उनके घर पहुंची तो वे साइबर ठगी करते हुए किसी अन्य को अपना शिकार बनाने में जुटे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने मोबाइल फोन पानी के टैंक में फेंक दिया। उनके घर की छानबीन में 14 लाख की नकदी, आठ मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड और आठ एटीएम कार्ड मिले हैं।

## पूर्व बसपा सांसद दाऊद अहमद की निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत ध्वस्त

**जागरण संवाददाता, लखनऊ :** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न लेने पर बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद व सिम्मी बानो के पांच मंजिला अवैध निर्माणाधीन भवन को जिला प्रशासन ने रविवार को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान जेसीबी चालक मलबे में दब गया। आधे घंटे बाद उसे निकाला जा सका। गंभीर अवस्था में उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एएसआइ का पत्र मिलते ही जिला प्रशासन ने शनिवार देर रात ही ध्वस्तीकरण की तैयारी कर ली थी। इलाहाबाद प्राधिकरण से भवन गिराने के विशेषज्ञ जेएस पांडे (ओएसडी) को बुलाया गया था। उन्हें इलाहाबाद में दर्जनों अवैध भवनों को गिराने का अनुभव है। पांडे ने छह जेसीबी, तीन पोकलैंड और 50 मजदूरों की मदद से अवैध भवन को गिराया।

पूर्व सासंद ने 2017 में एएसआइ से एनओसी लिए बिना नबी उल्लाह रोड स्थित वजीरगंज में भवन बना लिया था। एएसआइ के अनुसार रेजीडेंसी स्मारक (पुरातत्व विभाग) से भवन की दूरी 123 मीटर है, जो नियमानुसार गलत है।

## ट्रांसमिशन लाइनों की कम क्षमता से बढ़ा बिजली संकट

दीपक मौदगिल, पटियाला

मांग और आपूर्ति के बड़े अंतर ने पंजाब में बिजली संकट खड़ा कर दिया है। संकट पर काबू पाना अब सीधे तौर पर पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पावरकाम) के हाथ में भी नहीं है। कारण यह है कि पावरकाम ने इस धान के सीजन में पंजाब में अधिकतम बिजली की मांग 13500 मेगावाट तक जाने का अनुमान लगाया था परंतु मांग 14500 मेगावाट तक पहुंच गई। अभी पंजाब 7300 मेगावाट बिजली दूसरे राज्यों व नेशनल ग्रिड से खरीद रहा है और 6200 मेगावाट उसके पास उपलब्ध है। इस तरह 13500 मेगावाट बिजली का इंतजाम है। बाहर से वह 7300 मेगावाट से ज्यादा बिजली खरीद ही नहीं सकता क्योंकि इसके लिए उसकी ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता ही नहीं है।

पावरकाम ने दूसरे राज्यों व नेशनल ग्रिड से ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता बढ़ाने का मुद्दा नार्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर के समक्ष उठाया हुआ है। दूसरे राज्यों से बिजली लेने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता 3315 मेगावाट और बढ़ाने का प्रस्ताव 2018 में तैयार हुआ था। काम शुरू हो गया, लेकिन इसके पूरा होने में तीन महीने और लगेंगे।

पावरकाम बिजली की मांग का सही अनुमान लगाने में चूक गया। पंजाब में 2019 में बिजली की अधिकतम मांग 13,633 और 2020 में 13150 मेगावाट रही। इस साल पावरकाम ने करीब 13500 मेगावाट का अनुमान लगाया था, लेकिन मांग इससे भी ज्यादा बढ़ गई। पावरकाम को उम्मीद थी कि मानसून के जून के अंत तक पंजाब पहुंच जाने या प्री-मानसून की बारिश से बिजली की मांग में कमी आएगी परंतु बारिश न होने और गर्मी बढ़ जाने से मांग में बढ़ोतरी हो गई। बारिश न होने से धान को पानी देने के लिए ट्यूबवेलों पर ज्यादा बिजली खर्च हो रही है। रोपड़ व तलवंडी साबो प्लांटों की यूनिटें बंद होने से भी संकट बढ़ा। हालांकि अब रोपड़ प्लांट की यूनिट चालू हो गई है।

तापमान के अनुसार ही बिजली की मांग बढ़ती या घटती है। बारिश की स्थिति तय करती है कि धान की रोपाई वाले खेत को सींचने के लिए कितने घंटे ट्यूबवेल चलाने की जरूरत है। तापमान जितना कम होगा और बारिश जितनी ज्यादा होगी उससे हिसाब बिजली की मांग में कमी आ जाएगी। अब आने वाले दिनों में पंजाब में मानसून की रफ्तार तय करेगी कि बिजली की मांग में गिरावट आएगी या अभी यह संकट बरकरार रहेगा।

### पंजाब में 30 फीसद क्षमता के साथ ही चल सकेगी इंडस्ट्री

**जागरण टीम, चंडीगढ़, अमृतसर :** बिजली संकट से जूझ रही इंडस्ट्री को एक बार फिर प्रदेश सरकार ने परेशानी में डाल दिया है। तीन दिन के अवकाश के बाद रविवार को उद्योगों ने काम शुरू किया तो इसी बीच पीएसपीसीएल ने नया आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि सोमवार से नियमित उत्पादन करने वाली इंडस्ट्री को 30 फीसद क्षमता के साथ उत्पादन करने की आज्ञा होगी। यह पाबंदी पोल्ट्री, राइस शेलर, दूरसंचार, काल सेंटर व जरूरी सेवाओं संबंधी इकाइयों पर लागू नहीं होगी। यह जानकारी पीएसपीसीएल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ए वेनू प्रसाद ने दी। बताया कि पीएसपीसीएल की दूसरी यूनिट में खराबी पड़ने के बावजूद बिजली सप्लाई संतोषजनक है। कहा कि जल्द से जल्द बिजली सप्लाई को सामान्य करने प्रयत्न किया जा रहे हैं।

## सिद्धू ने की 300 यूनिट मुफ्त बिजली की वकालत

**राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ :** बिजली विभाग दिए जाने पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को एक बार फिर ट्वीट कर बिजली संकट के लिए कैप्टन को निशाने पर लिया।

सिद्धू ने राज्य में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की वकालत करते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को तीन से पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जानी चाहिए। लोगों को बिना बिजली कट 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलनी चाहिए। सिद्धू ने लिखा कि पंजाब अभी 9000 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दे रहा है। हमें घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए और बेहतर करते हुए उन्हें 10 से 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली की जगह तीन से पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जानी चाहिए। यह संभव भी है।

सिद्धू ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस हाईकमान के जनहितैषी 18 सूत्रीय कार्यक्रम वाले एजेंडा पर अब काम शुरू हो जाना चाहिए।

**जागरण विशेष**

# गोबर से हुआ कमाल, किसान बन रहे आत्मनिर्भर

## लोहरदगा के मुर्की गांव के सुरेश मुंडा ने दिखाई राह, गांव के दूसरे लोग भी जैविक खाद से कर रहे ठीक-ठाक कमाई

गफ्फार अंसारी • लोहरदगा

रासायनिक खाद से होने वाले नुकसान को देखते हुए अब किसान जैविक खाद के प्रयोग की ओर मुड़ रहे हैं। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के मुर्की गांव में ज्यादातर किसान गोबर और केंचुआ से जैविक खाद बनाकर फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, जैविक खाद बेचकर अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। मुर्की गांव में यह क्रांति लाने का श्रेय सुरेश मुंडा को जाता है, जो जैविक खाद तैयार कर सालाना एक से डेढ़ लाख रुपये तक की कमाई कर रहे हैं।

सुरेश की सफलता देख दर्जनों किसान जैविक खाद के उत्पादन और प्रयोग में जुट गए हैं। सुरेश बताते हैं कि कुछ साल पहले प्रदान नाम की एक संस्था के कुछ सदस्य गांव में आए थे, जिन्होंने समझाया कि जैविक खाद से जमीन की उर्वरा क्षमता तो बढ़ती ही है, फसल व अनाज की गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका प्रयोग अनाज व सब्जियों को पौष्टिक बनाता है। इससे अच्छी कमाई भी की जा सकती है क्योंकि अनाज, सब्जियों व अन्य फसलों की पौष्टिकता पाने के लिए लोग इससे उपजी फसलें ज्यादा कीमत पर खरीदने को तैयार रहते हैं। जैविक खाद की भी अच्छी कीमत देते हैं। खेती-बागवानी योजनाओं में कृषि विभाग किसानों से जैविक खाद खरीद कर अच्छी कीमत दे रहा है। कई संस्थाएं भी खाद खरीद रही हैं।

**गांव से खाद खरीदते हैं व्यापारी:** सुरेश मुंडा बताते हैं कि यह पता नहीं था कि गोबर की खाद को अच्छी-खासी आमदनी का जरिया भी बनाया जा सकता है। शुरुआत में गोबर से बिना पूंजी कमाई होने लगी तो दायरा बढ़ाया। पशुपालकों से गोबर खरीद कर बड़े पैमाने पर जैविक खाद तैयार करने लगे। अब व्यापारी गांव आकर जैविक खाद खरीद कर ले जाते हैं। गांव में अब करीब 60 लोग जैविक खाद तैयार कर रहे हैं।

**सात से आठ रुपये प्रतिकिलो की दर से बिक जाती है खाद:** सुरेश बताते हैं कि एक ट्रैक्टर ट्राली गोबर 2,500 रुपये में मिलता है। इसमें लगभग ढाई टन गोबर रहता है। यानी लगभग एक रुपये प्रति किलो की लागत आती है। इसमें मिलाने के लिए केंचुआ भी आसानी से गांव में उपलब्ध हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया तथा मजदूरी आदि में प्रति किलो लगभग दो रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है। इस तरह तीन से साढ़े तीन रुपये प्रतिकिलो की लागत आती है। बाजार में आसानी से सात से आठ रुपये प्रति किलो खाद बिक जाती है। लोहरदगा के अलावा रांची, गुमला, लातेहार, पलामू आदि क्षेत्र के व्यापारी भी इसे खरीदने आते हैं।

**अन्य किसानों को देते हैं प्रशिक्षण:** सुरेश गांव के दूसरे किसानों को भी जैविक खाद तैयार करने का प्रशिक्षण देते हैं। बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। मुर्की गांव में घर- घर में जैविक खाद तैयार की जा रही है। इसका सबसे अधिक उपयोग धान व सब्जियों की खेती में हो रहा है। अच्छी बात है कि लोग आत्मनिभर हो रहे हैं।



लोहरदगा के मुर्की गांव में गोबर से जैविक खाद बनाते राजेश मुंडा व कौशल्या देवी। पीछे बैठे जगदीश मुंडा, गंगा उरांव व मैमून खातून • जागरण

> ये किसान अन्य गांवों के किसानों के लिए भी मिसाल पेश कर रहे हैं। प्रखंड की हर पंचायत में किसानों को प्रशिक्षण देकर इससे जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को गांव में ही रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा।
>
> **अशोक कुमार चौपड़ा,** प्रखंड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा



लोहरदगा के मुर्की गांव के लोगों के लिए आदर्श बने सुरेश मुंडा • जागरण

### बनाना भी आसान और बेचना भी

सुरेश से प्रभावित होकर मुर्की गांव के राजेश मुंडा, जगदीश मुंडा, गंगा उरांव, मैमून खातून, रानी देवी, कौशल्या देवी, सुशांति उरांव जैविक खाद बनाकर इसे जीविका के रूप में अपना चुके हैं। राजेश मुंडा कहते हैं कि जैविक खाद की मांग के साथ हमारी आमदनी भी बढ़ रही है और फसलों की पैदावार भी। इसे बनाना भी आसान है और बिक्री में भी कोई परेशानी नहीं है। खेती-किसानी से जुड़े लोगों के लिए यह बेहतर व्यवसाय है। प्रगतिशील किसान सुरेश कहते हैं कि जैविक खाद अपने खेतों में उपयोग करने से रासायनिक खाद में होने वाला खर्च बचता है। खेत की मिट्टी भी खराब नहीं होती है।

## बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में चार्जशीट दाखिल

**जासं, गाजियाबाद :** गाजियाबाद पुलिस ने बुजुर्ग के साथ मारपीट करने व दाढ़ी काटने वाले आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दूसरी ओर, वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशन व द वायर समेत छह अन्य आरोपितों को बयान दर्ज कराने के लिए दोबारा नोटिस भेजा है।

लोनी बार्डर थाना के प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि सात जून को कोतवाली क्षेत्र की राम विहार कालोनी स्थित मकान में प्रवेश गुर्जर, कल्लू गुर्जर, गुलशन उर्फ पोली, आरिफ उर्फ आवेश, आदिल, मुशाहिद, हिमांशु, इंतजार, बोना, शाहवेज और अनस ने बुलंदशहर निवासी अब्दुल समद के साथ मारपीट कर उनकी दाढ़ी काट दी थी। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित प्रवेश गुर्जर और कल्लू गुर्जर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है।

**19** फीसद की गिरावट आई है बीते 15 दिनों में दुनियाभर में कोरोना वायरस से मौतों की संख्या में। अब तक 39 लाख से ज्यादा की इस महामारी से मौत हो चुकी है।



## ताइवान के मामले में चीन ने अमेरिका को फिर दिखाई आखें

**बीजिंग, एएनआइ :** ताइवान के मामले में चीन आक्रामक हो गया है और अब वह अमेरिका को सीधे देख लेने की धमकी दे रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि ताइवान हमारी मुख्य भूमि का हिस्सा है और अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप कर खतरा उठा रहा है। वांग ने अमेरिका और सहयोगी देशों की उनके देश के खिलाफ बन रही योजनाओं की भी आलोचना की।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की शीत युद्ध की मानसिकता से कोई जीत हासिल नहीं होगी, सिर्फ सपने ही देखे जा सकते हैं। इस मानसिकता से बेहतर दुनिया का निर्माण तो असंभव ही है। अमेरिका ताइवान के मामले में जोखिम उठा रहा है। चीन के एकीकरण को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उल्लेखनीय है कि चीन लंबे समय से ताइवान पर दावा करता रहा है।

# फिलीपींस का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 45 की मौत

**चूक से हुआ हादसा**

- लैंडिंग के समय रनवे मिस होने के कारण क्रैश हुआ विमान
- तीन पायलटों समेत 49 लोगों को बचाने में मिली सफलता



दक्षिणी फिलीपींस के सुलु प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ वायुसेना का लॉकहीड सी-130 विमान। रायटर

**मनीला, एपी :** फिलीपींस के सुलु प्रांत में रनवे मिस होने के कारण सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जोलो एयरपोर्ट पर हुए इस भीषण हादसे में 42 सैनिकों और एयरपोर्ट के नजदीक मौजूद तीन नागरिकों की मौत हो गई है। फिलीपींस रक्षा विभाग ने वायुसेना के लॉकहीड सी-130 हरक्यूलिस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी दी है।

हादसे में 49 लोगों को बचाने में सफलता मिली है। बचने वालों में कुछ ऐसे सैनिक भी हैं, जो विमान में आग लगने और विस्फोट होने से पहले उससे कूद गए थे।

सैन्य अधिकारी ने बताया कि विमान में कुल 96 लोग सवार थे। इनमें तीन पायलट और पांच क्रू सदस्यों के अलावा 88 सैनिक थे। अब तक पांच सैनिकों का पता नहीं चल पाया है। तीनों पायलट गंभीर रूप से घायल हैं। क्रू के सभी सदस्यों को भी बचा लिया गया है। अमेरिका ने सैन्य सहयोग के तौर पर फिलीपींस को अपनी वायुसेना में रह चुके दो विमान दिए थे। इन्हीं में से एक विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है।

हादसे का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि किसी बाहरी हमले की आशंका नहीं जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान रनवे से आगे निकल गया था और एयरपोर्ट के बाहरी किनारे से टकराकर क्रैश हो गया। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि जोलो का रनवे देश के अन्य रनवे के मुकाबले छोटा है। लैंडिंग स्पॉट मिस होने के बाद किसी भी पायलट के लिए विमान को संभालना बहुत मुश्किल है।

**विमान में सवार बहुत से सैनिक नए थे :** एक अधिकारी ने बताया कि विमान में सवार बहुत से सैनिक नए थे और हाल ही में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी। इन्हें सुलु में तैनाती के लिए भेजा जा रहा था। सैन्य कमांडर मेजर जनरल विलियम गोंजालेस ने बताया कि ये सैनिक यहां आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने वाले थे। यह एयरपोर्ट सुलु के पहाड़ी इलाके से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इस इलाके में सेना अबु सैयाफ आतंकी समूह से लड़ रही है। कुछ आतंकी अपने आप को इस्लामिक स्टेट (आइएस) का भी हिस्सा बताते हैं।

## म्यांमार में सेना ने 25 विरोधियों को जान से मारा

**यंगून, रायटरः** म्यांमार के सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के केंद्र में एक शहर में सैन्य जुंटा के विरोधियों के साथ टकराव में कम से कम 25 लोगों को मार डाला है। म्यांमार के एक निवासी और मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी है।

म्यांमार के सरकारी ग्लोबल न्यू लाइट ने कहा कि 'सशस्त्र विरोधियों' ने नायपीडॉ से लगभग 300 किमी उत्तर में, सागिंग क्षेत्र के डेपायिन में गश्त कर रहे सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, उनमें से एक की मौत हो गई और छह घायल हो गए। उसने कहा कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर पीछे हट गए। निर्वाचित नेता आंग सान सू की के खिलाफ एक फरवरी को तख्तापलट से म्यांमार अराजकता में डूब गया है। इसमें 5.3 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी वाले देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है। डेपायिन के एक निवासी ने बताया कि चार सैन्य ट्रकों ने शुक्रवार तड़के गांव में सैनिकों को उतारा। जुंटा का विरोध करने के लिए गठित एक स्थानीय पीपुल्स डिफेंस फोर्स के युवकों ने उनका सामना करने के लिए मोर्चा संभाला। हालांकि, उनके पास केवल अस्थायी हथियार थे और सुरक्षा बलों की भारी गोलाबारी से उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था। स्थानीय निवासी ने फोन पर बताया कि लड़ाई के बाद कुल 25 शवों को एकत्र किया गया था। डेपायिन पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि उसके 18 सदस्य मारे गए और 11 घायल हो गए। जन रक्षा बलों की स्थापना म्यांमार के कई हिस्सों में जनता के विरोधियों द्वारा की गई है। लगभग दो दर्जन जातीय सशस्त्र समूह म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में दशकों से लड़ रहे हैं, लेकिन डेपायिन जातीय बामार बहुमत के केंद्र में है, जो सशस्त्र बलों पर भी हावी है।

# अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा कर रहा तालिबान

**बढ़ रहा दबाव** ▸ एक तिहाई जिलों पर नियंत्रण करने का दावा

### मुकाबले से भागे तीन सौ अफगान सैनिक ताजिकिस्तान पहुंचे

**काबुल, एपी :** अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान अफगान सुरक्षा बलों पर भारी पड़ रहा है। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में तालिबान निरंतर बढ़त बना रहा है और हर रोज कई जिले उसके कब्जे में आ रहे हैं। यहां तालिबान द्वारा खदेड़े जाने के बाद तीन सौ सैनिक अपने देश की सीमा पार कर ताजिकिस्तान पहुंच गए।

ताजिकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की राज्य समिति ने तीन सौ अफगान सैनिकों के आने की पुष्टि की है। समिति ने कहा है बदख्शां प्रांत से लगी सीमा से ये सैनिक आए हैं। मानवता के कारण इन्हें यहां प्रवेश की अनुमति दी गई है।

अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की सेना वापसी की घोषणा के बाद से पूरे अफगानिस्तान में तालिबान निरंतर बढ़त बना रहा है। देश के उत्तरी क्षेत्र में उसका तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है। तालिबान का दावा है कि उसने 421 जिलों में से एक तिहाई जिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रांतीय परिषद के सदस्य मोहिब उल रहमान ने कहा है कि उत्तर पूर्व के बदख्शां के कई जिलों को सुरक्षा बलों ने बिना संघर्ष के ही छोड़ दिया। पिछले तीन दिनों में 10 जिले ऐसे ही तालिबान ने हासिल किए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने बिना लड़ाई के जिलों को हासिल करने की पुष्टि की है। एएनआइ के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान अफगान सुरक्षा बलों ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 143 आतंकियों को ढेर कर दिया। 121 तालिबानी आतंकी घायल हुए हैं।

### 50 हजार अफगान सहयोगियों को शरण दिलाने की कोशिश में अमेरिका

- उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाखस्तान से वार्ता, सेना के सहयोगी अफगान नागरिकों को तालिबान से खतरा

**वाशिंगटन, एएनआइ :** अफगानिस्तान से सेना की वापसी के साथ ही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता वो 50 हजार अफगान सहयोगी हैं, जो बीस साल तक उनकी मदद करते रहे। इनमें बड़ी संख्या में दुभाषिए व अन्य तकनीकी काम करने वाले लोग हैं। तालिबान ऐसे अफगान नागरिकों को लगातार धमका रहे हैं। अमेरिका इन सभी को मध्य एशिया के तीन देशों में शरण दिलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने कुछ सप्ताह पहले इन अफगान सहयोगियों के वीजा बनाने की पहल शुरू की थी। उस समय यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि वे कहां जाएंगे। अब बाइडन प्रशासन अस्थायी रूप से शरण दिलाने की संभावना तलाश रहा है।

द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार वाशिंगटन कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अफगान सहयोगियों को शरण दिलाने के लिए बात कर रहा है। यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के ही माध्यम से मिली है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और नाटो सेना की वापसी के दौरान ही तालिबान और अफगान सेना में संघर्ष तेज हो गया है और तालिबान ने कई जिलों पर कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका और नाटो देशों की सेना के साथ 20 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले अफगान नागरिकों की जान को खतरा पैदा हो गया है। बाइडन कह चुके हैं कि मदद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। गुरुवार को विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भी ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के समकक्षों से मुलाकात की।

## अफगानिस्तान में पाकिस्तान तैयार कर रहा जिहादियों की नई पौध

- अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद के हालात पर इजरायली अखबार ने किया आगाह
- कहा, जम्मू-कश्मीर और अफगानिस्तान में हमेशा हिंसा को बढ़ावा देगा पाक



नापाक इरादे। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

**इस्लामाबाद, एएनआइ :** ऐसे में जबकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है तब पाकिस्तान ने वहां पर खतरनाक खेल तेज कर दिया है। गृह युद्ध से जर्जर इस देश में पाकिस्तान अब जिहादियों की नई पौध तैयार करने के काम में जुट गया है।

यह बात इजरायल के अखबार यरुशलम पोस्ट ने अपने संपादकीय में लिखी है। लिखा है कि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से आतंकियों को प्रशिक्षण, हथियार, धन और खुफिया सूचनाएं मुहैया करा रहा है। ऐसा वह परंपरागत युद्ध में हारने के बाद कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ आतंकियों को हर जरूरत का सामान मुहैया कराती है।

जिन आतंकी-अतिवादी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार, धन और खुफिया सूचनाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उनमें तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हैं। 2008 के मुंबई आतंकी हमले और 2019 में पुलवामा में हुए हमले में पाकिस्तान की भूमिका खुलकर सामने आई है। वह आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता है। जैश प्रमुख मसूद अजहर इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है।

पाकिस्तान को लेकर दुनिया की यह गलत धारणा है कि वह अफगानिस्तान में संघर्ष की स्थिति को खत्म कराने में सहयोग देगा। वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। अखबार के अनुसार वास्तव में पाकिस्तान तालिबान पर अपने प्रभाव के बूते पर अफगानिस्तान को लेकर चल रही शांति वार्ता में शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान कमजोर हों और पाकिस्तान का प्रभाव कम हो। वह तालिबान की ताकत में और इजाफा कर उस पर नियंत्रण के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए करेगा।

**डबल गेम करेगा पाकिस्तान :** इस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान मसले पर हमेशा ही डबल गेम करेगा और अपना अहमियत बनाए रखेगा। पाकिस्तान का आतंकी संगठनों का इस्तेमाल उसकी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। इसी नीति से वह अफगानिस्तान और जम्मू-कश्मीर में कार्य कर रहा है।

## ईरानी विमान गिराने के लिए माफी मांगे अमेरिका : रूहानी

**तेहरान, आइएएनएस :** ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने तीन दशक से अधिक समय के बाद 1988 में ईरानी यात्री विमान को मार गिराने के लिए अमेरिकी सरकार से माफी मांगने को कहा है। बता दें कि तीन जुलाई, 1988 को खाड़ी में तैनात एक अमेरिकी युद्धपोत से दागी गई मिसाइल ईरानी विमान से टकरा गई थी। जिससे इसमें सवार सभी 290 लोग मारे गए थे।

शनिवार को एक बैठक को संबोधित करते हुए रूहानी ने कहा कि अमेरिकी सरकार को यह जानना होगा कि उसने 1988 में खाड़ी में एक बहुत बड़ा अपराध किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका माफी मांगे और बताए कि इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों को पुरस्कार क्यों दिए गए। इसके बारे में स्पष्टीकरण अभी भी अपेक्षित है। बता दें कि कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी के रूप में ईरान को नया राष्ट्रपति मिल गया है। अगस्त में वह हसन रूहानी की जगह लेंगे। दरअसल, तेहरान से दुबई जाने वाले इस विमान को मार गिराने के बाद अमेरिका ने दावा किया था कि उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया था। इसके लिए अमेरिका ने चालक दल को पुरस्कृत भी किया था। बाद में इस मुद्दे पर समझौता हुआ था, लेकिन अमेरिका ने माफी नहीं मांगी थी। अमेरिका विमान हादसे में मारे गए ईरानी लोगों के परिवारों को 61.8 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हुआ था। इसे एयरबस-300 से जुड़ा सबसे बड़ा विमान हादसा माना जाता है।

## बांग्लादेश के संविधान में सेक्युलरिज्म का इस्लाम से कोई टकराव नहीं : हसीना

- संसद में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सांसद हुरुनुर रशीद को दिया जवाब
- रशीद ने कहा था, कुरान में सेक्युलरिज्म का उल्लेख नहीं इसलिए मुस्लिम बहुल देश के लिए यह विरोधाभासी



रखी बात : शेख हसीना फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

**ढाका, आइएएनएस :** बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश के संविधान में सेक्युलरिज्म (पंथनिरपेक्षता) का इस्लाम से कोई टकराव नहीं है... और बेहतर होगा कि संसद में ऐसी बातें न कही जाएं। शेख हसीना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के सांसद हुरुनुर रशीद को जवाब दे रही थीं जिन्होंने दावा किया था, 'कुरान में सेक्युलरिज्म का कोई उल्लेख नहीं है... यह इस्लाम का विरोध करता है।'

संसद में बजट सत्र के समापन भाषण में हसीना ने शनिवार को टिप्पणी की, 'कुरान में लकुम दीनुकुम वलिय दीन का अर्थ है कि हर किसी को अपनी आस्था और धर्म का पालन करने का अधिकार है और वह अपने धर्म का पालन करेगा।' प्रधानमंत्री के समापन भाषण से पहले रशीद का यह भी कहना था कि संविधान में सेक्युलरिज्म को रखना मुस्लिम बहुल देश के लिए विरोधाभासी है।

जवाब में हसीना ने कहा, 'संसद के माननीय सदस्य ने कहा है कि कुरान में सेक्युलरिज्म का जिक्र नहीं है। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगी कि कुरान में अन्य धर्मों का सम्मान करने के बारे में कुछ जिक्र है। पैगंबर ने कहा था कि दूसरी संस्कृतियों और धर्मों के लोगों के प्रति सम्मानजनक और धैर्यवान रहो। पैगंबर ने यह सिखाया था। हमें कुरान में बताया गया है कि इस्लाम शांति का धर्म है। इस्लाम सभी धर्मों को सम्मान देता है।'

## बोलसोनारो के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन

**रियो डी जेनेरियो, एपी :** ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो मुसीबत में घिर गए हैं। उनके खिलाफ सर्वोच्च अदालत के वैक्सीन डील मामले में आपराधिक जांच की अनुमति देने के बाद देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

ब्राजील के 40 शहरों में हजारों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। उनकी मुख्य मांग राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की थी। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति बोलसोनारो को ब्राजील में कोरोना से हुई हर मौत का भी जिम्मेदार मान रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि मरने वालों के लिए एक-एक मिनट का भी मौन रखा जाए तो जून 2022 तक मौन रखने का सिलसिला बंद नहीं होगा।

ज्ञात हो कि शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने वैक्सीन डील की जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला उस समय शुरू हुआ था, जब स्वास्थ्य मंत्रालय के आयात विभाग के प्रमुख रिकार्डो मिरांडा ने यह आरोप लगाया था कि उन पर भारत से कोवैक्सिन के दो करोड़ टीकों का आयात करने के लिए अनुचित दबाव का सामना करना पड़ा। मिरांडा ने सीनेट समिति के सामने पेश होने के बाद कई आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में जेयर बोलसोनारो को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

# ब्रिटेन में मास्क लगाने की अनिवार्यता होगी समाप्त

- 19 जुलाई से लाकडाउन में दी सकती है ढील
- तेजी से वैक्सीन लगाने के आने लगे अच्छे परिणाम

**लंदन, रायटर :** ब्रिटेन में डेल्टा वैरिएंट के खतरों के बाद अब अच्छी खबर मिल रही है। पिछले कुछ सप्ताह के आंकड़े उत्साहजनक हैं। 19 जुलाई से लाकडाउन और पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। मास्क की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी।

ब्रिटेन के आवास मंत्री राबर्ट जेनरिक ने बताया कि आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बोरिस जानसन पाबंदियों में ढील की घोषणा करेंगे। आकंड़े लाकडाउन खोलने के लिए सकारात्मक हैं। मास्क की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाएगा। ब्रिटेन में जून में पाबंदियां हटाई जा रही थीं, लेकिन डेल्टा वैरिएंट के खतरों को देखते हुए इसको आगे के लिए टाल दिया गया था।

एपी के अनुसार यूरोप में डेल्टा वैरिएंट से निबटने के लिए वैक्सीन की दौड़ तेज हो गई है। इस महाद्वीप का हर देश जल्द से जल्द अपने नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने की होड़ में है। वैक्सीन लगवाने वालों को किराना का सामान, यात्रा और मनोरंजन के वाउचर और नकद पाने के लिए ड्रा निकाले जा रहे हैं।

**इंडोनेशिया :** एपी के अनुसार कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण 20 जुलाई तक इमरजेंसी लगा दी गई है। मरीजों की मौत के बाद यहां आक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है।

**ईरान :** आइएएनएस के अनुसार डेल्टा वैरिएंट के कारण पाबंदियों को फिर लगा दिया गया है। इस वैरिएंट के कारण संक्रमण तेज गति से फैल रहा है।

**अमेरिका में डेढ़ करोड़ लोग टीके की दूसरी खुराक लेने से चूके**

आइएएनएस के अनुसार अमेरिका में डेढ़ करोड़ लोग वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने से चूक गए हैं। यह जानकारी सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर (सीडीसी) ने दी है। सीडीसी के अनुसार फाइजर वैक्सीन की दूसरी खुराक पहली खुराक के तीन सप्ताह के बाद और माडर्ना की चार सप्ताह के बाद लेने की संस्तुति की गई है। 42 दिन होने पर दूसरी खुराक से वंचित होना माना जाता है। विभिन्न कारणों से डेढ़ करोड़ लोगों ने 42 दिन तक वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली।

## इंडोनेशिया में आक्सीजन की कमी से 63 मरे



इंडोनेशिया में आक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना वायरस से संक्रमित 63 मरीजों की मौत हो गई। योग्याकार्ता प्रांत के स्लेमन में स्थित सार्दजीतो अस्पताल में हुई इस दुखद घटना के बाद अस्पताल को तत्काल बंद कर दिया गया। बचे हुए मरीजों को टैंटों में बनाए अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इनमें कई कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए चिकित्सकों की टीम को आपरेशन करना पड़ा। रायटर

## पोप फ्रांसिस रोम के अस्पताल में भर्ती

**वेटिकन सिटी, एपी :** पोप फ्रांसिस को रविवार को रोम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी बड़ी आंत में परेशानी (स्टेनोसिस) है, जिसकी सर्जरी पहले से तय थी। एक संक्षिप्त बयान में वेटिकन ने कहा कि जब पोप की सर्जरी हो जाएगी तब अवगत कराया जाएगा। इससे तीन घंटे पहले पोप फ्रांसिस ने परंपरा के अनुसार सेंट पीटर्स स्क्वायर पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि वह सितंबर में हंगरी व स्लोवाकिया जाएंगे। एक सप्ताह पहले पोप फ्रांसिस (84) ने लोगों से अपने लिए विशेष प्रार्थना करने की अपील की थी। समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, जेमिली अस्पताल में पोप की सर्जरी प्रोफेसर सर्जियो अल्फिएरी करेंगे। रायटर के अनुसार वर्ष 2013 में चयन के बाद पोप फ्रांसिस को पहली बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोप फ्रांसिस का स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहता है, लेकिन युवावस्था में उनके एक फेफड़े के हिस्से को हटाना पड़ा था।

## जापान से लौटी उइगर शोधार्थी की चीन के यातनागृह में हत्या

- छह माह बाद परिजनों को मिली सूचना, माता-पिता पहले से हैं जेल में

**बीजिंग, एएनआइ :** शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के दमन और अत्याचार के मामलों की अमेरिका सहित कई देश आलोचना कर चुके हैं। चीन इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में ड्रैगन का एक और जघन्य कृत्य सामने आया है। उस पर जापान से लौटी वनस्पति शास्त्र की एक उइगर मुस्लिम शोधार्थी की हत्या आरोप लगा है। उसे चीन की धरती पर कदम रखते ही चीनी अधिकारियों ने यातना गृह में भेज दिया था। जहां उसकी हत्या का आरोप है।

29 वर्षीय मिहराइ इर्किन जापान में नारा टेक्नोलाजी एंड साइंस इंस्टीट्यूट में शोध कार्य कर रही थीं। जून 2019 में उन्हें शिनजियांग प्रांत में रहने वाले अपने माता-पिता की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई और वह वहां से अपनी नौकरी छोड़कर आ गईं। चीन पहुंचते ही उन्हें मनमाने तरीके से हिरासत में ले लिया और उनको यानबुलक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया।

अब इर्किन का कोई पता नहीं चल रहा है। इर्किन की हत्या की जानकारी उसके नार्वे में रहने वाले चाचा अब्दुवेली अयूप ने वायस आफ अमेरिका को दी है। उनका कहना है कि इर्किन के मारे जाने के छह माह बाद उन्हें जानकारी मिली है। उनके माता-पिता को डिटेंशन सेंटर में भेजने के कारण ही इर्किन चीन से जापान चली गईं थीं। शिनजियांग में रहते हुए उसके माता-पिता को बाद में 10 साल से ज्यादा की सजा सुना दी गई थी।

अब इर्किन के रिश्तेदार चीनी अधिकारियों से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको कहां दफना दिया गया। यह मामला अब इंटरनेट मीडिया की सुर्खियां बन गया है।

## हाफिज के घर पर हमले में पाक एनएसए के भारत पर अनर्गल आरोप

**इस्लामाबाद, एएनआइ :** आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाक अब हाफिज सईद के घर के सामने बम विस्फोट के मामले में भारत पर ही अनर्गल आरोप लगा रहा है। पाक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मोईद युसुफ ने हाफिज सईद के घर पर हमले के मामले में भारत पर आरोप लगाया है। युसुफ का आरोप है कि हमले का मास्टर माइंड एक भारतीय है और उसके रॉ से संबंध हैं। उनका कहना है कि 23 जून को इस हमले के साथ ही कई साइबर हमले भी किए गए। उन्होंने डान अखबार के हवाले से कहा कि साइबर हमले हमारी जांच में बाधा डालने और सबूत मिटाने के लिए किए गए थे।

**पाक में पत्रकारों का देशव्यापी प्रदर्शन :** पाकिस्तान में पत्रकारों ने प्रेस की आजादी के लिए पूरे देश में सोमवार को प्रदर्शन करने का एलान किया है। पत्रकार पंजाब प्रांत की सरकार द्वारा लाए गए विवादित प्रिविलेज बिल-2021 का विरोध कर रहे हैं।

## यूएई में करोड़पति बना भारतीय, हाथ लगा 40 करोड़ रुपये का जैकपॉट

**दुबई, प्रेट्र :** संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 37 वर्षीय एक भारतीय ड्राइवर और विभिन्न देशों के उसके नौ सहयोगियों ने दो करोड़ दिरहम (करीब 40 करोड़ रुपये) की लॉटरी जीती है।

खलीज टाइम्स ने शनिवार को बताया कि केरल निवासी और अबूधाबी में ड्राइवर का काम करने वाला रंजीत सोमराजन पिछले तीन साल से टिकट खरीद रहा था। मीडिया रिपोर्ट में सोमराजन के हवाले से कहा गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जैकपॉट लगेगा। मुझे लगा था कि मैं दूसरे या तीसरे स्थान की लॉटरी जीत सकता हूं। सोमराजन ने कहा कि इस बार दूसरा पुरस्कार 30 लाख और तीसरा पुरस्कार 10 लाख दिरहम था। जैकपॉट लगने के बाद से सोमराजन के पास उसके मित्रों एवं प्रियजन के फोन लगातार आ रहे हैं। सोमराजन ने कहा, मैं 2008 से यहां हूं। मैंने दुबई टैक्सी और अन्य कंपनियों के साथ ड्राइवर के रूप में काम किया। पिछले साल मैंने एक कंपनी में ड्राइवर सह विक्रेता के रूप में काम किया, लेकिन वेतन कटने के कारण मेरे लिए जीवनयापन मुश्किल था।

रंजीत सोमराजन ने कहा कि वह कुल 10 लोग हैं। अन्य लोग भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे विभिन्न देशों से हैं। वे एक होटल की पार्किंग में काम करते हैं। हमने 'दो खरीदों एवं एक मुफ्त पाओ' पेशकश के तहत टिकट खरीदा. हर व्यक्ति ने 100 दिरहम दिए। टिकट 29 जून पर मेरे नाम पर लिया गया। उसने कहा कि मुझे पूरा भरोसा था कि ईश्वर की कृपा एक दिन मुझ पर होगी। इससे पहले, पिछले साल 35 वर्षीय एक भारतीय व्यक्ति ने एक करोड़ दिरहम यानी 19.90 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीता था। पंजाब के निवासी गुरप्रीत सिंह ने पिछले साल अगस्त में लाटरी टिकट खरीदा था। आयोजकों ने तीन सितंबर को सिंह को फोन किया और उन्हें बताया कि उन्होंने लाटरी जीती है तो उन्हें लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है।

## जुमा ने अपनी सजा को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत में दी चुनौती

**जोहानिसबर्ग, प्रेट्र :** दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपने 15 महीने की जेल की सजा को सुप्रीम में चुनौती दी है। उन्हें यह सजा उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यूरी के समक्ष पेश नहीं होने पर सुनाई गई है।

विगत मंगलवार को संवैधानिक अदालत ने जुमा को ज्यूरी के समक्ष बार-बार पेश नहीं होने पर 15 महीने की जेल काटने की सजा सुनाई गई थी। 79 वर्षीय जुमा पर वर्ष 2009 से 2018 के बीच राष्ट्रपति रहने के दौरान धांधलियों को प्रश्रय देने का आरोप है। अदालत ने जुमा को रविवार तक की मोहलत दी है ताकि वह सजा पूरी करने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। कोर्ट ने उनसे 12 जुलाई तक इस संबंध में एक आवेदन भी मांगा है। जुमा ने अपनी याचिका में कहा है कि जेल जाने से पहले संवैधानिक अदालत को एक बार उनकी अपील सुनने का लोकतांत्रिक अधिकार है।

# कमाल के केन

- हैरी ने इंग्लैंड के लिए दागे दो शानदार गोल
- इंग्लैंड ने बनाई सेमीफाइनल में जगह



**1996** के बाद इंग्लैंड पहली बार यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। अब वह घरेलू धरती पर वेंबले स्टेडियम में डेनमार्क से भिड़ेगा

हमें वेंबले में सेमीफाइनल खेलने को मिलेगा। एक टीम, एक देश के रूप में हमारे लिए क्या शानदार मौका है। हमें इसका पूरा फायदा उठाना होगा।
**हैरी केन,** कप्तान, इंग्लैंड

सेमीफाइनल लाइन-अप

| मैच | जगह |
|---|---|
| इटली vs स्पेन | लंदन |
| इंग्लैंड vs डेनमार्क | लंदन |

नोट: सेमीफाइनल मुकाबले मंगलवार से खेले जाएंगे।

**2004** के बाद यूरो कप में इंग्लिश की टीम ने सबसे कम समय में गोल किया है और यह कारनामा केन ने चौथे मिनट में किया।

यूक्रेन के खिलाफ गोल करने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन • रायटर

**रोम, एपी:** इंग्लैंड टीम के कोच गेरेथ साउथगेट को पता था कि उनकी टीम को अगर इस टूर्नामेंट में अपना लंबा सफर तय करना है तो उसके लिए उनके कप्तान हैरी केन का चलना जरूरी है। केन पिछले कुछ समय से अपनी फार्म को लेकर परेशान थे और इसको लेकर उनकी आलोचना भी हो रही थी। उनका ग्रुप स्तर के मैचों में भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और इन मैचों में वह एक भी गोल नहीं कर पाए थे। लेकिन प्री-क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के खिलाफ 2-0 की जीत में 27 वर्षीय केन ने हेडर से गोल दागकर अपनी खोई फार्म वापस पाई। फिर क्वार्टर फाइनल में केन के कमाल से इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से रौंदकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

**गोल**

इंग्लैंड 4 – 0 यूक्रेन

हैरी केन (चौथा, 50वां), हैरी मैगुइर (46वां), जार्डन हेंडरसन (63वां मिनट)

गेंद रखी: इंग्लैंड 51% – यूक्रेन 49%

| इंग्लैंड | | यूक्रेन |
|---|---|---|
| 00 | यलो कार्ड | 00 |
| 00 | रेड कार्ड | 00 |
| 02 | कार्नर किक | 03 |
| 621 | कुल पास | 599 |
| 02 | गोलकीपर बचाव | 03 |

इस मैच में केन ने शानदार दो गोल दागे। इसके अलावा केन यूरो नाकआउट मैच में दो गोल करने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि प्री-क्वार्टर फाइनल तक गोल करने वाले रहीम स्टर्लिंग क्वार्टर फाइनल में गोल नहीं कर पाए तो हैरी मैगुइर और जार्डन हेंडरसन ने गोल करके उनके भार को कुछ कम किया। हालांकि कोच गेरेथ साउथगेट ने टीम के डिफेंस में भी काफी काम किया है क्योंकि टीम ने इस टूर्नामेंट के पिछले पांच मैचों में कोई गोल नहीं खाया है। अब अंतिम-चार के मुकाबले में इंग्लिश टीम का सामना डेनमार्क से होगा। यूरो में यह एकमात्र मैच था जिसे इंग्लैंड ने वेंबले स्टेडियम से बाहर खेला था और इसी में उसने सबसे दबदबे वाला प्रदर्शन किया।

यह 1966 के विश्व कप फाइनल के बाद पहला अवसर है जबकि इंग्लैंड ने किसी बड़े टूर्नामेंट के नाकआउट चरण में चार गोल किए। उसने 1966 में पश्चिम जर्मनी को 4-2 से हराया था। क्वार्टर फाइनल की शुरुआत इंग्लैंड के लिए अच्छी रही। बाक्स के अंदर से स्टर्लिंग ने गेंद केन की तरफ पास की जिन्होंने इसे गोल पोस्ट में पहुंचाने में देर नहीं की और टीम का स्कोर मैच में 1-0 कर दिया। प्री-क्वार्टर फाइनल में मजबूत स्वीडन को चौंकाने वाली यूक्रेन की इंग्लिश टीम के खिलाफ एक नहीं चली और दूसरे हाफ में साउथगेट की टीम ज्यादा आक्रामक होकर खेली। 46वें मिनट में लुइक ने गेंद हैरी मैगुइर की तरफ भेजी और मैगुइर ने गोलकीपर बाक्स से हेडर के जरिये गेंद को उसकी सही जगह दिखा दी। चार मिनट बाद केन ने टीम की बढ़त को 3-0 कर दिया। इस बार भी लुइक ने गेंद को सही दिशा में केन को पास की, जिन्होंने हेडर से गोल कर दिया और यूक्रेन के खिलाड़ी इस गोल को रोकने में बेबस नजर आए। फिर 62वें मिनट में केन के एक प्रयास को गोलकीपर हिरोई बशचन ने विफल कर दिया। लेकिन, 63वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी हेंडरसन ने इंग्लिश टीम की बढ़त को चार गोल की करने में ज्यादा देर नहीं की। इसके बाद यूक्रेन के खिलाड़ी एक गोल भी नहीं दाग पाए।

## इंग्लैंड से खाली हाथ लौटेगी श्रीलंकाई टीम, भारत से होगा सामना

**नई दिल्ली, जेएनएन :** इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच ब्रिस्टल में खेला गया, तीसरा व अंतिम वनडे मैच बारिश की वजह से रद हो गया। इस तरह श्रीलंकाई टीम इंग्लैंड से खाली हाथ स्वदेश लौटेगी, जहां उसे 13 जुलाई से भारत के खिलाफ सीमित ओवर की सीरीज खेलनी है।

शिखर धवन की कप्तानी वाली भारतीय टीम खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज से पहले श्रीलंका की टीम के पास लय हासिल करने के लिए इंग्लैंड का दौरा अच्छा मौका था, लेकिन उसे इस दौरे पर पूरी तरह से निराशा हाथ लगी। टी-20 सीरीज 3-0 से जीतने के बाद मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में भी 2-0 से हरा दिया। इंग्लैंड ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी की। टाम कुर्रन (4/35), क्रिस वोक्स (2/28) और डेविड विली (2/36) की धारदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम को 41.1 ओवर में ही 166 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका की ओर से दासुन शनाका ने 65 गेंद में दो छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से सर्वाधिक नाबाद 48 रन बनाए। श्रीलंका की पारी समाप्त होने के बाद बारिश शुरू हो गई, जो लगातार चलती रही और मैच को रद करना पड़ा।

**कपिल बोले, अब ओपनर को इंग्लैंड भेजने के बारे में नहीं सोचे बोर्ड:** पूर्व कप्तान कपिल देव का मानना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले चोटिल शुभमन गिल के विकल्प पर विचार करने के लिए ओपनर को इंग्लैंड भेजने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। श्रीलंका के सफेद गेंद के दौरे पर गए पृथ्वी शा को बैकअप ओपनर के रूप में इंग्लैंड भेजा जा सकता है।

# सब कुछ दांव पर लगाकर जीते डेनिल मेदवेदेव

**लंदन, एपी:** विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर रूस के डेनिल मेदवेदेव ने अपने करियर का सबसे शानदार मैच खेला। इस मैच में उन्होंने वह कर दिखाया जिसके लिए वह वर्षों से मेहनत करने में जुटे हुए थे। मेदवेदेव ने 32वीं वरीय क्रोएशिया के मारिन सिलिक के खिलाफ पहले दो सेट हराने के बाद जोरदार वापसी करते हुए अंतिम तीनों सेटों को अपने नाम कर पांच सेटों तक चले मुकाबले को 6-7(7-3), 3-6, 6-3, 6-3, 6-2 जीता। इस तरह मेदवेदेव ने अपने करियर में पहली बार ग्रैंडस्लैम मैच में पहले दो सेट हारने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की और उन्होंने टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए इस मैच में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।

मैच की शुरुआत में डेनिल मेदवेदेव के पास मारिन सिलिक के शाट का जवाब नहीं था। सिलिक ने शुरुआती सेटों में दमदार सर्विस से मेदवेदेव को कोर्ट में जमने का मौका ही नहीं दिया। पहला सेट टाई ब्रेकर में गया और सिलिक ने 6-3 से बढ़त ले रखी थी। तभी मेदवेदेव ने सर्विस की और सिलिक ने शानदार रिटर्न देने के बाद दूसरे शाट में टेनिस कोर्ट पर बैडमिंटन के अंदाज में स्मैश मारते हुए पहले सेट को 7-6 (7-3) से अपने नाम किया। दूसरे सेट में भी सिलिक ने अपनी शानदार लय को बरकरार रखा और दो बार सर्विस को जीतते हुए सेट को 6-3 से अपने नाम कर लिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि अब मदेवेदेव के लिए वापसी बहुत ही मुश्किल है और उनके पहले विंबलडन खिताब जीत की दौड़ शायद खत्म जो जाएगी। मगर दूसरी तरफ हाल ही में ग्रास कोर्ट पर पहली बार मालोर्का ओपन का खिताब जीतकर विंबलडन में खेलने वाले मेदवेदेव ने जोरदार वापसी की।

मेदवेदेव ने करीब छह फीट लंबे खिलाड़ी सिलिक को कोर्ट के आगे नेट के पास खिलाना शुरू कर दिया जिसका जवाब सिलिक नहीं दे पा रहे थे और उनसे कई बेजा गलतियां भी होने लगी। इसका फायदा मेदवेदेव को मिलने लगा और उन्होंने अंतिम तीन सेटों में सिलिक को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। जिन्हें मेदवेदेव ने 6-3, 6-3, 6-2 से जीता और इतिहास रच दिया। वह पहली बार विंबलडन के चौथे राउंड में पहुंचे हैं। उधर, अन्य मैचों में एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रीट्स को 6-7 (3-7), 6-4, 6-3, 7-6 (7-4) से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं, विंबलडन में रविवार को आराम दिन होने के कारण कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया है। अंतिम-16 मुकाबलों की शुरुआत सोमवार से होगी।

तीन सेटों में वापसी करते देखना अच्छा लगता है। शुरुआती दो सेट से पिछड़ने के बाद यह मेरी पहली वापसी है और वास्तव में 2019 में विंबलडन में डेविड गोफिन के खिलाफ ऐसे ही मैच में मैं हार गया था। इसलिए जब मैं चौथे सेट के बाद कोर्ट से निकला, तो मैंने खुद से कहा, यह उनमें से एक है और इस बार पहले जैसा नहीं होगा।
**डेनिल मेदवेदेव**

### अंतिम-16 के आज खेले जाने वाले मुकाबले

**पुरुष सिंगल्स:** जोकोविक vs गारिन, फेडरर vs लोरेंजो सोनेगो, मेदवेदेव vs हयूबर्ट हरकच, ज्वेरेव vs फेलिक्स आगर एलियासेम, फुकसोविक्स vs रुबलेव, शापालोव vs बाटिस्टा आगुट, खचानोव vs कोर्ड, बेरेटिनी vs इवशका।

**महिला सिंगल्स:** स्वियातेक vs जब्योर, रिबाकिना vs सबैलेंका, कीज vs विक्टोरिया गोलुबिक, बार्टी vs क्रेजीकोवा, प्लिस्कोवा vs सैमसोनोवा, पौल बदोसा vs कैरोलिना मकोवा, कोको गाफ vs कर्बर, रादकान vs टोमीयानवीक।


मैच के बाद डेनिल मेदवेदेव • एपी

## पेस और भूपति ने फिर से जोड़ी बनाने के दिए संकेत

**नई दिल्ली, जेएनएन:** चार जुलाई साल 1999 में पहले इंडियन एक्सप्रेस के नाम से मशहूर भारत के टेनिस स्टार लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने इतिहास रचते हुए विंबलडन का डबल्स खिताब जीता था। जिसकी 22वीं वर्षगांठ पर पेस और महेश भूपति ने उस पल को याद करते हुए ट्वीट किया और साथ ही अपने ट्वीट के जरिये एक बार फिर से जोड़ी बनाकर खेलने का इशारा भी किया। पिस ने ट्विटर पर लिखा, 'आज से 22 साल पहले हम विंबलडन जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, दो युवा लड़कों के रूप में हम सभी का सपना था कि हम अपने देश का नाम रोशन करें।' जिस पर भूपति ने भी जवाब देते हुए लिखा, 'हां...यह खास था। क्या आपको लगता है कि अब एक और अध्याय लिखने का समय आ गया है? जिस पर भूपति ने फिर से जवाब देते हुए लिखा, 'मैं हमेशा खेल में रहता हूं, क्या प्लान है?

# अर्जेंटीना सेमीफाइनल में, मेसी का गोल

**रियो डि जेनेरियो, एपी:** सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी के 76वें अंतरराष्ट्रीय गोल की मदद से अर्जेंटीना ने इक्वाडोर को 3-0 से करारी शिकस्त देकर कोपा अमेरिका फुटबाल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका सामना कोलंबिया से होगा।

मेसी ने शनिवार को खेले गए मैच में अर्जेंटीना की तरफ से तीसरा गोल किया और इससे पहले के दोनों गोल करने में भी मदद की। इस जीत से मेसी ने पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने की उम्मीदें भी जीवंत रखी हैं। अर्जेंटीना मंगलवार को सेमीफाइनल में कोलंबिया से भिड़ेगा, जिसने एक अन्य मैच में उरुग्वे को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। दूसरा सेमीफाइनल ब्राजील और पेरू के बीच खेला जाएगा।

गोइनिया के ओलंपिक स्टेडियम में खेले गए मैच में मेसी के पास 23वें मिनट में ही टीम को बढ़त दिलाने का मौका मिल गया था, लेकिन वह इसमें चूक गए। वह बाक्स के बाहर हरनेन गालिंडेज को छकाने में सफल हो गए, लेकिन गेंद को गोल पोस्ट में नहीं पहुंचा पाए। हालांकि, रोड्रिगो डि पाल ने 39वें मिनट में पहला गोल दागा और अर्जेंटीना को मैच में 1-0 से आगे कर दिया। अर्जेंटीना के लाउतारो मार्टिनेज ने मैच का दूसरा गोल 84वें मिनट में किया।

स्पेनिश क्लब फुटबाल बार्सिलोना से अनुबंध समाप्त होने के बाद अपना पहला मैच खेल रहे दिग्गज स्ट्राइकर लियोन मेसी ने इन दोनों गोल को करने में मदद की। मेसी ने मैच के इंजुरी समय (90+3वें मिनट) में फ्री किक पर अर्जेंटीना की तरफ से तीसरा गोल किया।

मेसी ने बाक्स से गेंद पर बायें पैर से किक लगाई और गेंद सीधा गोल पोस्ट के बायीं ओर नेट के अंदर चली गई। यह टूर्नामेंट में उनका चौथा गोल भी है। अर्जेंटीना की जीत का अंतर इससे भी बेहतर होता, लेकिन उसने गोल करने के कई मौके गंवाए, जिसमें टीम आगे के महत्वपूर्ण मैच से पहले सुधार करना चाहेगी।


गोल करने के बाद मेसी (ऊपर) • रायटर

सेमीफाइनल मुकाबला टूर्नामेंट में हमारे लक्ष्य में से एक था। हमें अभी आराम करना है और कोलंबिया के खिलाफ मैच के बारे में सोचना है। उनका डिफेंस अच्छा है और वे भी काउंटर अटैक करते हैं। मैं व्यक्तिगत पुरस्कारों को बाद में मानता हूं।
**लियोन मेसी,** कप्तान, अर्जेंटीना

**01** गोल करने के साथ लियोन मेसी दक्षिण अमेरिका से सर्वाधिक गोल करने के पेले के रिकार्ड की बराबरी कर लेंगे। मेसी के 76 गोल हो गए हैं

**58** करियर गोल (क्लब व राष्ट्रीय) मेसी ने फ्री किक पर किए हैं और उन्होंने फ्री किक पर सर्वाधिक गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़ दिया। रोनाल्डो के 57 गोल (क्लब व राष्ट्रीय) थे

सेमीफाइनल लाइन-अप

| मैच | समय | दिनांक |
|---|---|---|
| ब्राजील vs पेरू | 4:30 | सोमवार |
| अर्जेंटीना vs कोलंबिया | 6:30 | मंगलवार |

# नंबर एक मुक्केबाज को कभी तरसना पड़ा था रिंग के लिए

**पदक के दावेदार**
TOKYO 2020 — 18 दिन शेष

**अनिल भारद्वाज • गुरुग्राम**

सामान्य सी कद-काठी वाला किशोर जब गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लेने के लिए आया था तो तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह दुनिया में भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा। आज यह स्टार मुक्केबाज विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज है और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक का जोरदार दावेदार है। हम बात कर रहे हैं 52 किग्रा भारवर्ग के धुरंधर मुक्केबाज अमित पंघाल की। अमित को आर्थिक समस्या से लेकर खेल सुविधाओं तक की कमी से लंबे समय तक जूझना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि गुरु ने जो भी ज्ञान दिया उस पर लगातार ध्यान केंद्रित किया।

**शिष्य की जिद ने किया गुरु को मजबूर:** बात 2011-12 की है, जब हरियाणा शिक्षा बोर्ड में डीईपी पद पर कार्यरत पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज व अमित के गुरु अनिल धनखड़ का तबादला रोहतक से गुरुग्राम हो गया। उस समय गुरुग्राम खेल विभाग के पास मुक्केबाजी रिंग नहीं होने के कारण उन्होंने यहां प्रशिक्षण का काम बंद कर दिया। अपने गुरु के पीछे-पीछे अमित भी रोहतक को छोड़ गुरुग्राम आ गए। प्रशिक्षक के मना करने के बाद भी अमित रोहतक नहीं लौटे। आखिरकार शिष्य की जिद के गुरु को मजबूर होना पड़ा और आगे प्रशिक्षण देने के लिए राजी हो गए। बिना रिंग के ही प्रशिक्षण का दौर चलता रहा।

### ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर की तैयारी

धनखड़ बताते हैं कि अमित में वह सब कुछ मौजूद था जो एक चैंपियन के लिए जरूरी होता है। गुरुग्राम में सुविधा नहीं होने की वजह से वह चाहते थे कि अमित रोहतक में ही प्रशिक्षण ले। अमित ने भी उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह रिंग के बिना प्रशिक्षण ले रहा है। अमित किसान पिता विजेंद्र सिंह के बेटे हैं। विजेंद्र सिंह का सपना था कि अमित के बड़े भाई अजय पंघाल देश के लिए खेलें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अमित कहते हैं कि यह गुरु अनिल धनखड़ ही थे जिन्होंने एशियाई खेल और ओलंपिक का लक्ष्य लेकर प्रशिक्षण शुरू किया था। जब गुरुजी कहते थे कि 2018 एशियाई खेल व टोक्यो ओलंपिक मे खेलना है तो मैं सोचता था कि यह कैसे संभव होगा। जब 2015 के 35वें राष्ट्रीय खेलों में जब देश के बड़े मुक्केबाजों ने खेलने से मना किया तो मुझे प्रदेश की तरफ से खेलने का मौका मिला और वहां पर रजत पदक जीतकर लाया। तब लगा कि वह देश का नाम रोशन करने के काबिल हूं। उसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखा। वर्ष 2017 में जिले के कुछ लोगों के प्रयास से मुझे रिंग मिली और एक वर्ष रिंग में प्रैक्टिस करने का मौका मिला, जिसके बलबूते 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत सका।

### पदक की राह में चुनौती

टोक्यो की तैयारी करने के लिए इटली जाने से पहले अमित का कहना था कि 2019 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में ओलंपिक पदक विजेता उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज शाखोबिदिन जोइरोव के हाथों 0-5 से हार मिली थी। अब 2021 एशियाई चैंपियनशिप में बराबरी के मुकाबले में हार मिली। अब हमारे बीच से कौन बेहतर लड़ता है वह फर्क खत्म हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है मैं टोक्यो में उसे हार का जख्म दूंगा। टोक्यो में किसी राउंड का मुकाबला आसान नहीं है।


अमित पंघाल • फाइल फोटो, ट्विटर

**उपलब्धियां**

- **2017** एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक
- **2018** एशियाई खेल में स्वर्ण पदक
- **2018** कामनवेल्थ खेलों में रजत पदक
- **2019** विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक
- **2019** एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक
- **2021** एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक

**उपलब्धि** भारतीय महिला टीम ने तीसरा वनडे जीता, कप्तान राज ने एक ही दिन में तोड़े दो रिकार्ड

# रन बनाने की भूख 22 साल पहले जैसी: मिताली

**वार्सेस्टर, प्रेट्र:** भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने कहा कि उनकी रन बनाने की भूख अब भी वैसी ही है जैसे 22 साल पहले हुआ करती थी और वह अगले साल न्यूजीलैंड में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए अपनी बल्लेबाजी को नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं।

मिताली की 89 गेंदों पर नाबाद 75 रन की पारी से भारत ने शनिवार को तीसरे और अंतिम वनडे में इंग्लैंड को चार विकेट से हराया। इस पारी के दौरान मिताली महिला क्रिकेट में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली बल्लेबाज भी बनीं। मिताली के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब 10337 रन हो गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स (10,273) को पीछे छोड़ा। महिला क्रिकेट में केवल इन्हीं दो खिलाड़ियों ने 10,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं। साथ ही मिताली महिला क्रिकेट में सर्वाधिक वनडे मैच जीतने वाली कप्तान भी बन गईं। उन्होंने बेलिंडा क्लार्क का रिकार्ड तोड़ा, जिनकी कप्तानी में आस्ट्रेलिया ने 83 वनडे जीते थे।

आयरलैंड के खिलाफ 26 जून 1999 को मिल्टन केयेंस में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाली मिताली ने कहा, 'जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, यह यात्रा आसान नहीं रही। इसकी अपनी परीक्षाएं और चुनौतियां थीं। मेरा हमेशा मानना रहा है कि परीक्षाओं का कोई उद्देश्य होता है। ऐसा भी समय आया जब विभिन्न कारणों से मुझे लगा कि अब बहुत हो चुका, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जिससे मैं खेलती रही और अब मुझे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 22 साल हो गए हैं, लेकिन रनों की भूख अब भी कम नहीं हुई है। मेरे अंदर अब भी वही जुनून है, मैदान पर उतरकर भारत के लिए मैच जीतना। जहां तक मेरी बल्लेबाजी का सवाल है तो मुझे लगता है कि इसमें अब भी सुधार की संभावना है और इस पर मैं काम कर रही हूं। कुछ ऐसे आयाम हैं जिन्हें मैं अपनी बल्लेबाजी में जोड़ना चाहती हूं।'

मिताली ने 2019 में ही टी-20 से संन्यास ले लिया था और वह पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि न्यूजीलैंड में चार मार्च से तीन अप्रैल 2022 के बीच होने वाला महिला विश्व कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा।


भारतीय कप्तान मिताली राज • प्रेट्र

मिताली के रिकार्ड सारी कहानी बयां करते हैं। उन्होंने जो हासिल किया है वह महान गावस्कर व तेंदुलकर की उपलब्धियों के बराबर है। वह लंबे समय तक पर शीर्ष पर रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल उनका रिकार्ड टूट पाएगा।
**शांता रंगास्वामी,** पूर्व कप्तान, भारत

मिताली ने हमें दिखाया कि आखिर क्यों उन्होंने रिकार्ड तोड़ना जारी रखा है। यह आपको दर्शाता है कि वह किस स्तर की बल्लेबाज हैं। वह लक्ष्य का पीछा काफी अच्छी तरह करती हैं। मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका औसत 100 से अधिक होगा, असाधारण उपलब्धि।
**लिसा स्थालेकर,** पूर्व कप्तान, आस्ट्रेलिया

मिताली तारीफ की हकदार हैं। वह भारतीय टीम के लिए पिछले 22 साल से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वह सभी खिलाड़ियों की आदर्श हैं।
**रमेश पोवार,** मुख्य कोच, भारतीय महिला टीम

**10,337** रन के साथ भारत की मिताली राज अब सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं

**34,357** रन भारत के सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, जो पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक हैं

## स्मिथ को उपमहाद्वीप में आठ टेस्ट मैच खेलने का इंतजार

**मेलबर्न, प्रेट्र:** आस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भारत के खिलाफ चार टेस्ट मैच सहित भारतीय उपमहाद्वीप में खेले जाने वाले इस प्रारूप के आठ मैचों के दौरान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।

भविष्य के दौरा कार्यक्रम के अगले चक्र में आस्ट्रेलिया को विदेशी दौरे पर भारत के खिलाफ चार, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ दो-दो टेस्ट मैच खेलने हैं। टीम को इसके साथ ही 10 टेस्ट मैचों की मेजबानी भी करनी है। स्मिथ ने कहा, 'मैंने भविष्य दौरा कार्यक्रम को देखा है और यह काफी व्यस्त है, इसमें काफी कुछ है। जाहिर तौर पर एशेज और फिर उपमहाद्वीप के दौरे हैं, जो विशेष रूप से टेस्ट क्रिकेट में आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौती पेश करेंगे। इसमें अच्छे दौरे हैं और एक खिलाड़ी के रूप में यह वास्तव में आपकी कड़ी परीक्षा लेगा। मैं निश्चित रूप से उसका इंतजार कर रहा हूं। मुझे लगता है डब्ल्यूटीसी बहुत अच्छी अवधारणा है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है।'

# टोक्यो रवाना होने से पहले दिल्ली में अभ्यास करेंगी जुडोका सुशीला

**ओलंपिक डायरी**

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने रविवार को कहा कि जुडोका सुशीला देवी दिल्ली में ही दो अभ्यास सहयोगियों के साथ टोक्यो ओलंपिक की तैयारी करेंगी। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकीं 48 किग्रा भार वर्ग की इस जुडोका के लिए साई ने नौ जुलाई से जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में शिविर की व्यवस्था की है।

सुशीला की अभ्यास में सहयोगी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की उनकी साथी होंगी। इनके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट और मसाज करने वाला अभी स्टेडियम परिसर के नए हास्टल में क्वारंटाइन पर हैं। साई ने कहा कि सरकार टोक्यो जाने वाले खिलाड़ियों को हर तरह से सहयोग और उनकी अच्छी तैयारियां सुनिश्चित कर रही है। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2014 की कांस्य पदक विजेता मोंगियाम कविता देवी (48 किग्रा) और 2018 की राष्ट्रीय चैंपियन निंगथोजाम शारदा (52 किग्रा) उनकी अभ्यास सहयोगी होंगी। सुशीला देवी और उनके कोच जीवन शर्मा राष्ट्रीय राजधानी से ही टोक्यो के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में ही उन्हें कोविड-19 का दूसरा टीका भी लगाया जाएगा। सुशीला की ओलंपिक में स्पर्धा 24 जुलाई को है।

**जापान पहुंचा सर्बियाई खिलाड़ी कोविड संक्रमित:** सर्बिया के नौकायन दल के एक सदस्य को टोक्यो ओलंपिक के लिए जापान पहुंचने पर कोविड-19 परीक्षण में पाजिटिव पाया गया है। जापानी एजेंसी क्योदो ने जापानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधकारियों के हवाले से रविवार को यह रिपोर्ट दी। अधिकारियों ने कहा कि इस खिलाड़ी को टोक्यो के हनेदा हवाईअड्डे पर ही अलग-थलग कर दिया गया। उनके साथ यात्रा कर रहे चार अन्य को हवाईअड्डे के पास में स्थित होटल में भेज दिया गया है। उन्हें मध्य जापान के नैंटो में अभ्यास शिविर में भाग लेने के लिए जाना था। अधिकारियों ने कहा कि इस अभ्यास शिविर को रद किया जा सकता है।

### ओलंपिक में वैकल्पिक खिलाड़ी भी बनेंगे टीम का हिस्सा

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों को देखते हुए कहा है कि आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों को स्टैंडबाई और वैकल्पिक खिलाड़ियों को कुछ खेलों की टीमों का हिस्सा बनाने की अनुमति दी जाएगी। ओलंपिक में टीम स्पर्धाओं में अन्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की तुलना में कुछ ही खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं लेकिन आइओसी ने अंतरराष्ट्रीय महासंघों (आइएफ) के साथ चर्चा के बाद कुछ खेलों में टीम चयन के लिए लचीलापन प्रदान करने का फैसला किया है। आइओसी ने कहा, 'पहले वैकल्पिक खिलाड़ी फुटबाल, हैंडबाल, हाकी, रग्बी और वाटर पोलो में उपलब्ध होते थे। हालांकि ये ओलंपिक टीम के लिए स्थायी स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर ही उपलब्ध होते थे। अब प्रत्येक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी) प्रत्येक मैच में इनका इस्तेमाल कर पाएगी।'





कहानी



शैली बक्षी खड़कोतकर

# विद्याकसम

मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी को अपने में समेटे बारिश के उत्सव और झूले के कौतूहल के बीच दो स्कूली सहेलियों के भावुक मन और प्यार भरे लगाव की अनूठी कहानी...

ए देख नई छोरी।

मालवा अंचल के कस्बेनुमा गांव की इकलौती शान 'रोज इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल' के गलियारों में आज कौतूहल उमड़ पड़ा था। आखिर, सन 1998 से अब तक, स्कूल के कुल जमा सात वर्ष के इतिहास में ऐसे दृश्य विरल ही थे। नया एडमिशन, वो भी केजी में नहीं, तीसरी में और तब जबकि स्कूल ही पांचवीं तक हो और लड़की का केजी समेत पांचवीं तक अंग्रेजी पढ़ने का सदुपयोग शादी में डिग्री की तरह होता हो।

-'सहर से अइ हे।'

-'सहर नी शहर.... गंवार..!'

-'श... इधर इ आ री हे...'

-'मेरा नाम निधि है, तुम्हारा?'

-'म... मेरा नाम... किरन!'

-'मैं इधर बैठ जाऊं?'

'ये गूंजी की जगे हे,.....पीछे लाली, फिर रेखा...'

'तो मैं कहां बैठूं?' नवागंतुक स्वर रुआंसा हो आया।

'तू यहां आजा।' पीछे से आवाज आई।

'थैंक यू।' अपरिचय के सागर में डूबते को इतना सहारा काफी था।

खुसुर-पुसुर फिर शुरू हो गई।

-'इंग्लिश बोलती हे।'

-'किरन, तूने क्यों नी बिठाया अपने पास?'

-'मेरे को तो कोई भाए नी, सहर की छोरीओन... बहुत इतराती हे।'

-'एक अई थी न दूसरी में थे अपन जब, तिमाही के पेले इ चली गई थी वापिस।'

-'वोई तो, इस सहर के लोगोन का मन थोड़ी न लगे गांव में।'

-'ओर ये सरिता को तो देख, आते इ अपने पास बिठा लिया।'

-'चली जई न, तब मालूम चलेगा।'

पूरी क्लास नई उपस्थिति से असहज थी। शहरी लड़की को इसका भान था। वह खुद नए परिवेश से सामंजस्य का यत्न कर रही थी।

-'साइंस का पीरियड है न, कौन सा चैप्टर?' नई लड़की ने उस सहृदय सहपाठिन से पूछा।

-'दूसरा।'

-'ये-'द नेचर एंड इट्स रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग?'

-'तू अंग्रेजी कित्ते फट से पढ़ लेती हे?' ये बात जान-बूझकर जोर से कही गई। तेल सनी चोटियों वाली चार-पांच मुंडियां पीछे पलटीं।

-'हमारे इस्कूल में इत्ती अंग्रेजी तो मेडम को भी नी आए।' हंसी का एक गुब्बारा फूटा, जिसमें दूसरी लड़कियों की हंसी भी घुल-मिल गई। भोले बचपन की गीली जमीन पर दोस्ती के बीज पड़ चुके थे। एक अफसर की नाजुक शहरी गुड़िया सी बेटी, एक संपन्न किसान की ठेठ ग्रामीण छोरी।

अगले दिन अनुभवी सहेली ने नई लड़की को स्कूल घुमाया, वो नियम-कायदे समझाए जिनका पालन कभी नहीं होता था, 'टीचरोन' को क्या कहकर चिढ़ाते हैं, वो बताया और गेट बंद होने पर बाजू के टीले से दीवार फांदकर आने की जुगाड़ समझाई। इस सद्भावना का प्रतिसाद शहर से लाए क्रीम बिस्किट से चुकाया गया। दिन धीमे-धीमे सरकने लगे और नई मैत्री अपने लिए नए आयाम खोजने लगी।

-'ये ले मेरे पेड़ के जामुन, भोत मीठे हे। फिर जबान देखना, नीली नट्ट....।'

-'मैं टिफिन में वेज कटलेट लाई हूं।'

-'ये विद्या किताब में रख ले, पास हो जईगी।'

-'तुमको इंग्लिश का लेसन समझ नहीं आया न, मैं समझाऊं?'

-'देख रंगीन चपेटे, तेरे को सिखा दूंगी, फिर मन पड़े तो तू इ रख लेना।'

-'और तुम ये लो, सेंट वाला रबर।'

-'शाम को खेलने अइगी?'

दोस्ती को विस्तार मिल गया। नई सखी नए खेल सीख रही थी, चपेटे, सितौलिया, पौआ...।

इस अलसाए कस्बे में गढ़ती दोस्ती की ऊर्जा से आषाढ़ के सूरज में भी चमक आ गई थी। दोनों साथ आती-जाती, खेलती, खिलखिलातीं। सूरज देख मुस्काता, उजास के आशीष लुटा विदा होता।

नई लड़की का मन यहां रमने लगा। अन्य सखियां उसके साथ सहज हो रही थीं, पर अपनी पुरानी सहेली को नई दोस्ती में मगन देख थोड़ा ईर्ष्या भाव भी कायम था। बूंदों की सरगम बजने लगी, कोयल तान देने लगी, धरती की हथेली पर हरियाली मेहंदी रचने लगी। बारिश ने दस्तक दे दी थी। शहरी परिवार गांव के वर्षा उत्सव को कौतुक से निहार रहा था। गांव की बहन-बेटियों, बहुओं को इंतजार रहता था तो सावन तीज की पूर्व संध्या पर सरिता के बगीचे में होने वाले आयोजन का। सरिता के घर से सारी व्यवस्थाएं होतीं, खाना-पीना, नाच-गाना, झूले, मेहंदी, चूड़ियां, एक छोटा सा मेला ही सजता। मां-बेटी को भी विधिवत निमंत्रण मिला। गांव की सारी सुंदरता, चंचलता, उमंग वहां सिमट आई थी। चहकती सखियां अमराई में डले झूलों की ओर चलीं तो शहरी मां ने ताकीद की, 'बेटा चलो, हमें जल्दी जाना है।' पर बेटी के लिए उत्सव नया था। उसने इसरार किया, 'मम्मी, मुझे झूला झूलना है, मैं सरिता के साथ आ जाऊंगी, प्लीज...।'

झूले के लिए लड़कियां रोमांचित थीं।

-'पेले सीमा, फिर में, फिर किरन...हे न सरिता?'

-'नी, सब में पेले निधि, फिर सीमा, फिर तू...।' लड़कियों ने कनखियों से एक-दूसरे को देखा। तब तक झूले को 'निधि' के रूप में अपना सवार मिल चुका था। झूला बचपन के ख्वाब सा हो गया था, इतना ऊंचा उठता, जैसे क्षितिज छू लेना चाहता हो।

इधर सरिता को अकेले पाकर लड़कियों ने छेड़ा, 'क्यों रे, हर बार तो अपन ऐसे ई झूलते हे न?'

-'इस बारी उसको झूल लेन दे। नोरात्रि के मेले में तू पेले झूल लेना।'

-'किरन, झूल लेन दे उसको। नोरात्रि तक वो तो रएगी नी, फिर...'

'क्यों नी रएगी वो...?' सरिता चौंक पड़ी।

'मेरे चाचा ने बताया, बड़े साब ने गुस्से से इसके पिताजी की यहां बदली कर दी थी, खूब कोसिस कर रए हे वापिस जाने की।' 'वापिस जाना' इन शब्दों ने हथौड़े सा प्रहार किया। तुरंत सखी को पुकारा गया, 'निधि... ए... निधि... सुन...'

'हां... बोलो!' जब झूला नीचे आया, तब पुकार सुनाई दी।

'तू वापिस जई री क्या?'

'नहीं तो...'

'सच्ची ना? रख विद्याकसम...?'

'हां! सच... विद्याकसम...' अब तक झूला फिर पींग भर ऊपर पहुंच चुका था, 'मैं नहीं जा रही अभी वापस। मैंने मम्मी को बोल दिया है कि मैं तुम्हारे साथ घर आऊंगी।' आखिरी वाक्य हवा में कहीं गुम हो गया, जिसे नीचे खड़ी सखियां सुन ही नहीं सकीं। 'विद्याकसम' अभी घर न जाने की बात पर ली गई है या शहर वापसी के लिए, इसे दोनों अपने-अपने संदर्भों के साथ जोड़कर निश्चिंत थीं।

'देख, वो झूठ नी बोलती, विद्याकसम भी ली उसने। नी जा रई वो शहर। लगे तो तू पूछ ले?'

'मेरे को क्या, तू ही पूछ लेना, वो आए तो।'

'नी, मेरे को भरोसा हे।'

सहेलियों ने खूब खेला, खाया, फिर हाथों में मेहंदी रचाई और नई चूड़ियां खनकाती घर आईं।

'मम्मी, आज बहुत मजा आया।' बेटी बोली।

'हां, बेटा। आज का दिन सचमुच अच्छा रहा। पापा को दोबारा शहर में पोस्टिंग मिल रही है, अभी खबर मिली है।'

बेटी की खुशी तत्क्षण गायब हो गई। गांव में बात फैलते कितनी देर लगती। अगले दिन स्कूल में नजारा बदला हुआ था। लड़कियां उसे टेढ़ी नजरों से देख रहीं थीं, किसी ने बात नहीं की। अपनी जगह पर बस्ता रखा। सरिता सिर झुकाए बैठी थी। नहीं... वह तो रो रही थी! आंखें सूजी, नाक लाल...।

-'क्या हुआ सरिता?'

-'तू जा रई हे, वापिस शहर...?'

-'हां...।'

-'तो, तू मेरे से झूठ क्यों बोली?'

-'कब?'

-'अच्छा...? कब...? कल पूछा नी मेने तेरे को, तू झूले पे थी तब कि वापिस जइगी क्या तो क्या बोली तू?' इतना बोलते हुए आवाज भर आई। प्रिय सखी से विछोह का दुख, उस पर दूसरी सखियों के ताने और सबसे बढ़कर कल जो भरोसा जताया था, उसके टूटने की पीड़ा।

-'झूले पर थी, तब? वो मैंने घर वापस जाने के बारे में बोला था। ट्रांसफर का कल घर जाने पर मम्मी ने बताया, सच में...।'

-'रेने दे, झूठी...! जा वापिस अपने शहर, मेरे को नी बात करनी तेरे से...जा तेरा खुशबू वाला रबर भी ले ले, नी चइए...'

-'सरिता...प्लीज, सुनो न। मैंने झूठ नहीं बोला।' पीड़ा यहां भी थी। शहर वापिस जाना होगा, इसका अंदाजा था, पर इतनी जल्दी? प्यारी सहेली को छोड़ने का दुख और उस पर ये तोहमत? धूल में पड़े तोहफे को उठाकर साफ किया और बस्ते में डाल लिया।

सरिता ने जगह बदल ली। छुट्टी में फिर कोशिश की गई, 'सरिता, बात तो करो, मैंने झूठ नहीं बोला, विद्याकसम।'

'तूने बोला नी जाएगी ओर अभी जा रही हे न ओर झूठी विद्याकसम खाएगी तो फेल हो जईगी।'

'अरे, मैंने शहर नहीं घर जाने के लिए बोला था... बदली का मुझको नहीं मालूम था।' उसके सब्र का बांध तोड़ रुलाई फूट पड़ी और वह दौड़कर घर पहुंची। घर में सामान की पैकिंग शुरू हो चुकी थी। छोटा भाई बक्सों पर कूदा-फांदी कर रहा था। बेटी की उदासी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अगले दिन बेटी ने स्कूल न जाने का एलान किया तो भी सहजता से मान लिया गया कि अब यहां स्कूल जाकर फायदा भी क्या।

चार दिन बाद बृहस्पतिवार को निकलना तय हुआ। आते मंगल दूसरे अफसर को इनकी जगह लेने पहुंचना था, लेकिन मंगल का बुध हो गया, वो नहीं आया तो खटका हुआ। दफ्तर से ट्रंक काल किया तब पता चला, उसने मंत्री की सिफारिश से तबादला रुकवा लिया और अब अगले साल तक कोई उम्मीद नहीं। घर में मायूसी छा गई, लेकिन कोई था घर में, जिसकी मुस्कान लौट आई थी, मन का बोझ उतर गया था, हाथ में कुछ दबाकर वह दौड़ पड़ी 'मम्मी मैं अभी आई...।' पैरों में पंख लग गए हों जैसे, दौड़ सीधे रुकी सरिता के घर के बाहर, 'सरिता... सरिता... '

इस वक्त आवाज सुन नाराज सखी भी भागी आई।

'मैं नहीं जा रही शहर, सरिता। देखो मैंने झूठ नहीं बोला था न?'

'क्या बोल रई, सच्ची...? विद्याकसम।'

'सच, विद्याकसम। ट्रांसफर कैंसिल... इस साल यही रहेंगे हम। ये लो, अपना खुशबू वाला रबर।'

'ओर जो आते बरस तेरी बदली हुई तो? तो... मैं फिर से कुट्टी कर लूंगी और खुशबू वाला रबर वापिस कर दूंगी।'

'हां, कर देना तो फिर से बदली रुक जाएगी।'

'उसके आते बरस हुई... तो फिर कुट्टी और रबर वापिस।'

'तो फिर बदली कैंसिल...।'

दोनों सखियों की उन्मुक्त हंसी रबर की भीनी खुशबू के साथ हवा में बिखर रही थी।

shaily_157@rediffmail.com



रेखांकन-ब्रिज

गीत



अनामिका सिंह

# जलजीवन आधार



बूंद-बूंद हर एक कीमती
मत करना बेकार
जलजीवन आधार।

जैव चक्र का चक्का उतरा
काट दिए जंगल,
जल के सारे स्रोत सुखाकर
चाहें निज मंगल।
बोनसाई कर सजा लिए हैं
गमलों में पीपल,
इसीलिए कुदरत ने डाले
हैं माथे पर बल।

अधिक देर अब होगी घातक
वृक्ष लगा लें चार
जलजीवन आधार।

नहीं उलीचें बेमकसद जल
कर लें संवर्धन,
रीती गागर सूने पनघट
करें मौन गर्जन।
सूखे गले टिटहरी के हैं
धरती हुई गरम,
कौन घाट पर जाऊं पूछे
आंखें लेकर नम।

यही शिकायत करती सिमटी
देख नदी की धार
जलजीवन आधार।

अब बादल से अनबन टूटे
एक यही है हल,
बिन वर्षा के जल का टोटा
निश्चित होगा कल।
संरक्षण हित हमें खोदने
गहरे होंगे ताल,
तभी संवारा जा सकता है
कल धरती का हाल।

जलजीवन का मूल घटक है
इसी पंक्ति में सार
जलजीवन आधार।

yanamika0081@gmail.com

स्मरण



डा. राकेश शुक्ल

# अनूठे साहित्य सर्जक

व्यक्तिगत जीवन और साहित्य में मानवीय करुणा, संवेदनशीलता और जीवन मूल्यों के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले गिरिराज किशोर हिंदी के उन विरल साहित्य सर्जकों में थे, जिनका लेखन बहुविध और प्रभूत है...



अपनी 50 वर्ष से अधिक की रचना यात्रा में गिरिराज किशोर जी ने अनेक उत्कृष्ट कृतियों की रचना की। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के संघर्षमय जीवन पर आधारित उनका कालजयी उपन्यास 'पहला गिरमिटिया' सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। कस्तूरबा के जीवन पर आधारित 'बा' उपन्यास भी गिरिराज किशोर जी ही लिख सकते थे।

आठ जुलाई 1937 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक जमींदार परिवार में जन्मे गिरिराज जी के पिता श्री सूरज प्रकाश अंग्रेजी, फारसी तथा उर्दू के विद्वान थे, पर उनके पितामह के छोटे भाई हिंदी प्रेमी थे, जिनसे उन्हें हिंदी साहित्य पढ़ने और इस भाषा में लिखने की प्रेरणा मिली। विशेष बात यह कि लेखन के बीज भी उनमें सामंती व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना के कारण ही पड़े। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाभिमानी गिरिराज जी ने अनेक नौकरियां छोड़ीं। इलाहाबाद (अब, प्रयागराज) के साहित्यिक वातावरण में उनकी प्रतिभा में निखार आया, पर बेहतर आजीविका के लिए उन्हें कानपुर आना पड़ा और फिर वह यहीं के होकर रह गए।

गिरिराज जी का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है। पहला उपन्यास 'लोग'-1966 तथा 'जुगलबंदी'-1973 में आजादी के पहले के अंग्रेज परस्त सामंतों की मानसिकता का यथार्थ अंकन है तो 'चिड़ियाघर', 'इंद्र सुनें', 'दावेदार', 'अंतर्ध्वंस' तथा 'ढाई घर' में आजादी के बाद के जीवन में तेजी से हो रहे बदलावों को स्वर दिया गया है। उनके उपन्यासों में एक ओर शोषणमूलक व्यवस्था पर करारा प्रहार किया गया है तो दूसरी ओर बदलते जीवन मूल्यों के संदर्भ को भी हमारे सामने रखा गया है। 'यात्राएं' तथा 'दो' ऐसे ही उपन्यास हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार पर 'यथाप्रस्तावित' तथा 'परिशिष्ट' जैसे उपन्यास लिखे तो 'आंजनेय जयते' में हनुमान के मिथकीय चरित्र को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। उनके नाटकों और कहानियों में भी अनुभवों की विविधता है। 'संवाद सेतु', 'लिखने का तर्क', 'कथ अकथ', 'सरोकार', 'एक जन भाषा की त्रासदी', 'सप्तपर्णी' तथा 'जन जनसत्ता' में संकलित उनका वैचारिक लेखन समाज विज्ञान की दृष्टि से भी बहुमूल्य है।

आजीवन कानपुर के एक छोटे से मकान में रहने वाले अतिशय आतिथ्यप्रेमी गिरिराज जी ने न जाने कितने नवांकुरों का मार्गदर्शन किया था। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की कीर्ति अर्जित की थी, पर कानपुर के जन सामान्य को भी उन्होंने इस कदर अपना बना लिया था कि 10 फरवरी 2020 को जब उनका पार्थिव शरीर देहदान हेतु मेडिकल कालेज ले जाया जा रहा था तो आंसुओं से भरा जन सैलाब उनके पीछे चल रहा था।

rakeshshukla940@gmail.com

संस्मरण



ममता कालिया

# वह अविस्मरणीय गोष्ठी

इलाहाबाद (अब, प्रयागराज) में होने वाली साधारण सी साहित्यिक गोष्ठी कैसे बेहद दिलचस्प हो जाती है। ऐसी ही एक गोष्ठी के दौरान घटित हुआ रोचक प्रसंग वरिष्ठ लेखिका की कलम से...

यह इलाहाबाद की फितरत है। कैसी बड़ी गोष्ठियां हमारे अपने घर में आयोजित हुईं, जिनका नाम निशान तक हमारे एलबमों में नहीं है। लोगों की स्मृतियों में है। वे स्मृतियां हम सबके साथ चली जाएंगी। अभी छायाकार, रंगकर्मी अजामिल ने याद दिलाई हमारे घर रानी मंडी में हुई एक संगोष्ठी की। उतनी शानदार गोष्ठी हमारे यहां शायद ही कभी हुई हो। उस कथा गोष्ठी के मुख्य अतिथि थे कमलेश्वर। उनके नाम के साथ, फिल्म, टेलीविजन, पत्रकारिता और रचनात्मक लेखन का मिला जुला ग्लैमर था। नतीजा यह हुआ कि हिंदी-उर्दू के लेखकों और पाठकों का बेकाबू जुटान हो गया। इस जुटान में स्थापित लेखक तो थे ही, क्योंकि वे सब कमलेश्वर के दोस्त थे, अमरकांत, मार्कण्डेय, भैरवजी, लक्ष्मीकांत वर्मा, फातिमी, असरार गांधी, एसएमए काजमी, उमेश नारायण शर्मा, शैलेश मटियानी, अमर गोस्वामी, अजामिल आदि। कमरे में जगह भर गई तो लोग सीढ़ियों पर बैठे। जरा नीचे आफिस था, उसकी भी सब कुर्सियां भर गईं। कमलेश्वर जी के जो बेशुमार गुण थे उनमें सबसे बड़ा था आत्मीयता और बेतकल्लुफी। वह हर आगंतुक को नाम से पहचानते थे। कमलेश्वर आराम से जमीन पर बिछे डबल गद्दे पर मसनद के सहारे बैठे थे। यह सन् 1974-75 की बात होगी। हमारा बेटा अनिरुद्ध तब तीन साल का था। वह भीड़ को चीरता हुआ बैठक में आया और सीधे कमलेश्वर जी की गोद में बैठ गया। मैंने लाख जतन किया कि वह उनकी गोद से उतर कर मेरी गोद में बैठ जाए, पर अन्नू क्या जो मान ले। कमलेश्वर जी ने कहा, 'ममता रहने दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं।'

अतिथियों की इतनी विशाल संख्या देख मेरे मन में आया कि घर में मौजूद प्लेट-प्याले चाय के लिए कम पड़ेंगे। मैंने रवि (रवींद्र कालिया) को बुलाकर कहा, 'तुम जल्दी से लोकनाथ (इलाहाबाद का एक प्रसिद्ध बाजार) से कुल्हड़ खरीद लाओ।' पास ही बाजार था। रवि ने स्कूटर निकाला और बाजार चल दिए। उन्होंने कुल्हड़ खरीदे और थोड़ा ज्यादा नमकीन कि कोई चीज कम न पड़े। जब वह सामान से लदे-फंदे घर की गली की ढलान उतरे, न जाने कहां से गली की चक्कीवाली का छोटा बेटा अचानक बीच सड़क पर आकर रवि के स्कूटर से टकरा गया। चक्कीवाली का आधा परिवार गली को आंगन समझ वहीं उठता-बैठता था। बच्चा गिर गया था। उसके घुटने छिल गए। बच्चा बुक्का फाड़कर रोने लगा। रवि बच्चे से भी ज्यादा घबरा गए। चक्कीवाली दौड़ी आई और चिल्लाने लगी, 'बाबूजी होस में नई हो, जो हमरे लरिका को कुछ होइ जाई तो कौन से ले बू। यह पेटपोंछना है।' रवि ने बच्चे को उठाया, प्यार दिया और कहा, 'इसे बगल के डाक्टर को दिखाओ, जो खर्चा होगा मैं दूंगा।' चक्कीवाली भड़क गई। वह धर्मशाला में लगी तमाशबीनों की भीड़ से मुखातिब हो गई, 'लो सुन लो बड़े लोगन के बोल। बचवा खूनमखून हुई गवा, इन्हें बगल का डाक्टर दिख रहा। बाबूजी सीधे बड़े डाक्टर के लइके चलो बचवा को।'

रवि ने घर का सामान साइकिल की दुकानवाले आदमी लल्लन को पकड़ाया और कहा, 'घर पर बता देना मैं अभी आता हूं।'

लल्लन भी हमारी गली का बाशिंदा था। हमारा घर अच्छी तरह से जानता था। ड्योढ़ी में उसने इतने लोग खड़े देखे तो लोगों को ही कुल्हड़ और पुड़े पकड़ाकर चला गया कि बाबूजी ने भेजे हैं। थोड़ी देर में खबर मुझे मिली कि कुल्हड़ आ गए हैं। मैं ऊपर गई। चाय का पानी कब से अंगीठी पर खौल रहा था। मुझे अंदर ही अंदर रवि पर गुस्सा आ रहा था कि जहां जाते हैं देर लगाते हैं। गोष्ठी, चाय और अन्नू तीनों का झमेला मेरे ऊपर डालकर सटक गए हैं। वह तो कमलेश्वर का कमाल और हिंदी-उर्दू अफसाना निगारों की खूबी थी कि उन्होंने गोष्ठी जारी रखी। गोष्ठी में कुछ लड़कियां भी थीं। मालती और उनकी मदद से मैंने सबको चाय पेश की। बहुत देर बाद जब लोग उठने के मूड में आ चुक थे, रवि ड्योढ़ी में स्कूटर रखकर नमूदार हुए।

कमलेश्वर ने कहा, 'तुम क्या किसी और गोष्ठी में चले गए कालिया।'

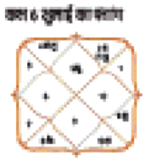
रवि की सांस फूली हुई थी। उन्होंने कहा, 'नहीं वह चक्कीवाली का बच्चा...।'

अभी वह आगे बोल पाते कि कमलेश्वर ठठाकर हंस पड़े, 'कालिया, किस चक्कीवाली के चक्कर में पड़ गए तुम?'

रवि ने धीरे-धीरे पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे चक्कीवाली की गोद में बच्चे को बिठाकर रवि उन दोनों को डाक्टर दरबारी के यहां लेकर गए। ए टी एस इंजेक्शन लगवाया, मरहम पट्टी करवाई और घर वापस लाकर छोड़ा।

काजमी साहब ने कहा, 'चलो खैर हुई। अब आप अपने घर की मीटिंग का हाल कल अखबार में पढ़ना।' बाद के बरसों में भी कमलेश्वर जी कभी-कभी रवि को छेड़ते, 'तुम्हारा चक्कीवाली से चक्कर खत्म हुआ कि नहीं।' बच्चे के इलाज और दूध, बिस्किट की सप्लाई भेजने का नतीजा यह निकला कि चक्कीवाला भी रवि को अपना रकीब समझने लगा।

mamtakalia011@gmail.com







राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 5 जुलाई, 2021
# आजकल
14
www.jagran.com

## सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने शुरू किया कारोबार

वर्ष 1994 में आज ही के दिन जेफ बेजोस ने वाशिंगटन में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की नींव रखी थी। शुरुआत में उन्होंने 20 उत्पादों की सूची तैयार की थी, लेकिन मुख्य फोकस किताबें बेचने पर था। दो हफ्ते में ही उनकी कंपनी को हर हफ्ते 20 हजार डॉलर की कमाई होने लगी।



## पाकिस्तान में जिया उल हक के नेतृत्व में सेना ने किया तख्तापलट

वर्ष 1977 में आज ही के दिन जनरल जिया उल अक के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पद से हटाकर शासन अपने हाथ में ले लिया था। इसे 'ऑपरेशन फेयरप्ले' का नाम दिया गया था। बाद में भुट्टो को फांसी दे दी गई थी।

## पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता ओलंपिक का रजत पदक



वर्ष 1995 में आज ही के दिन हैदराबाद में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का जन्म हुआ था। उन्होंने आठ वर्ष की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2009 में श्रीलंका में खेलकर कांस्य पदक जीता। वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। बैडमिंटन में शानदार खेल के लिए वर्ष 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2015 में पद्मश्री, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।

# चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने नए स्टेशन के बाहर पहली स्पेसवॉक की

**बीजिंग, एपी :** चीन के दो अंतरिक्ष यात्रियों ने रविवार को पहली बार चीन के निर्माणाधीन नए अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेसवॉक की है। उन्होंने यह सफल स्पेसवॉक एक 15 मीटर (50 फीट) लंबे रोबोटिक आर्म बनाने के काम को पूरा करने के लिए की है।

चीनी अंतरिक्ष यात्री लियू बोमिंग और टैंग होंगबो को चीन के सरकारी टीवी द्वारा एयरलॉक से बाहर अंतरिक्ष में निकलते हुए दिखाया गया। उनके बाहर आने पर ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी उनके ठीक नीचे हो। इस दल के तीसरे सदस्य और कमांडर नी हैशेंग अंतरिक्ष यान के अंदर रहकर ही उसे संचालित करते रहे।

यह अंतरिक्ष यात्री विगत 17 जून को चीन के तीसरे कक्षीय स्टेशन पर तीन महीने के मिशन के लिए पहुंचे हैं। अंतरिक्ष में यह गतिविधियां चीन के एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत मई में मंगल ग्रह पर रोबोट रोवर को उतारा था। उनका यह खास मिशन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाने के नजदीक अंजाम दिया जाएगा।



चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर स्पेसवॉक करते अंतरिक्ष यात्री लियू बोमिंग और टैंग होंगबो। उन्होंने 15 मीटर लंबे रोबोटिक आर्म बनाने का काम किया। एपी

**50** फीट लंबी रोबोटिक आर्म बनाने के लिए उठाया जोखिम

### कुल 11 लांच की योजना

अंतरिक्ष एजेंसी अगले साल के अंत तक 70 टन के स्टेशन में दो और मॉड्यूल जोड़ने के लिए कुल 11 लांच की योजना बना रही है। लियू 2008 में शेनझोउ-7 मिशन से पहले ही अनुभव हासिल कर चुके हैं। इस दौरान झाई झिगांग ने पहली अंतरिक्ष यात्रा की थी। नी अंतरिक्ष में अपनी तीसरी यात्रा पर हैं। सभी सैन्य पायलट हैं।

स्टेशन का पहला मॉड्यूल, तियानहे, या हेवनली हार्मनी, 29 अप्रैल को लांच किया गया था। यह भोजन और ईंधन से युक्त एक स्वचालित अंतरिक्ष यान से किया गया था। लियू, नी और टैंग 17 जून को शेनझोऊ कैप्सूल से पहुंचे।

रविवार को लियू और टैंग एक रोबोटिक आर्म की स्थापना को पूरा कर रहे थे। इसका उपयोग स्पेस स्टेशन के बाकी हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाएगा। चीन के सरकारी टीवी के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे जरूरत पड़ने पर छह घंटे तक अंतरिक्ष के शून्य में काम कर सकें।



## रेगिस्तान में योग...

मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाके स्यूदाद जुआरेज के समलायुका ड्यून्स में योग करते लोग। योग को लेकर यह छठी वार्षिक बैठक इस वर्ष आउटडोर करने का निर्णय लिया गया था। इस मौके पर योग के जरिये वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने लोगों के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया गया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुनियाभर में योग के प्रति लोगों का रुझान काफी तेजी से बढ़ा है। रायटर

### इधर-उधर की

## अमेजन की डिवाइस के चलते बदलना पड़ा नाम

**लंदन, एजेंसी :** जहां एक ओर नई-नई तकनीक आने से लोगों के काम आसान हुए हैं, वहीं कई लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ताजा मामला अमेजन की वॉयस असिस्टेंट डिवाइस 'एलेक्सा' से जुड़ा है। इस डिवाइस के नाम को लेकर ब्रिटेन में एक बच्ची की मां इस कदर परेशान हुई कि उसने उसका नाम ही बदल दिया। महिला के मुताबिक एलेक्सा नाम होने के चलते स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे। बेटी मजाक उड़ाए जाने के डर से अपना नाम बताने से डरने लगी थी। कई बार शिकायत के बावजूद स्कूल से कोई मदद नहीं मिल रही थी। महिला ने कहा कि बेटी का नाम बदलने के साथ ही उन्होंने अब उसे दूसरे स्कूल भेजने का निश्चय किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 25 साल से कम उम्र के करीब चार हजार लोग हैं, जिनका नाम एलेक्सा है।



ब्रिटेन में 25 साल से कम उम्र के करीब चार हजार लोग हैं, जिनका नाम एलेक्सा है। इंटरनेट मीडिया

# चार साल बाद दिखी सूर्य पर विशाल ज्वाला

## खगोलीय घटना ▶ सूर्य से निकली एक्स श्रेणी की ज्वाला से सौर विज्ञानी अचंभित

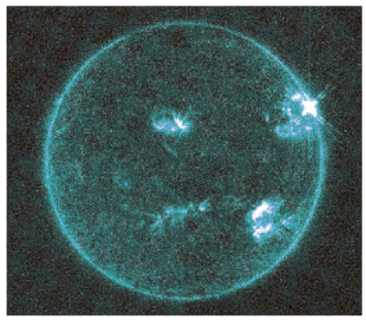
### सूर्य के कई हिस्सों में अब भी उभरे हुए हैं कई सनस्पॉट

**रमेश चंद्रा, नैनीताल**

सूर्य के उत्तर पूर्वी छोर से अचानक निकली एक्स श्रेणी की विशाल ज्वाला ने दुनियाभर के विज्ञानियों को अचंभित कर दिया। इतनी बड़ी ज्वाला यानी सोलर फ्लेअर चार साल बाद देखने को मिली। दुनिया की कई अंतरिक्ष वेधशालाओं ने इस ज्वाला की तस्वीरें ली हैं। सूर्य में तीन सनस्पॉट यानी सौर कलंक समूह अभी बने हुए हैं। जिनसे और सोलर फ्लेअर निकलने की आशंका बनी हुई है।

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) नैनीताल के वरिष्ठ सौर विज्ञानी डा. बहाबउद्दीन ने बताया कि सूर्य में यह ज्वाला भारतीय समयानुसार शनिवार रात आठ बजकर पांच मिनट पर निकली है। हैरानी की बात यह है कि शनिवार सुबह तक इस क्षेत्र में कोई सनस्पॉट नहीं बना था, जिससे फ्लेअर निकलने का अनुमान लग पाता। शाम अचानक सनस्पॉट उभरा और उभरने साथ ही उसमें से एक्स 1.6 श्रेणी की ज्वाला निकल पड़ी। बिना किसी पूर्वानुमान के अचानक निकली ज्वाला से दुनियाभर के सौर विज्ञानियों को अचंभित कर दिया। यह 25वां सोलर साइकिल है, जिसमें पहली बार एक्स श्रेणी की ज्वाला निकली है। इससे पूर्व सितंबर 2017 में एक्स श्रेणी की ज्वाला सूर्य से निकली थी। तब 24वें सोलर साइकिल का अंतिम चरण चल रहा था। नए सोलर साइकिल में एम श्रेणी तक की ज्वालाएं अभी तक निकल चुकी हैं। जबकि एक्स श्रेणी की ज्वाला का विज्ञानियों को इंतजार था। सूर्य में पिछले कई दिनों से तीन सनस्पॉट समूह बने हुए हैं। जिनसे बड़ी ज्वालाएं निकलने की उम्मीद है। सूर्य की निगरानी के लिए एरीज में सोलर टेलीस्कोप मौजूद है। सूरज में यह घटना रात के समय होने के कारण एरीज से इस ज्वाला की तस्वीरें नहीं ली जा सकी। बहरहाल सूर्य पर उभरे सनस्पॉट पर एरीज के विज्ञानी नजरें जमाए हुए है।

**बेहद खतरनाक होते हैं सूर्य से निकलने वाले सौर तूफान :** डा. बहाबउद्दीन ने बताया कि सोलर फ्लेअर का निकलना सूरज में होने वाली सामान्य घटना है, लेकिन इनसे निकलने वाले सौर तूफान पृथ्वी के इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रीकल उपकरणों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। वहीं यह आसमान में विचरते सेटेलाइट व हवाई जहाजों के लिए भी खतरनाक होते हैं। जिस कारण विज्ञानी सूर्य की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हैं।



शनिवार रात नासा के एसडीओ से ली गई सूर्य की ज्वाला की अल्ट्रावायलेट तस्वीर। सौ. एरीज

# त्वचा और जोड़ों को रखना है दुरुस्त तो करें संतुलित भोजन

### अनुसंधान



अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार जरूरी है। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

अगर आप त्वचा या जोड़ों की सूजन से परेशान हैं तो नियमित संतुलित आहार लेकर इन बीमारियों से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। यूसी डेविस हेल्थ के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। अध्ययन में पाया गया कि त्वचा की सूजन का कारण चीनी और वसा की अधिक मात्रा लेना भी हो सकता है। चीनी और वसा आंत में माइक्रोबियल कल्चर का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इस कारण से विशेषतौर पर सोरायसिस जैसी बीमारी के खतरे बढ़ जाते हैं। अध्ययन के परिणाम जर्नल आफ इनवेस्टिगेटिव डर्मेटोलाजी में प्रकाशित हुए हैं। यूसी डेविस हेल्थ के प्रोफेसर और अध्ययन का नेतृत्व करने वाले सेम टी वांग ने कहा कि पूर्व में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पश्चिमी देशों के आहार में चीनी और वसा का ज्यादा प्रयोग होता है। इस कारण त्वचा में सूजन की आशंका अधिक रहती है। यहां तक कि सोरायसिस के खतरे बढ़ जाते हैं। सोरायसिस एक त्वचा रोग होता है। इसमें त्वचा पर एक परत चढ़ जाती है जो लाल रंग के चकत्ते के रूप में दिखाई देती है। सोरायसिस के 30 फीसद मरीजों में गठिया का खतरा भी बढ़ जाता है। इसमें सुबह उठने पर शरीर में जकड़न, थकान, अंगुलियों में सूजन, जोड़ों में दर्द और नाखूनों में बदलाव जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं। यह अध्ययन चूहों पर किया गया था। इसमें ये भी देखा गया कि बीमारी के लक्षण आने के बाद संतुलित आहार यानी वसा और चीनी की संतुलित मात्रा लेने से फायदा हुआ। (एएनआइ)

## स्क्रीन शॉट



शाह रुख का फिल्म मांगने का अंदाज है कमाल। जागरण आर्काइव

# शाह रुख खान ने मांगा आलिया से काम!

**स्टार चाहे कितना** भी बड़ा क्यों न हो, खुद के लिए काम तलाशने और काम मांगने में कोई बुराई नहीं होती है। अब किंग खान शाह रुख खान को ही ले लीजिए। अजीब जरूर लगेगा, लेकिन शाह रुख भी सामने से काम मांगने में कोई बुराई नहीं समझते हैं। उन्होंने तो ट्विटर पर दुनिया के सामने आलिया भट्ट से काम मांग लिया। आलिया अपनी प्रोडक्शन कंपनी में बनने वाली पहली फिल्म डार्लिंग्स की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा करके दी थी। इस फिल्म के सह निर्माता शाह रुख भी हैं। उनकी और आलिया की प्रोडक्शन कंपनी मिलकर फिल्म को बना रही है। ऐसे में शाह रुख ने ट्विटर पर आलिया से काम मांगते हुए लिखा, 'इस प्रोडक्शन के बाद प्लीज अपने अगले होम प्रोडक्शन के लिए मुझे साइन कर लो। मैं शूटिंग के लिए टाइम पर आऊंगा और बहुत प्रोफेशनल रहूंगा, वादा।' इस पर आलिया ने भी मजेदार जवाब देते हुए लिखा, 'मैं इससे ज्यादा और कुछ मांग ही नहीं सकती थी। डील डन, आपको साइन कर लिया है। मेरे पसंदीदा को ढेर सारा प्यार।' शाह रुख खान इस प्रोजेक्ट पर भले ही बतौर सह निर्माता जुड़े हों, लेकिन इससे पहले शाह रुख और आलिया डियर जिंदगी फिल्म में एकसाथ स्क्रीन साझा कर चुके हैं।

# स्टार किड्स आलसी नहीं हैं : हर्षवर्धन राणे

**इन दिनों अभिनेता** हर्षवर्धन राणे नैनीताल के पास रानीखेत में रह रहे हैं। वहां वह अपनी आगामी एक्शन फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर स्टार किड्स और आउटसाइडर्स को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा चलती रहती है कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है या किसे आसानी से काम मिल गया है। हर्षवर्धन खुद आउटसाइडर हैं, लेकिन वह स्टार किड्स की मेहनत से भी काफी प्रभावित हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में हर्षवर्धन ने कहा कि इनसाइडर और आउटसाइडर का मुद्दा काम से भागने का केवल एक बहाना है। जो मेहनत करते हैं उन्हें इनसाइडर और आउटसाइडर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के दौर के कई बड़े स्टार्स जैसे आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव सब फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से ही आए हैं, लेकिन जो स्टार किड्स काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वे आलसी हैं। वे भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, जितनी हम आउटसाइडर्स कर रहे हैं। नेपोटिज्म का मुद्दा चर्चा और बहस करने के लिए ठीक है। मुझे लगता है जिसे काम नहीं करना है या बहाने बनाने हैं, वह हजारों बहाने बना सकता है। हम खुद जिम्मेदार होते हैं कि हमें काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरों को या तकदीर को दोष देना सही नहीं है। कहां तक हम नेपोटिज्म का बहाना लेकर बैठेंगे। रानीखेत में वक्त बिताने को लेकर हर्षवर्धन कहते हैं कि यहां एक एक्शन फिल्म की ट्रेनिंग कर रहा हूं। हालांकि, मुझे बचपन से ही आउटडोर की आदत रही है। घूमना-फिरना पसंद है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें घरवालों की याद नहीं आती है, लेकिन क्या करूं मुझे प्रकृति के बीच रहना भी बहुत पसंद है।



एक्शन फिल्म की तैयारी कर रहे हैं हर्षवर्धन। इंस्टाग्राम

# आज के गायक इस डर में नहीं गा रहे कि उन्हें कोई जज करेगा : शान

**बदलते दौर के** साथ काम करने के तरीकों में बदलाव आता है। गायिकी के क्षेत्र में आए बदलावों को गायक शान पहले से बेहतर मानते हैं। एक लाइव चैट के दौरान शान ने कहा कि आज के युवाओं को जब गाते हुए देखता हूं तो उनकी आवाज में एक आजादी महसूस होती है। वह इस डर के साथ नहीं गा रहे हैं कि उन्हें कोई जज करेगा। वह जैसा गाना चाहते हैं, वैसा ही गा रहे हैं। गाना जब फिल्मों के लिए गाया जाता है तो उसमें बहुत अनुशासन रखना पड़ता है। जिस हीरो के लिए आप गाना गा रहे हैं, उसके स्टाइल को समझना होता है। कंपोजर के विजन और गाने को लेकर जो वह बारीकियां चाहते हैं, उस पर खरा उतरना पड़ता है। गायिकी के क्षेत्र में मेरे करियर की शुरुआती दौर में जो लड़कियां आई थीं, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह आशा जी और लता जी की रेंज में गाएं, जो संभव नहीं था। मंगेशकर बहनें लेजेंड्स हैं। सुनिधि चौहान ने अपनी अलग आवाज से गायिकी के दौर को बदला। अब गायकों के मुताबिक गाने का स्केल बनाया जाने लगा है। आज के गायक अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक गाना गाते हैं, जबकि हम कंपोजर की पर्सनालिटी के मुताबिक गाते आए हैं। जो गाना सुनने वाले लोग हैं, उनमें भी बदलाव आया है। अब के संगीत प्रेमी पहले के लोगों की तरह जिद्दी नहीं हैं कि फलां तरीके का ही गाना सुनना है। पहले लोग गाने में तुरंत गलतियां निकाल देते थे, लेकिन आज के सुनने वाले गायक के अनोखेपन को अपनाकर उन्हें मौका देते हैं। गायक बनने का यह अच्छा वक्त है।



गायकों के लिए इस दौर को अच्छा मानते हैं शान। इंस्टाग्राम

# मैं बस यही चाहती हूं कि काम करके घर लौटने के बाद खुश रहूं : श्वेता

मसान और हरामखोर जैसी फिल्मों की अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी इन दिनों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय हैं। मिर्जापुर और लाखों में एक जैसी वेब सीरीज के बाद अब वह द गॉन गेम के दूसरे सीजन की शूटिंग कर रही हैं। छह जुलाई को अपना 36वां जन्मदिन मना रही श्वेता से उनके करियर और आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई बातचीत के अंश :

सात सवाल

**● कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घर में रहकर क्या चीजें सबसे ज्यादा याद आई?**

-अकेले रहकर आप मेहनत करके सिर्फ अपनी स्किल्स (कौशल) को सुधार सकते हैं, लेकिन अकेले में एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। मैंने दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान सेट पर एक साथ मिलकर काम करने वाले इस अहसास को बहुत मिस किया। अब अभिषेक सेनगुप्ता के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज द गॉन गेम 2 के सेट पर शूटिंग करते हुए इस अहसास का आनंद ले रही हूं।

**● पिछले सीजन की अपेक्षा द गॉन गेम 2 में क्या-क्या नया होगा?**

-दूसरा सीजन तो पूरा ही बदल गया है। पहले सीजन को हमने लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से शूट किया था। दूसरे सीजन को बाकायदा प्रोफेशनल सेट अप के साथ शूट किया जा रहा है। मेरा किरदार अमारा गुजराल बहुत जटिल है, इसमें कहानी कुछ ऐसी होती है कि उसे कई भावनात्मक अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इसकी शूटिंग जुलाई के अंत तक खत्म होगी।

**● बतौर कलाकार प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता आपको कितना प्रभावित करती हैं?**

-मैं हमेशा से बस यही चाहती थी, मैं जब काम करके घर आऊं तो खुश रहूं, फिर भले ही मुझे सेट पर अपने किरदार में रोना पड़ा हो। द गॉन गेम 2 में भी मेरा किरदार अमारा कई जगह टूट जाती है। ऐसे सीन करते हुए कई बार आप इमोशनली और मेंटली काफी थक जाते हैं, लेकिन सेट पर इतना रोने के बाद भी मैं रात में संतुष्टि के साथ सोती हूं। क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने अपने किरदार को अपना शत-प्रतिशत दिया है। शो सफल होता है या नहीं यह तो हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे साथ में सिर्फ इतना होता है कि हम सेट पर कैसे काम करते हैं।

**● आपकी ज्यादातर फिल्में आर्टिस्टिक रही और फिलहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रियता का क्या कारण है?**

-शुरुआत में तो अपने आप आर्टिस्टिक फिल्में होती गईं, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसलिए नहीं गई कि मुझे फिल्मों या टेलीविजन में काम नहीं मिल रहा था, मैं इसलिए गई कि यहां मुझे मेड इन हैवेन, मिर्जापुर और लाखों में एक जैसे बेहतरीन कहानियों का हिस्सा बनने का मौका मिला।

**● साल 2009 में धारावाहिक क्या मस्त है लाइफ से शुरू करने के 12 वर्षों बाद इंडस्ट्री में अपने अनुभव कैसे देखती हैं?**

-मेरे लिए यह साल बहुत मजेदार रहे हैं। मेरी पहली फिल्म मसान को लोगों बहुत प्यार दिया, उसके बाद हरामखोर, द गॉन केश, लाखों में एक और मिर्जापुर जैसे कई प्रोजेक्ट आए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मसान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम मिलेगा या फिर हरामखोर में मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जब किसी समीक्षा में आपके काम की तारीफ होती है, तो लगता है कि आप कुछ तो ठीक कर रहे हैं।

**● इस बार जन्मदिन की क्या योजनाएं हैं?**

-शूटिंग के बीच से मुझे फिलहाल कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई है, इसलिए इस बार मैं सिर्फ बर्थडे नहीं, बल्कि मुंबई में अपने परिवार और दोस्तों के साथ बर्थडे वीक मनाने वाली हूं। मुझे फिल्मों के सेट पर काम करते हुए या सफर करते हुए जन्मदिन मनाना बहुत पसंद है। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मुझे ऐसी चीजें पसंद आती हैं जो किसी के इस्तेमाल के लायक हों। हर जन्मदिन पर मेरे पति चैतन्य शर्मा मेरे लिए एक कविता लिखते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुझे अपने इस विशेष गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

**● फिल्म रश्मि रॉकेट में भी आप काम कर रही हैं..**

-फिल्म के निर्देशक आकर्ष खुराना मेरे दोस्त हैं। उनके कहने पर ही मैंने इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस (मेहमान भूमिका) की है। इसके अलावा मेरी वेब सीरीज काली काली आंखें की शूटिंग पूरी हो चुकी है और दूसरी वेब सीरीज इस्केप लाइव की शूटिंग द गॉन गेम 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद अगस्त महीने से शुरू होगी।

(दीपेश पांडेय)



फिल्म रश्मि रॉकेट में मेहमान भूमिका में दिखेंगी श्वेता त्रिपाठी ● पीआर टीम

# आर्मी अफसर होते हैं असली हीरो : गौतम रोडे



आर्मी अफसर के किरदार में होंगे गौतम। इंस्टाग्राम

**कुछ किरदार** ऐसे होते हैं, जिन्हें निभाना भले ही चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उन किरदारों की अपनी अहमियत होती है। खासकर सेना से जुड़े किरदार जब कलाकार निभाते हैं तो वह सम्मानित महसूस करते हैं। स्टेट आफ सीज : 26/11 वेब सीरीज का दूसरा पार्ट स्टेट आफ सीज : टेंपल अटैक एक फिल्म होगी। फिल्म में गौतम रोडे अहम किरदार में नजर आएंगे। वह आर्मी अफसर मेजर समर का किरदार निभा रहे हैं। सरस्वतीचंद्र धारावाहिक और अक्सर 2 जैसी फिल्में कर चुके गौतम ने इस किरदार की तैयारियों को लेकर दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड डे से बातचीत में कहा कि मेजर समर का किरदार निभाना मेरे लिए गर्व की बात है। इस फिल्म में मेरा किरदार काफी इंटेंस है। मेरे लिए यह किरदार मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। आर्मी अफसर असली हीरो होते हैं। स्टेट आफ सीज : 26/11 सीरीज मुंबई में हुए आतंकी हमले पर आधारित थी, जिसमें एनएसजी कमांडो के आपरेशन को दिखाया गया था। वहीं, स्टेट आफ सीज : टेंपल अटैक फिल्म साल 2002 में अक्षरधाम मंदिर में हुए आंतकी हमले से प्रेरित बताई जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन केन घोष ने किया है। फिल्म नौ जुलाई को जी5 पर रिलीज होगी।



फिलहाल फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कार्तिक आर्यन ● इंस्टाग्राम

# बदला जाएगा कार्तिक आर्यन की फिल्म का नाम

**कभी लोगों की** भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, तो कभी किसी कानूनी आदेशानुसार, कभी-कभी तो कहानी के अनुसार भी फिल्मों के शीर्षक अक्सर बदले जाते हैं। हाल ही में निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्म सत्यनारायण की कथा की आधिकारिक घोषणा की थी। सत्यनारायण हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। ऐसे में फिल्म के शीर्षक से सत्यनारायण शब्द जुड़े होने के कारण फिल्म विवादों में आ गई। कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ-साथ भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी निर्माता साजिद नाडियाडवाला से फिल्म का शीर्षक बदलने की मांग की थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने शनिवार रात इस फिल्म का शीर्षक बदलने की घोषणा की। फिल्म के निर्देशक समीर विद्वांस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि फिल्म का शीर्षक क्रिएटिव प्रक्रियाओं के दौरान अपने आप निकल कर सामने आता है। लोगों की भावनाएं आहत न हो, इसलिए हमने अपनी हालिया घोषित फिल्म सत्यनारायण की कथा का शीर्षक बदलने का निर्णय लिया है। इस फिल्म के निर्माता और क्रिएटिव टीम इस निर्णय के पूरे समर्थन में हैं। हम इस फिल्म निर्माण के सफर के दौरान नए शीर्षक की घोषणा करेंगे।